के अन्तर्गत

अर्थशास्त्र विषय में

विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी.)

की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध

<u>शोध शीर्षक</u>

उदारीकरण के पश्चात् पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन - एक विश्लेषण

शोधार्थी

अतुल गोयल

एम.ए. अर्थशास्त्र

शोध निर्देशिका

डॉ0 रेनू माथुर

विभागाध्यक्ष - अर्थशास्त्र विभाग

बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी (उ.प्र.)

पूर्वजों को समर्पित..........

-: प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल गोयल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में विद्यावाचस्पति (पी०एच०डी०) की उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया।

शोधार्थी के शोध शीर्षक का विषय "उदारीकरण के पश्चात् पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन - एक विश्लेषण" है। इन्होंने दो वर्ष से अधिक समय तक मेरे निर्देशन में रहकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ।

शोध निर्देशिका

Renu Mathur

(डॉ० रेनू माथुर)

विभागाध्यक्ष

अर्थ शास्त्र विभाग

बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

प्रस्तावना

शोध का कार्य जितना रोचक है उतना ही मनोरंजक भी। शोध मानव के ज्ञान में वृद्धी करता है तथा "कारण–परिणाम" का दृष्टा तथा समालोचक बना देता है। कभी–कभी यह होता है कि सरकार का दावा कुछ और होता है पर आँकड़े सारी सत्यता को किताब की तरह खोलकर रख देते हैं और इसी कारण कहा गया कि समंकों से सत्य को छिपाना मुश्किल है। हम लोगों ने मिलकर एक सपना देखा है कि 2020 तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जायेगा। यह सपना नेताओं के दावे से पुष्ट भी है। पर कहते है कि वही सपने हकीकत में बदलते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाये। इस दृष्टि से आवश्यकता यह है कि हम अपनी नीतियों की समालोचना तटस्थ रहते हुये इस उद्देश्य से करें ताकि यह सपना पूरा हो सके और इसी कार्य के लिए प्रस्तुत शोध को यथा सम्भव "वस्तु परक" बनाने का प्रयत्न किया गया है।

अर्थनीति सम्बन्धित शोध यदि वैज्ञानिक पद्धति के स्थान पर कलात्मक पद्धति से किया जाये तो शोध कार्य और भी कठिन हो जाता है क्योंकि पहली बात कि वैज्ञानकि की बजाय कलात्मक दृष्टि में चरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है जो लगातार गतिशील ही बने रहते हैं जैसे भारत की राजनीति, जनसंख्या, संस्कृति आदि, और दूसरी बात वैज्ञानिक पद्धति से भले ही कुछ बातें सैद्धान्तिक रूप से सत्य लगें पर मानवता के नाते वह सत्य नहीं हाता और जो मानवीय दृष्टि से सही हो उसे ही क्रियान्वित करने से कल्याण की सम्भावना अधिक होती है। भविष्य के आर्थिक उच्चवचनों को

ध्यान में रखते हुये भले ही भारत आर्थिक माहशक्ति न बन सके परन्तु यदि औसत भारतीय का जीवन अच्छा है तो वह हमारे लिए अधिक गौरव की बात होगी। दौड़ में प्रथम व अन्तिम के बीच अर्थ का अन्तर होना तो चाहिये पर यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिये, जो पूँजीवाद में सम्भव नहीं हो पा रहा है। मेरे विचारों का शोध पर यदि थोड़ा बहुत प्रभाव पढ़ा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि शोधार्थी को तटस्थ ही होना चाहिये।

मैं अपनी पूज्य माता जी "श्रीमती कौशल्या देवी" को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने "सत्य के अनुकूल मेरी इस सोच का संवर्धन किया एवं बचपन से ही मुझे "सह असतित्ववाद" का पाठ पढ़ाया, उनका अमूल्य सहयोग शोध कार्य में मुझे प्राप्त हुआ तथा जो न लौटाये जा सकने वाले आर्शिवाद के समान है।

मैं अपनी शोध निर्देशिका पूज्यनीय डॉ. रेनू माथुर जी का भी चरण वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया एवं अमूल्य निर्देशन एवं समय दिया। शोध निर्देशिका जी के कारण ही मेरे लिए शोध कार्य के दौरान तटस्थ बने रहना सम्भव हो सका है तथा उन्होने ही मुझे इतना समर्थ बनाया कि मैं कारण, घटना, परिणाम को पहचान कर सही विश्लेषण कर सकूँ।

पारिवारिक परिचित आदरणीय डॉ. चन्द्रकांत अवस्थी जी का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने "मूर्ति रूप" शोध को सही चेहरा देने में मेरी मदद की। मेरे गुरू भाई – सुरेन्द्र, महेश, संतोष, सुनील इत्यादि के सुझावों ने विषय के सम्बन्ध में मेरा सहयोग किया तो घनिष्ठ मित्र 7 विवेक, अश्वनी, मुकेश, ए.के. सिंह, दीपक, आशुतोष के सुझाव व्यवहारिक थे।

जीवन संगिनी पूर्णिमा ने अन्य अन्या कार्यो में मेरा समय बचाकर तथा कभी–कभी कलम के माध्यम से मेरा सहयोग किया और इस सबसे अधिक बड़ा सहयोग भईया–भाभी, पिता, बहिन–जीजाजी का मानसिक रहा। कम्प्यूटर टाईपिस्ट श्री देवेन्द्र कुमार झा जी ने मेरे शोध को अन्य कार्यों पर प्राथमिकता देकर मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया।

अंत में सभी आत्मीय स्वजनों को यथा योग्य तथा यथा रीति धन्यवाद देते हुये मैं अपना शोध प्रस्तुत करता हूँ।

अतुल गोयल
106, चौक बाजार
बरूआसागर – झाँसी (उ.प्र.)
मो. : 09452214309

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ सं.

॥ भूमिका ॥

उत्तर प्रदेश भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, जीवन योग्य परिस्थितियाँ अनुकूल है तथा विविधतायें भी बहुत हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के राजनैतिक व आर्थिक घटनाओं में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामायण तथा महाभारत काल की इस क्षेत्र में घटित हुयी घटनायें बहुत रूचि से विश्व भर में पढ़ी व सुनी जाती हैं। परतंत्रता की त्रास्दी यदि सर्वाधिक इसी क्षेत्र ने झेली तो 1857 की क्रांति का उदय भी इसी भूमि से हुआ। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का महत्व और अधिक बढ़ गया एक समय कहा गया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की पहली शर्त है कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हो।

एक तरफ उत्तर प्रदेश का राजनैतिक व सांस्कृतिक महत्व था तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी, उत्तर प्रदेश को भारत के पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल किया जाता है तथा यहाँ के आर्थिक समंक भारत के औसत के अत्यधिक निकट हैं इस दृष्टि से "उदारीकरण के पश्चात् उत्तर प्रदेश के अध्ययन" ने वैश्वीकरण के भारत पर प्रभाव की एक झलक दिखला दी है। दूसरी समस्या यह थी कि उदारीकरण रूपी पूंजीवाद ने परम्परागत रूप से असमान दो क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य देखा जाता है कि एक ओर अल्प उत्पादन अल्प आय है तो दूसरी ओर अवसरों की प्रचुरता है इस तरह से "पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन" और अधिक सार्थक हो जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) व गाजियाबाद प्रदेश का गौरव हैं। जहाँ आधे से अधिक उद्योग धंधे सिमटे हुये हैं और यहाँ प्रदेश की

समस्त समृद्धी सिमटी हुयी है तो दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर व श्रावस्ती जिले उद्योग विहीन हैं केन्द्रीय उत्तर प्रदेश की स्थिति तुलनात्मक रूप से ठीक कही जा सकती है परन्तु बुन्देलखण्ड व पूर्वी क्षेत्र की स्थिति चिन्तनीय है जहां तुरंत अत्यधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। आशा है कि प्रस्तुत शोध के माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस विविधता को पर्याप्त प्रदर्शित किया जा सका है तथा तथ्य परक विश्लेषण से पिछड़े क्षेत्रों की समस्या समझने में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश
का मानचित्र
उत्तर
सहारनपुर
मुज़फ्फरनगर
बिजनौर
बागपत
मेरठ
मुरादाबाद
रामपुर
गाजियाबाद
पीलीभीत
गौतमबुद्ध नगर
बुलन्दशहर
बरेली
बदायूं
खीरी
शाहजहाँपुर
अलीगढ़
बहराइच
श्रावस्ती
बलरामपुर
मथुरा
हाथरस
एटा
फर्रुखाबाद
सीतापुर
हरदोई
सिद्धार्थ नगर
महराजगंज
कुशीनगर
फिरोजाबाद
मैनपुरी
आगरा
कन्नौज
गोण्डा
लखनऊ
बाराबंकी
बस्ती
संत कबीर नगर
गोरखपुर
देवरिया
इटावा
उन्नाव
फैजाबाद
औरैया
कानपुर देहात
कानपुर नगर
अम्बेडकर नगर
सुल्तानपुर
रायबरेली
जालौन
आजमगढ़
मऊ
बलिया
फतेहपुर
प्रताप गढ़
जौनपुर
हमीरपुर
गाजीपुर
झाँसी
बांदा
कौशाम्बी
महोबा
इलाहाबाद
चित्रकूट
वाराणसी
चन्दौली
मिर्जापुर
ललितपुर
सोनभद्र

पश्चिमी उ. प्र.
केन्द्रीय उ. प्र.
पूर्वी उ. प्र.
बुन्देल खण्ड
सहारनपुर
मुज़फ्फरनगर
बागपत
मेरठ
बिजनौर
गाजियाबाद
बुलन्दशहर
मुरादाबाद
रामपुर
बरेली
पीलीभीत
मथुरा
अलीगढ़
हाथरस
बदायूं
शाहजहांपुर
एटा
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
फर्रुखाबाद
इटावा
कन्नौज
औरैया
खीरी
सीतापुर
हरदोई
लखनऊ
बाराबंकी
उन्नाव
कानपुर देहात
रायबरेली
फतेहपुर
जालौन
हमीरपुर
महोबा
बांदा
चित्रकूट
ललितपुर
बहराइच
श्रावस्ती
बलरामपुर
गोण्डा
सिद्धार्थ नगर
महराजगंज
कुशीनगर
बस्ती
सन्त कबीर नगर
गोरखपुर
देवरिया
फैजाबाद
अम्बेदकर नगर
सुल्तानपुर
आजमगढ़
मऊ
बलिया
प्रताप गढ़
जौनपुर
गाजीपुर
कौशाम्बी
इलाहाबाद
वाराणसी
चन्दौली
मिर्जापुर
सोनभद्र

हमारे अध्ययन का क्षेत्र

पश्चिमी उ० प्र०

सहारनपुर
मुज़फ्फरनगर
बागपत
मेरठ
बिजनौर
गाजियाबाद
गौतमबुद्ध नगर
बुलन्दशहर
ज्योतिबा फूलेनगर
मुरादाबाद
रामपुर
मथुरा
अलीगढ़
हाथरस
बदायूं
बरेली
पीलीभीत
एटा
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
फर्रूखाबाद
शाहजहांपुर
इटावा
कन्नौज
औरैया

पूर्वी उ० प्र०

बहराइच
श्रावस्ती
बलरामपुर
सिद्धार्थ नगर
गोण्डा
महराजगंज
कुशीनगर
बस्ती
संत कबीर नगर
गोरखपुर
फैजाबाद
देवरिया
अम्बेदकर नगर
सुल्तानपुर
आजमगढ़
मऊ
बलिया
प्रताप गढ़
जौनपुर
गाजीपुर
कौशाम्बी
इलाहाबाद
सं.र.दा. नगर
वाराणसी
चन्दौली
मिर्जापुर
सोनभद्र
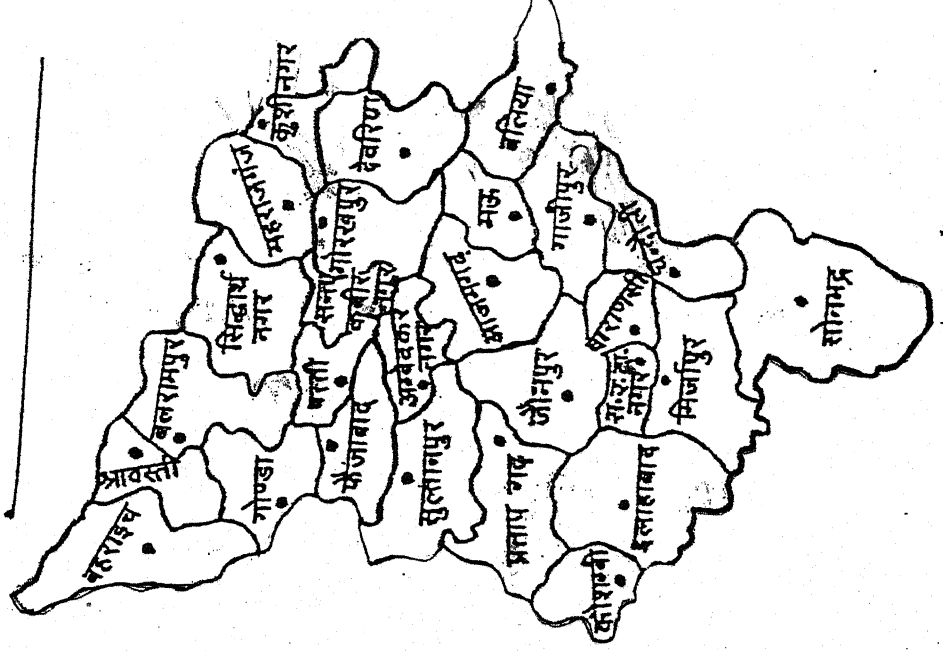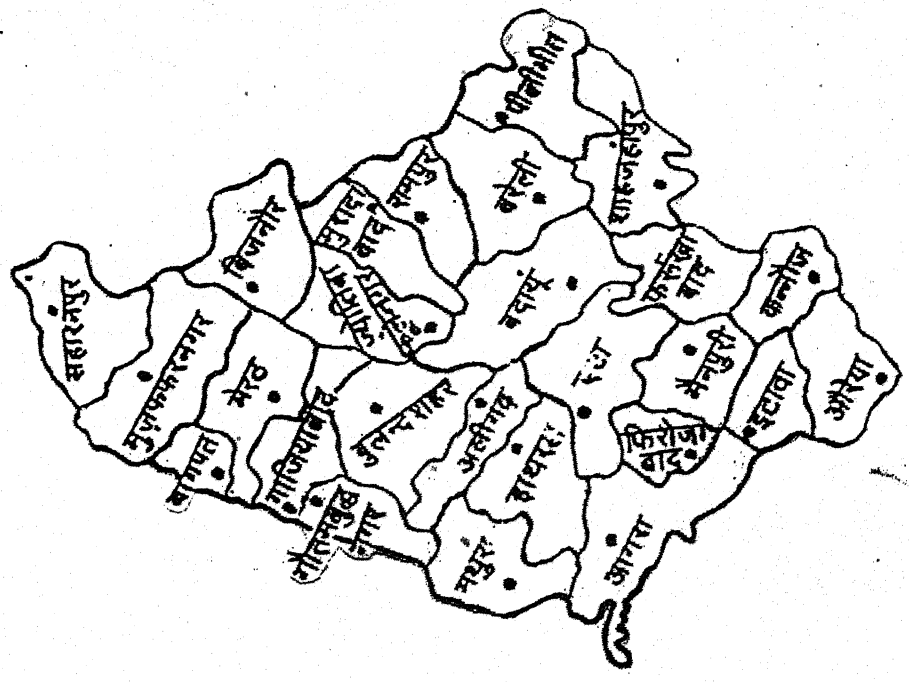
प्रथम अध्याय
उत्तर प्रदेश एक परिचय

क - भौगोलिक स्थिति

ख -पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश

ग - ऐतिहासिक महत्व

घ - अध्ययन का महत्व

ङ - अध्ययन का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश एक परिचय
  तथ्यात्मक विश्लेषण

क - भौगोलिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तरांचल गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी स्पर्श करती थीं, लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तरांचल में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य है इस प्रकार प्रदेश की सीमायें आठ राज्यों से लगती हैं। प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्यांचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तरांचल के रूप में प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र अलग हो चुका है, शेष उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से तीन भागों – भाभर व तराई, मैदानी तथा दक्षिण के पहाड़ व पठार में बाँटा जा सकता है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक पर्वतीय क्षेत्र से लगी हुई पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है, पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. तक चौड़ा है परन्तु पूर्व की ओर यह संकरा होता जाता है। मैदानी क्षेत्र गंगा, यमुना और सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है जिसका पश्चिमी अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है जबकि पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है। प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग आता है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप के कारण हुआ। पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा यमुना नदी से विभाजित है, समुद्र तल से ऊँचाई 300 मीटर तथा कुछ स्थानों पर 450 मीटर तक है। मिर्जापुर की सोनभद्र पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊँचीं है।

उत्तर प्रदेश की जलवायु गर्म है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ जिलों का तापमान 43 डिग्री सेन्टीग्रेट तक पहुंच जाता है। औसत रूप से प्रदेश का निम्नतम तापमान 12.5 से 17.5 तक रहता है। जून से सितम्बर माह तक प्रदेश में 83 प्रतिशत वर्षा होती है जबकि 17 प्रतिशत शरद ऋतु में वर्षा होती है।

गंगा तथा यमुना प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक गंगा की सहायक नदियां हैं। जबकी यमुना की सहायक नदियां प्रदेश में चम्बल, सिन्ध, बेलवर और केन हैं। इसके अलावा अन्य छोटी–छोटी नदियां कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन तथा धसान भी कहीं न कहीं गंगा या यमुना से मिल जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टी गहरी भूरे रंग की अम्लीय है जबकि पश्चिम के मैदानी भाग में सामान्य से अधिक उर्वरा है। पूर्व की ओर चलने पर पीलीभीत तक अम्लीय है पर थोड़ा आगे क्षारत्व आ जाता है। प्रदेश के केन्द्र में चिकनी तथा बलुई मिट्टी है जिसमें थोड़ा अम्ल भी है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की मिट्टी को स्थानीय भाषा में मोंट या बंजर कहा जाता है।

प्रदेश का 4.46 प्रतिशत (10751 वर्ग किमी.) क्षेत्र वनाच्छादित है यहाँ उष्ण प्रदेशीय–आद्रपर्णपाती शुष्क पर्णपाती तथा कटीले वन पाये जाते हैं। आद्र पर्णपाती वन भाभर व तराई क्षेत्र में पाये जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन मैदानी भागों, आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। कटीले वन अधि ाकांश दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं।

खनिज पदार्थों के लिए प्रदेश के सात जिले खासतौर से जाने जाते हैं – आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना तथा डेलेमाईट सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिलों में मिलता

है। ताँबा – ललितपुर में, ग्लास-सैंड इलाहाबाद, बाँदा और मऊ जनपदों में मिलता है। हाल ही में ललितपुर में यूरेनियम भण्डारों का पता चला है।

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश की जन संख्याँ 16,60,52,859 है। प्रदेश की जनसंख्या देश में सबसे अधिक तथा कुल जनसंख्या में इसका योगदान 16.17% हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान (15.7 करोड़) से अधिक तथा विश्व की जनसंख्या में ब्राजील (17 करोड़) के बाद छठें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी. राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद पांचवें नम्बर पर है। 1991-2001 में प्रदेश में 25.80% जनसंख्या वृद्धि हुयी। प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 689 जन प्रति वर्ग किलोमीटर, देश में पांचवा सबसे अधिक है। बनारस (1995) सबसे अधिक घनी आबादी व ललितपुर (194) सबसे कम घनी आबादी है।

ख - पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत 26 जिलों को रखा गया है यथा –

1. बिजनौर 2. मुरादाबाद 3. रामपुर 4. सहारनपुर
5. मुजफ्फर नगर 6. मेरठ 7. गाजियाबाद 9. बुलन्दशहर
10. अलीगढ़ 11. मथुरा 12. फिरोजाबाद 13. एटा
14. मैनपुरी 15. बदायूँ 16. बरेली 17. पीलीभीत
18. शाहजहाँपुर 19. फर्रूखाबाद 20. इटावा 21. जे.पी. नगर 22. बागपत 23. गौतमबुद्ध नगर 24. हाथरस 25. कन्नौज 26. औरैया।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में २७ जिलों को सम्मिलित किया जाता है –

1. प्रतापगढ़ 2. इलाहाबाद 3. बहराइच 4गोण्ड
5. फैजाबाद 6. अम्बेडकर नगर 7. सुल्तानपुर 8. सिद्धार्थनगर 9. महाराजगंज 10. बस्ती 11. गोरखपुर
12. कुशीनगर 13. देवरिया 14. मऊ 15. आजमगढ़
16. जौनपुर 17. बलिया 18. सन्त रविदास नगर
19. वारणसी 20. गाजीपुर 21. मिर्जापुर 22. सोनभद्र
23. कौशम्बी 24. त्रावस्ती 25. बलरामपुर
26. सन्त कबीर नगर 27. चन्दौली।

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र में 10 जिलों को रखा गया है –

1. खीरी 2. सीतापुर 3. हरदोई 4. उन्नाव
5. लखनऊ 6. रायबरेली 7. कानपुर देहात 8.कानपुर नगर
9. फतेहपुर 10. बाराबंकी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 7 जिले सम्मिलित हैं :-

1. जालौन 2. झाँसी 3. ललितपुर 4. हमीरपुर 5. महोबा 6. बांदा 7. चित्रकूट।

प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अच्छा समझा जाता है, यहां की मिट्टी में अम्लत्व पाया जाता है। दिल्ली की शोध फर्म इंडिकस एनालेटिक के 2005-2006 कृषि उत्पादन पर आधारित हालिया शोध (मार्च 2007) के अनुसार प्रदेश में प्रति एकड़ उत्पादकता के मामले में पश्चिमी क्षेत्र आगे है, मुजफ्फर नगर में सर्वाधिक 29000 प्रति एकड़ उत्पादकता मापी गई।[1] परम्परागत एवं कुटीर उद्योगों में सहारनपुर-बरेली का लकड़ी का फर्नीचर, मुरादाबाद का पीतल का काम, संभल का पशु सींग के शोपीस, अमरोहा के खिलौने, आगरा का जूता उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, फिरोजाबाद का कांच का काम, भदोही का कालीन उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। नई आर्थिक नीति से पश्चिमी क्षेत्र के गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) का औद्योगिक विकास पर्याप्त हुआ है। प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से अच्छी है, राजधानी क्षेत्र लखनऊ प्रशासनिक कार्य से जबकी कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर प्रदेश का बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़े हुये हैं। इंडिकस एनालेटिक के इसी शोध के अनुसार बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश बदहाली की ओर सफर कर रहे हैं। इन इलाकों की प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादक्ता 4500 से 6000 के बीच है जबकी कुछ जिलों का कुल उत्पादन मात्र 30 से 40000 बैठता है। यहां की ग्रामीण आबादी में प्रति व्यक्ति कृषि आय 1000 से 3000 रूपये के बीच है। संत रविदास नगर में प्रतिव्यक्ति उपज 1878 रूपये,जौनपुर-रायबरैली में 3000 रूपये जबकी सिद्धार्थ नगर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रतापगढ़, कौशम्बी, वाराणसी में 2000 रूपये है।[2]

ग - ऐतिहासिक महत्व

भारत में मानव सभ्यता का विकास सर्व प्रथम ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित उत्तर-पश्चिमी भू-भाग (आधुनिक पंजाब) में हुआ माना जाता है हालांकि पुराणों एवं महाकाव्यों के रूप में प्राचीन संस्कृत साहित्य से स्पष्ट होता है कि भारत वर्ष की संस्कृति चारों दिशाओं में फैली हुयी थी। उस समय भारत के कुछ प्रमुख घराने पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य पांचजन्य कहलाते थे। इसके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश का महत्व सप्त सिंधू की अपेक्षा बढ़ने लगा तथा प्रदेश का भारत के इतिहास से निकट सम्बन्ध हुआ। प्रदेश के मिर्जापुर-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खुदाइ के दौरान प्राचीन एवं नवीन पाषाण काल के औजार एवं मेरठ जिले के आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन वस्तुयें मिलीं हैं।[3] गंगा तथा सरस्वती के बीच का मैदान जो पूर्व में प्रयाग तक फैला हुआ था, मध्य प्रदेश के नाम से अभिहित हुआ, वर्तमान उत्तर प्रदेश की भी वही सीमायें हैं। हिन्दू कथा साहित्य में इस प्रदेश को पवित्र माना गया है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान व्यक्तियों एवं देवताओं का वर्णन मिलता है वे यहीं रहते थे।

छठीं शाताब्दी में भारत में 16 महाजनपद हुये तब 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आते थे, इनमें से अधिक विख्यात वत्स, कोशल और काशी हुये इसके अतिरिक्त अन्य महाजनपद कुरू (मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर), पाँचाल (बरेली, बदायूँ, फर्रूखाबाद), शूरसेन (मथुरा के पास), मल्ल (देवरिया) और

अंग (भागलपुर) हुये। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे - कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिरी का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।[4]

ईसा से 323 वर्ष पूर्व सिकन्दर की वापसी के साथ भारत मे महान क्रान्ति हुयी नंद वंश के पतन के पश्चात् भारत मे महान क्रांन्ति हुयी और मौर्य काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा गया। चन्द्रगुप्त मौर्य उनके पुत्र बिन्दुसार एवं पोते अशोक के शासन में उत्तर प्रदेश की चहुँमुखी उन्नति हुयी। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी हुयी है, स्वतंत्र भारत का वही राजकीय चिन्ह है। ईसा से 232 वर्ष पूर्व अशोक की मृत्यु के बाद मगध अपना गौरव खोने लगा, उसके पोते दशरथ और उसके बाद बृहद्रथ का क्षेत्र पर शासन रहा और उसके बाद पुश्यमित्र शुंग का। शुंग वंश के पश्चात् कण्व वंश का शासन हुआ।

ईसा से 60 वर्ष पूर्व शकों का तथा 40 ईसा पूर्व कुषाण राज्य का शासन रहा। कुषाण राज्य की स्थापना "कुजला कदफिसेस" या कदंफिसेस प्रथम ने की और इनका अंतिम शासक कनिष्क प्रथम हुआ जिसने 120 और 144 ईसवी के बीच राज्य किया।[5] ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्यप्रदेश (उत्तर प्रदेश) से समाप्त हो गया।

नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत में गूर्जर प्रतिहारों का शासन रहा 1018-19 में महमूद गजनवी के आक्रमण से वह पराजित हुये पर जेजाक भुक्ती (वर्तमान बुन्देलखण्ड) के चन्देल राजाओं ने मध्यप्रदेश (उत्तर प्रदेश) के बड़े भू-भाग को गजनवी के प्रभाव से बचाये रखा, उनका गढ़ कालिंजर अजेय रहा, चंदेल शासक धंगा और विद्याधर का नाम आदर से लिया जाता है।[6]

गुर्जर प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्य देश में एक बार फिर अराजकता का माहौल बना और तेरहवीं एवं चौदहवीं शताब्दी में मध्य देश का इतिहास शौर्य पूर्ण प्रतिरोध एवं बर्बरता पूर्ण दमन का रहा। इस काल में मध्य-देश पर दिल्ली की सत्ता का शासन रहा और उससे विद्रोह करके मध्य-देश में अनेक राज्यों का गठन हुआ। 1394 में पूर्वांचल के रूप में शरकी साम्राज्य बना जो 84 वर्षों तक शासन करता रहा उधर औरंगजेब के शासन से विद्रोह करके बुन्देल खण्ड में वीर क्षत्रसाल 50 वर्षों तक युद्ध करते रहे। 1732 से 1774 तक रूहेलखण्ड के रूप में रूहेलों का शासन रहा। 1732 में अवध के स्थानीय सूबेदार सादल खाँ ने विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया।

इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा था। अवध के तीसरे नबाव शुजाउद्दौला (1754 से 1775 तक) को बक्सर के युद्ध में पराजित करके अंग्रेजों ने कड़ा एवं इलाहाबाद पर अपना अधिकार कर लिया। सन् 1775, 1798 और 1801 मे नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किया तथा 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीता वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में संगौली की संधी द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून जिलों को गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, इस प्रकार जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में तबदील कर दिया गया।[7]

1857 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ विद्रोह, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से प्रारम्भ हुआ जो राष्ट्र की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम

बन गया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलवी अहमद उल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिंह, अजीम उल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्र भक्तों ने एकजुट संघर्ष किया।

1858 में दिल्ली डिवीजन अलग करके उत्तर पश्चिमी प्रदेश अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित हुयी, उसी वर्ष नवम्बर में कम्पनी शासन सीधे इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया के हाथ आ गया। 1877 में यह बृहत क्षेत्र उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध कहा जाने लगा। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, 1937 में इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रान्त हुआ। आजादी के ढाई वर्ष बाद, 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश हुआ तथा पास-पड़ौस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का महत्वपूर्ण राज्य बना।[8]

घ - अध्ययन का महत्व

भारतीय आर्थिक चिंतन-परम्परा में उदारीकरण तत्पश्चात् वैश्वीकरण के रूप में महत्वपूर्ण बदलाव आया। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही साथ देश की राजनीति तथा आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु भी रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक विषमतायें देखने को मिलती हैं यही क़ारण है कि इसे लघु भारत भी कहा जाता है, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों के परिणामों का अध्ययन एक छोटे क्षेत्र में करने की दृष्टि से यह प्रदेश उपयुक्त है।

सैकड़ों वर्षों की दासता के कारण भारत के ज्ञान, विज्ञान तथा दर्शन को संसार में पर्याप्त स्थान नहीं मिल सका, यद्यपि सच्चाइ यह है कि भारत का प्राचीन ज्ञान-विज्ञान न केवल अत्यधिक विकसित था बल्की यथार्थ के धरातल पर अत्यंत सफल भी था, भारतीय आर्थिक विचारों की प्रमुख़ विशेषता निम्नलिखित थीं[9] :-

1. अर्थ को अधिक महत्व नहीं दिया गया, इसे साध्य न मानकर साधन माना गया।

2. चिर आदर्श त्याग को माना गया, भोग को नहीं इस सम्बन्ध में ईशावास्य उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है -

ईशा वास्यमिदं सर्व यक्तिंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विहनम्।।

इस पद्य का अनुवाद स्व. सियारामशरण गुप्त ने निम्न प्रकार किया -

ईस का आवास यह सारा जगत,
जीवन यहां जो कुछ उसी से व्याप्त है,

अतएव करके त्याग उसके नाम से।

तू भोगता जा वह तुझे जो प्राप्त है,

धन की किसी के भी न कर तू वासना।

इस प्रकार "त्याग पूर्वक भोग" यह भारतीय परम्परा का विचार है।

3. भारतीय आर्थिक विचारों में वैज्ञानिक के स्थान पर अर्थनीति को ही अधिक महत्व दिया गया जो नैतिक तथा व्यवहारिक सीमा से बंधा नहीं है।

4. भारतीय विचारकों ने शोषण और आर्थिक विषमता का विरोध किया है। पुराणों में ऋषी दधीच, हरिश्चन्द्र, कर्ण, बलि की कथाएं है, इतिहास में अशोक तथा हर्ष की उदारता तथा दानवीरता का वर्णन है तो विचारकों जैसे – मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य, बृहस्पति तथा कौटिल्य ने भी शोषण का विरोध किया।

भारतीय आर्थिक विचार यत्र-तत्र विखरे हुये हैं। वैदिक साहित्य, 18 पुराण, स्मृति ग्रंथ और प्राचीन संस्कृत साहित्य में अर्थनीति के गूढ रहस्य मिलते हैं। मैगस्थनीज, हानच्वांग, फाहियान तथा इब्नबतूता इत्यादी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से सुदृढ़ भारतीय अर्थव्यवस्था का पता चलता है। भारतीय आर्थिक विचारों के संकलन की दिशा में श्री के.पी. जयसवाल ने The Ancient Indian Policy श्याम शास्त्री ने कौटिल्य अर्थशास्त्र, के.टी. शाह ने Ancient Foundation of Economics in India आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। के. वी. एम. आयंगर का Aspects of Ancient Indian Economic Thought तथा के. एम. सरन का Labour in Ancient India भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन तथा 1991 में भारत में अपनायी गई उदारवादी नीतियों में बहुत अधिक भिन्नता है, नई नीति "मैरिटोक्रेसी" है जैसा कि उदारवादी सहर्ष स्वीकार भी करते हैं, पर वास्तव में यह पूँजीवाद

का ही बदला हुआ रूप है। इस बात की पुष्टी फोबर्स की 2007 सूची से होती है। इस समय भारत में फोबर्स की सूची के अनुसार 36 अरबपति है। जिनके पास भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 21% है, इसका अर्थ है कि नई नीति में पूँजी ही पैसा कमाने का जरिया है। नई नीतियो को उपभोक्तावादी संस्कृति भी कहा जाता है स्वयं सरकार का उद्देश्य भी उपभोग को बढ़ावा देना है, बैंकों को कर्ज देने के लिए, विशेष तौर पर उपभोक्ता कर्ज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पूँजी संचय को और कम खर्च करने को अर्थ व्यवस्था के विकास में वाधक माना जा रहा है। नई व्यवस्था अधिक्तम उपभोग "दो और लो" के सिद्धान्त पर कार्य करती है अर्थात् ज्यादा कमाओं ज्यादा खर्च करो इसके विपरीत 1991 तक भारत में अपनाये गये आर्थिक विचार भिन्नता रखते हैं, विनिवेश प्रक्रिया में लाय गये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) का उद्देश्य लाभ का न होकर समानता का था। संशाधनों का प्रयोग केवल योग्य के लिए न होकर प्रत्येक के लिए था। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार तो और अधिक भिन्नता रखते हैं, अर्थ नीति में कहा गया है–"यो अर्थ–शुचि स शुचि" अर्थात् जिसका आर्थिक जीवन शुद्ध है वही शुद्ध है।[10] पर वर्तमान नीति विपरीत मत देती है आज का युग गलाकाट व्यापार प्रतिस्पर्द्धा का है। आचार्य बृहस्पत के अर्थशास्त्र में वर्णित आर्थिक विचार निम्न प्रकार थे -

प्रथम अध्याय - ऋण नहीं करना चाहिये।[11]

द्वितीय अध्याय - राजा को कृषि, गोकुल और वाणिज्य की रक्षा करनी चाहिए।[12]

तृतीय अध्याय - ग्रामों की रक्षा करनी चाहिये।[13]

पांचवा अध्याय - नीति के चार उपाये साम, दाम, दण्ड तथा भेद हैं।[14]

शुक्राचार्य को भारतीय अर्थशास्त्र का पितामह कहा जा सकता है "श्री वेंकटेश्वर प्रेस" द्वारा प्रकाशित "शुक्रनीति" का पण्डित मिहिरचन्द्र द्वारा भाष्य किया गया है। शुक्राचार्य ने मजदूरी के संदर्भ में – मजदूरी दर, बोनस, पेंशन, क्षतिपूर्ति, कार्य के घण्टे, छुट्टियां आदि के नियम निर्धारित किये हैं जबकि उनका युग ईसा से 600 से 700 वर्ष पूर्व माना जाता है।[15]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321 ई.पू.) का दृष्टिकोंण व्यवहारिक है, वह नैतिकता और भावुकता को राज्य और अर्थ के संचालन से अलग रखते हैं, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा योजनाबद्ध उत्पादन (आधुनिक भाषा में नियोजन कहा जाता है) का पक्ष लेते हैं।

मध्य युगीन भारतीय आर्थिक विचारों के अन्तर्गत "सोमदेव सूरि" ने 11 वीं शताब्दी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "नीतिवाक्यमृत" की रचना की जबकि "अकबर" ने अपने मंत्री "टोडर मल" के सहयोग से जो आर्थिक सुधार राज्य में लागू किये उनका वृहद वर्णन "अबुलफजल" द्वारा लिखित "आईने अकबरी" में मिलता है।

भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के विचार वर्तमान उदारवादी नीतियों से भिन्न है, उस समय- राजा राममोहन राय, शशिपद बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, डॉ. फ्रॉसिस्को लुई गोम्स, महादेव गोविन्द रानाडे, रमेश चन्द्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉ. मोक्ष गुन्दम विश्वेश्वरैया, मेजर बामन दास बसु, इत्यादी ने अर्थ नीति से सम्बन्धित अपने विचार प्रकट किये। दादाभाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Poverty and unBritish rule in India में "प्रवाह सिद्धान्त" के द्वारा भारत से ब्रिटेन जाने वाली अपार धन राशि का जिक्र किया हालांकि रानाडे ने उसे "होम चार्जेज" बताया उनके अनुसार होम चार्जेज उत्पादक

शुक्राचार्य को भारतीय अर्थशास्त्र का पितामह कहा जा सकता है "श्री वेंकटेश्वर प्रेस" द्वारा प्रकाशित "शुक्रनीति" का पण्डित मिहिरचन्द्र द्वारा भाष्य किया गया है। शुक्राचार्य ने मजदूरी के संदर्भ में - मजदूरी दर, बोनस, पेंशन, क्षतिपूर्ति, कार्य के घण्टे, छुट्टियां आदि के नियम निर्धारित किये हैं जबकि उनका युग ईसा से 600 से 700 वर्ष पूर्व माना जाता है।[15]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321 ई.पू.) का दृष्टिकोंण व्यवहारिक है, वह नैतिकता और भावुकता को राज्य और अर्थ के संचालन से अलग रखते हैं, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा योजनाबद्ध उत्पादन (आधुनिक भाषा में नियोजन कहा जाता है) का पक्ष लेते हैं।

मध्य युगीन भारतीय आर्थिक विचारों के अन्तर्गत "सोमदेव सूरि" ने 11 वीं शताब्दी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "नीतिवाक्यमृत" की रचना की जबकि "अकबर" ने अपने मंत्री "टोडर मल" के सहयोग से जो आर्थिक सुधार राज्य में लागू किये उनका वृहद वर्णन "अबुलफजल" द्वारा लिखित "आईने अकबरी" में मिलता है।

भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के विचार वर्तमान उदारवादी नीतियों से भिन्न है, उस समय- राजा राममोहन राय, शशिपद बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, डॉ. फ्रॅांसिस्को लुई गोम्स, महादेव गोविन्द रानाडे, रमेश चन्द्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॅा. मोक्ष गुन्दम विश्वेश्वरैया, मेजर बामन दास बसु, इत्यादी ने अर्थ नीति से सम्बन्धित अपने विचार प्रकट किये। दादाभाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Poverty and unBritish rule in India में "प्रवाह सिद्धान्त" के द्वारा भारत से ब्रिटेन जाने वाली अपार धन राशि का जिक्र किया हालांकि रानाडे ने उसे "होम चार्जेज" बताया उनके अनुसार होम चार्जेज उत्पादक

कार्यो का मूल्य है जिससे निर्धनता नहीं बढ़ती।

मोहनदास करमचन्द गांधी के साथ सर्वोदय का अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया जिसका शाब्दिक अर्थ है – सभी का लाभ। आचार्य विनोबा भावे ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का झुकाव साम्यवाद की ओर था तथा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, पूँजीवाद या उससे मिलते–जुलते किसी भी अर्थनीति से परहेज किया गया, यही स्थिति भारत में 1991 तक रही।

जून 1991 में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश तथा औद्योगिक उदारवाद और उसके पश्चात् वैश्वीकरण के रूप में बड़ा नीतिगत परिवर्तन किया गया। आज नई नीतियों को अपनाये हुये डेढ़ दशक से अधिक बीत चुका है, इतना समय नीति के मुल्यांकन की दृष्टी से पर्याप्त है। नई नीतियों ने उत्तर प्रदेश के विकास में क्या भूमिका निभाई है तथा इसने आर्थिक रूप से भिन्न–भिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डाला है यही जानने की दृष्टी से यह शोध महत्वपूर्ण है।

ड. - अध्ययन का उद्देश्य

अर्थशास्त्र विषयक नये साहित्य में विश्व के देशों को अल्पविकसित तथा विकसित देशों में वर्गीकृत किया गया है। अल्पविकसित देश शब्द के प्रयोग के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेषज्ञों के दल का कहना है – "इस शब्द का प्रयोग उन देशों के अर्थ में किया गया है जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है। इस अर्थ में निर्धन देश उपयुक्त पर्यायवाची है।"[16] भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र है। उदारीकरण पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषतायें देखी गयीं–

1 - प्रति व्यक्ति वास्तविक आय निम्न थी।

2 - भारत का व्यवसायिक ढांचा प्राथमिक उत्पादनशील था, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि में लगा था।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाब बढ़ रहा था।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था में चिरकाल से चली आ रही बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगारी विद्यमान थी।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी पूँजी का आभाव था।

6. रिजर्व बैंक के जुलाई 1991 से जून 1992 तक ग्राम तथा शहरी परिवारों की सम्पत्ती सर्वेक्षण से परिसम्पत्ती वितरण में भारी असमानता देखी गयी, अर्थात् धनी व गरीब के मध्य खाई चौड़ी थी।[17]

7. कम विकसित मानवीय पूँजी। भारत में मानव संशाधन के विकास के लिए संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं थी।

8. उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की थी।

9. औसत भारतीय का जीवन स्तर निम्न श्रेणी का था।[18]

10. भारत के जनाकिकीय लक्षण अल्प विकसित राष्ट्र के थे अर्थात् ऊँची शिशु मृत्युदर तथा कम जीवन प्रत्याशा, अधिक जनसंख्या घनत्व आदि।

11. उपभोग के समाजार्थिक सूचक भी अल्पविकसित राष्ट्र के थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समान प्रवर्ती उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलती थी। हालाँकी भारत के कुछ धनी राज्यों के आर्थिक सूचक अच्छी स्थिति में थे पर उत्तर प्रदेश के आँकड़े औसत से मिलते जुलते थे तथा कुछ मामलों में यह प्रदेश पिछड़े राज्यों में सम्मिलित था। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 1990-91 में देश का 120 वां राज्य था जबकी 2000-01 में यहाँ मात्र 8% की प्रतिव्यक्ति आय में बृद्धि हुयी, 1990-91 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय साधन लागत पर तथा 1993-94 की कीमतों पर 7,321 रूपये, उत्तर प्रदेश (5,342) से 1,979 रूपये अधिक थी तथा एक दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से 4,484 रूपये अधिक हो गयी।[19] 1990-91 में 80-81 की कीमतों पर भारत के शुद्ध घरेलू उत्पादन 1,90,218 करोड़ रूपये में उत्तर प्रदेश का योगदान महज 11.97% था।[20] उदारीकरण पूर्व की स्थिती के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्न कारणों से अल्प विकसित राज्य कहा जा सकता था–

1- प्रति व्यक्ति आय बहुत कम, प्रचलित भाव पर 1990-91 में महज 3553 रूपये थी।

2 - प्राथमिक उत्पादनशील ढाँचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्य आय का 43.8% कृषि से आता था।

3. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का दबाब था, यह देश में सर्वाधिक थी।

4. प्रदेश में बेरोजगारी थी, 1991 में कुल जनसंख्या में कर्मकारों का प्रतिशत मात्र 32.27था ।[21]

5. पूँजी का आभाव तथा परिसम्पत्ती का दोषपूर्ण वितरण अर्थात् धनी व गरीब के बीच खाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी देखी जाती थी।

6. साक्षरता प्रतिशत मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 1991 में नीचे से तीसरा था तथा मानवीय संसाधनों के विकास के लिए संस्थाओं का आभाव था।

भारत में 1985 से 1990 तक तथा 21 जून 1991 के बाद से जारी किये आर्थिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य, आर्थिक विकास को प्राप्त करना था। जून 1991 के बाद की नीतियों को उदारीकरण का नाम दिया गया तथा विश्व व्यापार संगठन के उदय के बाद से 1994 में वैश्वीकरण का दौर भी आया। आर्थिक विकास शब्द एक व्यापक धारणा है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में परिभाषित किया जबकी बेन्जामिन हिगिन्स, हार्वे, लेविन्सटीन, आर्थर लुईस, जैकब, वाइनर, विलियमसन आदि ने आर्थिक विकास को प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धी से सम्बन्धित किया ।[22]

आर्थिक विकास की कुछ अन्य प्रमुख परिभाषायें निम्न प्रकार हैं -

1- आर्थिक विकास उस प्रक्रिया का बोध कराती है जिसमें किसी देश के नागरिक उपलब्ध साधनों का उपयोग प्रतिव्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए करते हैं – विलियमसन एवं बट्रिक ।[23]

2. आर्थिक वृद्धी से अभिप्राय एक देश के समाज में होने वाले उस परिवर्तन से लगाया जाता है जो अल्पविकसित स्तर से उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है – प्रो. डी. ब्राईट सिंह ।[24]

3. आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बताता है जिसमें बढ़ती हुई पूँजी की आवश्यकता एक

निश्चित सीमा तक प्रतिव्यक्ति उत्पादन में वृद्धी लाती है, वहाँ से पूँजी की आवश्यकता कम होती जाती है ।– कोलिन क्लार्क[25]

अधिकांश अर्थशास्त्री प्रतिव्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रतिव्यक्ति उत्पादन में वृद्धी को आर्थिक विकास मानते हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के रूप में इसे सही माना जा सकता है क्योंकि भौतिकतावादी इस युग में धन की उपलब्धी को ही आर्थिक कल्याण का पर्याय समझा जाता है परन्तु बात यदि राजकीय नीति की हो तब अर्थनीति में नीती शास्त्र का भी समावेस हो जाता है और अध्ययन का दायरा और अधिक विस्तृत हो जाता है।

पत्रकार भरत डोंगरे के अनुसार ''विकास की संक्रीण व भ्रामक सोच को नकार दिया जाना चाहिये तथा सार्थक विकास को नये सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिये जो मनुष्य के मूल कल्याणकारी उद्‌देश्यों तथा भावी पीढ़ी के लिए भी अनुकूल हो।''[26] अमेरिका के वर्जीनिया टेक में स्कूल में एक छात्र द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में अरिंदम चौधरी के अनुसार ''पूँजीवादी भौतिक विकास का खोखलापन यही है जो लोगों के क्षोभ के रूप में सामने आता है तथा यह बताता है कि व्यक्ति खुश नहीं है।''[27]

इसके अलावा भारत की उदार आर्थिक नीति के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन के और अधिक विस्तृत होने की भी परेशानी बतायी जाती है। उदारीकरण के संदर्भ में आज डेढ़ दशक बीत चुका है, छोटे क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई नीतियों ने किस प्रकार प्रभावित किया है यह जानना इस शोध का उद्‌देश्य है।

पाद टिप्पणी

1- 2. दैनिक जागरण - 17 अप्रैल 2007
3. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2004, पेज 11 (सू एवं ज. विभाग)
4. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1990-91, 91-92 पेज 31 (सू. एवं ज. विभाग)
5. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2004, पेज 13 (सू एवं ज. विभाग)
6. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2004, पेज 12 (सू. एवं ज. विभाग)
7. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1990-91, 91-92, पेज 13 (सू एवं ज. विभाग)
8. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2004, पेज 15 (सू. एवं ज. विभाग)
9. आर्थिक चिन्तन का इतिहास - डॉ. चतुर्वेदी एवं डॉ. चतुर्वेदी पेज 335
10. आर्थिक चिन्तन का इतिहास - डॉ. चतुर्वेदी एवं डॉ. चतुर्वेदी (साहित्य भवन) पेज 337
11. बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र 1/24,
12.. बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र 1/24
13 - 14 .बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र 1/38
15. आर्थिक चिन्तन का इतिहास - डॉ. चतुर्वेदी एवं डॉ. चतुर्वेदी (साहित्य भवन) पेज 337
16. United nations, measures for the economic development of under developed countries (1951) Pg. - 2
17 - 18 . रूद्र दत्त एवं के०पी० सुन्दरम् - भारतीय अर्थव्यवस्था, पेज - 6
19. Ministary of finance, Indian public finance statistic (2001 - 2002), Lok Sabha (2002) unstarred question - 2556.
20. भारतीय रिजर्व बैंक - Hand Book of Statistic on Indian Economy - 1999
21. उत्तर प्रदेश सांख्यकी 1990-91, 91-92 (सू. एवं ज. विभाग, उ.प्र.)
22. उपकार - अर्थ शास्त्र डॉ. अनुपम अग्रवाल, पेज - 200
23, 24 & 25 . एम.एल. झिंगन - आर्थिक विकास एवं नियोजन
26. दैनिक जागरण 23 अप्रैल 2007
27. India Today & tomarrow 29 April 2007 - Editorial

उत्तर प्रदेश एक परिचय
- तथ्यात्मक विश्लेषण

स्रोत : "उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक", प्रकाशक – अर्थ एवं संख्या प्रभाग वर्ष 2002

जनसंख्या

16,60,53,000
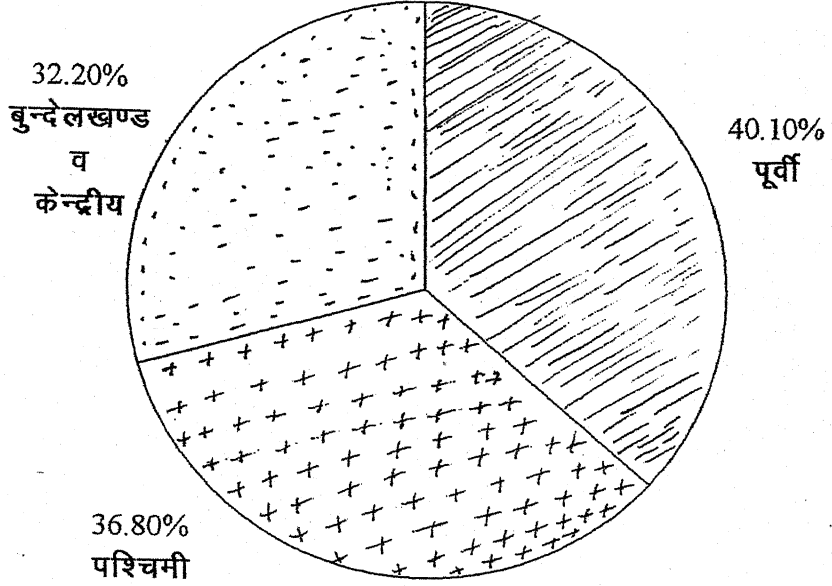
भौगोलिक क्षेत्रफल

240289 वर्ग किलोमीटर
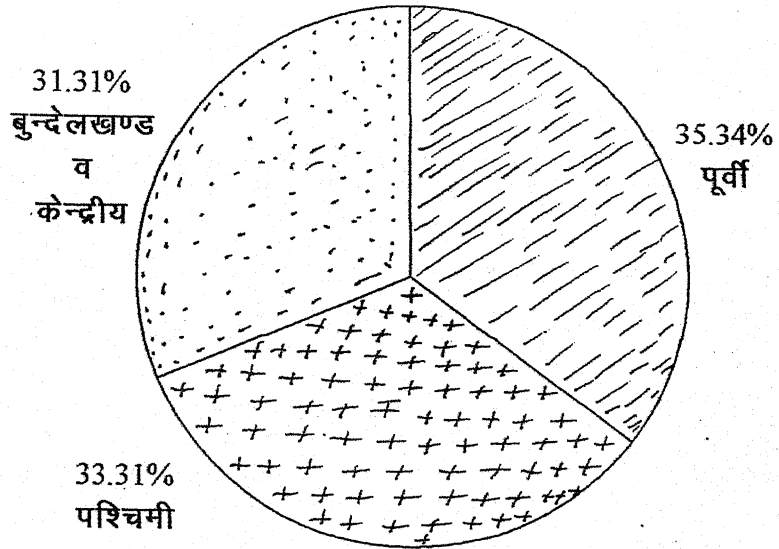
	जनसंख्या		भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किमी.	
	1991	**2001**	**1991**	**2001**
पश्चिमी	48,358,000	61,037,000	79831	80043
पूर्वी	53,044,000	66,616,000	86352	84934

जनसंख्या में दशकीय वृद्धी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26.22% तथा पूर्वी में 25.58 रही। जनसंख्या घनत्वं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 765 एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 776 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 689 है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी सम्भाग का वाराणसी जिला सर्वाधिक घनी आबादी का (1995) तथा सबसे कम घनी आबादी का बुन्देलखण्ड का ललितपुर जनपद (194) है।

उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात

	1991	**2001**
पश्चिमी	26.3	28.3
पूर्वी	11.6	11.8
उत्तर प्रदेश	19.7	20.8

1991 की जन गणना के अनुसार पश्चिमी सम्भाग की ग्राम्य जनसंख्या का 30.28%, 1000 से 1999 जनसंख्या के गाँव में रहती है जबकी 8.95% ग्राम आबादी, 200 से भी कम आबादी वाले गाँव में रहती है। इस क्षेत्र में 2.46% गाँव 5000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं, जहां 13.13% जन संख्या रहती है यही लगभग स्थिति पूर्वी सम्भाग की है।

1 - विभिन्न जनसंख्या वर्गानुसार ग्रामों की संख्या

जन संख्या का कुल ग्रामों की संख्या/ जनसंख्या से प्रतिशत

(1991 के अनुसार)

	200 से कम जनसंख्या वाले		200-499 जनसंख्या वाले	
	संख्या	जनसंख्या	संख्या	जनसंख्या
पश्चिमी	8.95%	0.58%	17.67%	4.87%
पूर्वी	14.79%	1.61%	25.17%	9.36%
उत्तर प्रदेश	11.07%	1.69%	23.45%	8.20%

	500 से 999 जनसंख्या वाले		1000-1999 जनसंख्या वाले	
	संख्या	जनसंख्या	संख्या	जनसंख्या
पश्चिमी	28.23%	15.83%	28.13%	30.28%
पूर्वी	28.26%	21.72%	21.49%	32.08%
उत्तर प्रदेश	26.22%	19.18%	21.74%	30.89%

	2000-4999 जनसंख्या वाले		5000 या अधिक जनसंख्या वाले	
	संख्या	जनसंख्या	संख्या	जनसंख्या
पश्चिमी	15.81%	35.31%	2.46%	13.13%
पूर्वी	9.42%	28.67%	0.87%	6.56%
उत्तर प्रदेश	10.59%	30.88%	1.30%	9.21%

शहरीकरण की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि 2000 जनसंख्या तक के ग्रामों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या

का प्रतिशत पूर्वी तथा उ.प्र. की तुलना में कम है इसके विपरीत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पश्चिमी उ.प्र. की आबादी का प्रतिशत अधिक है।

2- विभिन्न जनसंख्या वर्गानुसार ग्रामों की संख्या/ जन संख्या का कुल नगरों की संख्या/ जनसंख्या से प्रतिशत (1991 के अनुसार)

	20000 से कम जनसंख्या वाले		20000-49999जनसंख्या वाले	
	संख्या	जनसंख्या	संख्या	जनसंख्या
पश्चिमी	65	18.5	20.9	15.9
पूर्वी	73.6	22.3	13.8	10.3
उत्तर प्रदेश	69.1	18.7	18.5	14.1

	50000 से 99,999 जनसंख्या		1 लाख या अधिक जनसंख्या	
	संख्या	जनसंख्या	संख्या	जनसंख्या
पश्चिमी	6.6	10.6	7.5	55.0
पूर्वी	7.8	16.0	4.8	51.4
उत्तर प्रदेश	6.6	11.7	5.8	55.5

पश्चिमी सम्भाग में पूर्वी की अपेक्षा 20000 से 49999 जनसंख्या वर्ग तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग के नगरों की संख्या अधिक है तथा उत्तर प्रदेश के औसत के लगभग बराबर है जबकी 20,000 से कम आबादी तथा 50000 से 99999 वर्ग के नगरों की संख्या तथा जनसंख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक है। (पश्चिमी की तुलना में) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वर्ग की संख्या

तथा जनसंख्या भी औसत के लगभग है।

बड़े जनसंख्या वाले नगर सर्वाधिक केन्द्रीय सम्भाग में है जहां 72.8% नगरीय आबादी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में है। बुन्देलखण में बड़े नगरों का आभाव है, चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा जालौन जनपद में एक भी नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या का नहीं हैं।

आर्थिक विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी समंक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए निम्न प्रकार है –

3 - प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

	1990 - 1991	**2000 - 2001**
पश्चिमी	0.08	0.10
पूर्वी	0.08	0.13
उत्तर प्रदेश	0.12	0.10

उत्तर प्रदेश में कुल 166 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनका वितरण प्रत्येक क्षेत्र में लगभग समान है।

4 - प्रति लाख जनसंख्या पर बहुधंधी तकनीक संस्थानों की संख्या

	1990 - 1991	**2000 - 2001**
पश्चिमी	0.06	0.04
पूर्वी	0.04	0.05
उत्तर प्रदेश	0.6	0.05

5 - प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यालयों की संख्या

	जू. बेसिक		सी. बेसिक		हायर सेकेन्डरी	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	52	54	10	12	04	06
पूर्वी	40	49	10	11	04	05
उत्तर प्रदेश	57	54	11	12	04	05

प्रति लाख जन संख्या पर जूनियर तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक (औसत से डेढ़ गुनी) है जबकि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से अन्य मामलों में पिछड़ा हुआ है। रोजी - रोजगार में कमी तथा कृषि बदहाली के कारण इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम है।

6 - प्रति अध्यापक छात्रों की संख्या

	जू. बेसिक		सी. बेसिक		हायर सेकेन्डरी	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	52	43	32	31	52	41
पूर्वी	50	45	36	31	49	46
उत्तर प्रदेश	52	44	33	30	49	43

7 - उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत

	पुरूष		स्त्री		कुल	
	1991	**20 01**	**1991**	**20 01**	**1991**	**20 01**
पश्चिमी	54.77	70.28	26.5	44.64	42.02	58.44
पूर्वी	54.77	70.03	20.92	39.54	38.55	55.22
उत्तर प्रदेश	55.73	70.23	25.31	42.98	41.60	57.36

उत्तर प्रदेश के विभिन्न सम्भागों में स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों की संख्या निम्न प्रकार है –

8 - प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

	1990 - 1991	**2000 - 2001**
पश्चिमी	2.63	2.13
पूर्वी	1.92	1.85
उत्तर प्रदेश	2.35	2.05

9 - प्रति लाख जनसंख्या पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की संख्या

	1990 - 1991	**2000 - 2001**
पश्चिमी	14.39	10.58
पूर्वी	16.16	12.29
उत्तर प्रदेश	16.03	11.72

10 - प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक

	चिकित्सालय तथा औषधालयों की संख्या		शैयाओं की संख्या (प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र सहित)	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	2.92	2.87	41.56	38.38
पूर्वी	2.76	2.76	45.15	38.95
उत्तर प्रदेश	3.35	2.88	50.28	40.17

11- प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक

	चिकित्सालय तथा औषधालयों की संख्या		शैयाओं की संख्या	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	1.67	1.65	6.40	4.96
पूर्वी	2.23	3.95	6.87	10.25
उत्तर प्रदेश	2.30	2.13	7.75	5.81

आनुपातिक रूप में 91 की तुलना में 2001 में प्रदेश में चिकित्सालयों की संख्या में कमी हुयी है इसका अर्थ है कि जनसंख्या में वृद्धी की तुलना में चिकित्सा संसाधनों में बृद्धी नहीं की जा सकी है परन्तु इसके वावजूद प्रदेश में जीवन प्रत्याशा में बृद्धी एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी देखी गई जिसका अर्थ है प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं नर्सों की संख्या में वृद्धी से व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धी हुयी।

विकास सम्बन्धी अन्य संकेतक उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार हैं :-

12 - प्रति हजार मजरों पर पेयजल सुविधा युक्त मजरों की संख्या

	1990 - 1991	2000 - 2001
पश्चिमी	925	999
पूर्वी	882	999
उत्तर प्रदेश	870	999

13 - लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई

	प्रति लाख जनसंख्या पर		प्रति हजार वर्ग किमी. पर	
	1990 - 91	2000 - 01	1990 - 91	2000 - 01
पश्चिमी	47.16	59.72	276.00	456.64
पूर्वी	43.90	56.55	259.98	436.25
उत्तर प्रदेश	53.04	60.30	243.78	415.63

14 - कुल पक्की सड़कों की लम्बाई

	प्रति लाख जनसंख्या पर		प्रति हजार वर्ग किमी. पर	
	1990 - 91	2000 - 01	1990 - 91	2000 - 01
पश्चिमी	63.69	79.26	385.83	586.25
पूर्वी	56.70	70.06	348.27	523.18
उत्तर प्रदेश	61.12	79.17	334.88	528.14

15 - प्रति लाख जनसंख्या पर

	तार घरों की संख्या		डाकघरों की संख्या	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	4.2	0.4	11.5	9.5
पूर्वी	3.6	0.7	13.1	18.4
उत्तर प्रदेश	4.4	0.6	13.9	10.6

16 - प्रतिं लाख जनसंख्या पर

	दूरभाष केन्द्रों की संख्या		पी.सी.ओ. की संख्या	
	1990 - 91	**2000 - 01**	**1990 - 91**	**2000 - 01**
पश्चिमी	299	1757	5.14	58.65
पूर्वी	125	952	3.02	45.18
उत्तर प्रदेश	239	1402	4.25	52.58

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है प्रशासनिक दृष्टी से बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने में पूर्वी, पश्चिमी, बुन्देलखण्ड तथा केन्द्रीय क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं। तथापि पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिव्यक्ति आय तथा गरीबी में असमानता दृष्टिगत होती है।

द्वितीय अध्याय
शोध तकनीकि

क - निर्देशन

ख - निदर्शन

ग - अध्ययन का समय

घ - समंक संकलन

ङ - विभिन्न चरों का विशिष्टीकरण

क - निर्देशन

प्रस्तुत शोध "उदारीकरण का प्रभाव", अर्थशास्त्र से सम्बन्धित विषय है। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को विज्ञान, कला अथवा दोनों मानने के सम्बन्ध में मतभेद है। अर्थशास्त्र के स्वभाव को लेकर दो विरोधी दृष्टीकोंण प्राप्त होते हैं, इग्लैण्ड का प्रतिष्ठित सम्प्रदाय इसे पूर्ण रूपेण वास्तविक विज्ञान मानता है जे.बी.से., सीनियर तथा आधुनिक अर्थशास्त्री विशेषकर प्रो. राबिन्सन आदि इसे वास्तविक विज्ञान मानते हैं[1]। जबकी जर्मनी का ऐतिहासिक सम्प्रदाय अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान तथा नीतिशास्त्र से सम्बन्धित मानता है। प्रो. फ्रैडमैन अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान दोनों से मानते हैं, उनके अनुसार "अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान।[2]

शोध तकनीकि का चुनाव विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है, शोध कार्य के लिए प्रायः दो विधियां हैं :- (i) प्रयोगात्मक विधि (ii) सांख्यिकीय विधि। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग विशेषतः विशुद्ध विज्ञान में ही सटीक परिणाम दे सकता है परन्तु अर्थनीति से सम्बन्धित प्रस्तुत शोध में जबकि एक कारक को दूसरे कारक से अलग नहीं किया जा सकता, सांख्यिकीय विधि अधिक उपयुक्त है। उदाहरण स्वरूप भारत में उदारीकरण के साथ ही साथ विनिवेश तथा वैश्वीकरण को भी लागू किया गया, इन नीतियों ने वृहद रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया है। हावार्ड एल. बेल्सले के शब्दों में "सामाजिक विज्ञान सम्बन्धित शोध में, जो मुख्यतः मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं विषयों को स्थिर नहीं रखा जा सकता अतः शुद्ध प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल कुछ कारकों को स्थिर रखकर अन्य कारकों को दशाओ के अनुसार परिवर्तन करके प्रयोग करना सम्भव नहीं

होता है, जिससे वांछित सूक्ष्म उत्तर प्राप्त किया जा सके। ऐसी समस्याओं के अनुसंधान में सांख्यिकीय विधि ही उपयोगी एवं आवश्यक है।"[3]

आर्थिक दशा में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के रहन-सहन तथा सामाजिक जीवन पर भी कई तरह से प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि नई नीतियों के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन में भी प्रभाव देखा गया। उपभोक्तावादी तथा भौतिकतावादी नये दृष्टिकोंण के कई सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव हैं इस तरह से प्रस्तुत शोध को एक सीमा तक सामाजिक शोध भी कहा जा सकता है। मानव की जिज्ञासू प्रवृत्ति उसे चारों ओर विद्यमान सभी प्रकार की घटनाओं के कारण एवं परिणाम जानने को प्रेरित करती है, अग्रवाल एवं पाण्डेय के अनुसार "मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक घटनायें, इनसे सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा ज्ञान का सत्यापन करना ही शोध है।[4]

प्रस्तुत शोध में उदारीकरण की घटना से सम्बन्धित मूल-भूत तत्वों का विश्लेषण करके उसकी प्रवत्ति समझने का प्रयत्न किया जायेगा और उसके बाद उन नियमों का निर्माण किया जाता है जिसकी सहायता से कारण-परिणाम सम्बन्ध को मानव हित के अनुकूल परिवर्तित किया जा सके, शोध यदि सामाजिक प्रवर्ति का हो तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ओगार्ड्स के शब्दों में "एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज सामाजिक शोध है।"[5] मोजर ने नीवन ज्ञान के लिए व्यापक अनुसंधान को शोध कहाहै।[6] फिशर के अनुसार "समस्या को हल करना, परिकल्पना की परिक्षा करना अथवा नयी घटना - नये सम्बन्धों को खोजना शोध है।"[7]

शोध की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शोध का कार्य केवल नीवन सिद्धान्त का निर्माण नहीं है, वरन् पुराने तथ्यों की प्रमाणिकता जानना भी है। इस प्रकार शोध के अन्तर्गत निम्न लिख़ित कार्य किया जायेगा

1 - मानव व्यवहार एवं सामाजिक घटना का सूक्ष्म एवं व्यापक अध्ययन।

2 - परिकल्पना की उपयुक्तता की जांच करना।

3 - नवीन प्रविधियों का समुचित विकास।

4. - प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धान्त का रूप देना।

5. - विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके नवीनज्ञान का सृजन करना।

6. - स्थापित सिद्धान्त का पुनः परिक्षण।

इस प्रकार शोध एक जटिल किन्तु रूचिकर प्रक्रिया है। शोध कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि एक शोधकर्ता व्यवस्थित रूप से शोध के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुये सही शोध विधि से शोध कार्य प्रारम्भ करे। प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विधि आंकिक तथ्य को सरल करेगा, प्रो. किंग के शब्दों में – "बृहत संख्यात्मक तथ्यों को सरल बनाने में ही सांख्यकीय विज्ञान उपयोगी है।"[8] जैसा प्रस्तुत शोध का विषय है – "पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन।" सांख्यिकीय विधी ने अध्ययन को सुगम बनाया है, ए.एल. बाउले के अनुसार – "सांख्यिकी का प्रमुख व्यवहारिक प्रयोग सापेक्षिक महत्व है।"[9] इसके अलावा अनेक आर्थिक नियमों का प्रतिपादन समंकों के आधार पर ही किया गया है। जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त, डॉ. ऐंजिल का पारिवारिक व्यय का नियम आदि। शासकीय नीति का निर्माण भी समंक के आधार पर होता है – कराधान, आयाता–र्नियात, सामाजिक कल्याण, आय, मूल्य, मजदूरी, आदि सरकारी नीति समंक विश्लेषण तथा प्राप्त निष्कर्ष पर आधारित हैं।

प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विधी के साथ ही साथ इसकी सीमाओं का ध्यान भी रखा जायेगा, जैसे माप एवं निष्कर्ष औसत रूप में ही सही माने जा सकते हैं, संख्यात्मक तथ्य गुणात्मक नहीं माने जा सकते एवं समूह की माप व्यक्तिगत माप नहीं हैं आदि-आदि। जॉन मिनयार्ड कीन्स की पुस्तक General Theory of employment, interest and mony के 1936 में प्रकाशन के बाद तथा राष्ट्रीय लेखा को महत्व दिये जाने के कारण सांख्यिकीय का महत्व अर्थशास्त्र, आर्थिक नियोजन तथा नीति निर्धारण में बहुत अधिक बढ़ गया है। इस दृष्टी से भी सांख्यिकीय विधी का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत होता है।

ख - निदर्शन

शोध समस्या के निरूपण के पश्चात् शोधकर्ता ने शोध समस्या से सम्बन्धित अध्ययन क्षेत्र का र्निधारण किया है, तत्पश्चात् शोध पद्धति के बिन्दुओं के आधार पर अध्ययन से संबंधित विषय सामग्री को एकत्र किया है। शोधार्थी उन श्रोतो को भी ज्ञात करने का प्रयत्न करता है जिसके द्वारा उपयोगी तथ्यों को एकत्र किया जा सकता है। ''कार्ल पिययर्सन'' का कहना है कि ''शोध का क्षेत्र वास्तव में असीमित है तथा इससे संबंधित विषय सामग्री भी अनन्त है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक घटना, जीवन का प्रत्येक पक्ष, अतीत एवं वर्तमान का प्रत्येक स्तर शोध के लिए एक जीवित विषय सामगी प्रस्तुत करता है।''[10]

निदर्शन के माध्यम से शोधार्थी ने सम्पूर्ण इकाईयों में से कुछ का चयन स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार किया है जिससे चयन की गयी इकाईयां समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक उपयोगी पद्धति के माध्यम से हम समस्त इकाईयों में से कुछ इकाईयों का चयन कर लेते हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको समग्र के निष्कर्ष के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उदारीकरण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश की तुलना से हम उदारीकरण के अमीर तथा गरीब क्षेत्र के बीच प्रभाव को भारत के संदर्भ में भी परिभाषित कर सकेंगे। निदर्शन के संदर्भ में बोगार्ड्स ने लिखा है कि ''निदर्शन किसी पूर्व र्निधारित योजना के अनुसार इकाईयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है।'' जबकि पी.वी.यंग लिखते हैं कि ''एक सांख्यकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र है जिसमें से यह निदर्शन लिया गया है।''[12]

समूह की कुछ इकाईयों को समग्र का प्रतिनिधि किस प्रकार माना जा

सकता है, इस सम्बन्ध में शोधकर्ताओं की प्रमुख मान्यता यह रहीं है कि एक जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करने वाली इकाईयों में से यदि एक इकाई का चयन करके उसका पर्याप्त अध्ययन कर लिया जाय तो ऐसा अध्ययन अपने वर्ग की सभी इकाईयों की विशेषताओं का प्रदर्शन कर उनका स्पष्टीकरण करेगी। इस सम्बन्ध में दूसरी मान्यता यह है कि आर्थिक घटनायें परिवर्तनशील होती है, अध्ययन में इतना अधिक समय लग जाता है कि सम्बन्धित निष्कर्ष प्रस्तुत करने के समय समग्र की सम्पूर्ण विशेषतायें ही परिवर्तित हो चुकी होती है और उत्तसर प्रदेश के सन्दर्भ में, राजनैतिक स्थितियां भी इतनी तेजी से परिवर्तित हुईं है कि विभिन्न पार्टी की आर्थिक नीतियां एक दूसरे से काफी भिन्नता लिए हुए थी परन्तु पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्पन्नता में परिवर्तन यथावत् रहा है अतः तुलनात्मक अध्ययन शोध के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकेगा। तीसरी मान्यता यह है कि एक सी इकाईयों या सजातीय इकाईयों में से प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई की अच्छाईयों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि तत्वों में अत्यधिक एकरूपता हो तो चयनित इकाइयां ही सम्पूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करेगी।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में समग्र की संख्या बहुत अधिक है इससे लगभग प्रत्येक आर्थिक क्रिया यथा कृषि, उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र के द्वारा आर्थिक दशा की स्थिति जानने के लिए न्यादर्श के रूप में अधिक से अधिक इकाइयों को सम्मलित करने का प्रयत्न किया गया है।

शोध प्रक्रिया में निदर्शन की प्रतिनिधि कला के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए निदर्शन का चयन करना आवश्यक है निदर्शन का चयन करते समय पर्याप्त सावधानियां बरती गयीं हैं क्योंकि निदर्शन के चयन पर ही सम्पूर्ण

शोध प्रबन्ध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनकी सत्यता की जांच की जाती है। यदि निदर्शन के चयन में शिथिलता बरती गई होती तो समग्र की सभी विशेषताऐं शामिल नहीं हो सकती थी। यदि निदर्शन के चयन में पक्षपात किया गया हाता तो भी समग्र की सभी विशेषतायें शामिल नही हो सकती थीं। निदर्शन का चयन तत्परता या जल्दबाजी में न करके सभी पहलुओं पर पर्याप्त विचार करने के बाद किया जायेगा, निदर्शन का चयन ही सम्पूर्ण भावी शोध कार्य की आधार शिला है। निदर्शन का चयन शोधकार्य में उस नींव के समान है जिस पर भावी निर्माण कार्य किया जाना है, निदर्शन का चयन गलत हो गया तो निष्कर्ष भी गलत हो सकता है जिससे समग्र भी पूर्ण गलत होने की सम्भावना है। अतः निदर्शन के चयन में निष्ठा, ईमानदारी एवं सोच विचार के साथ र्निणय लिया गया है। निदर्शन की प्रतिनिधि भी कला का प्रभाव शोध कार्य पर सीधा पड़ता है जिससे शोध कार्य में अनावश्यक अध्ययन हो जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। निदर्शन का चयन यदि सटीक है तो अध्ययन के दौरान सार्थक परिणाम सामने आता है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही शोध कार्य व विशेलेषण को आगे बढ़ाया जायेगा।

चूँकी उत्तर प्रदेश बड़ा है अतः प्राथमिक व द्वितीयक समंकों को उचित निदर्शन विधि द्वारा एकत्र करना सुविधाजनक ही नहीं अपितु आवश्यक भी होगा।

ग - अध्ययन का समय

शोध के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण चरण संबंधित विषय तथा समय का चयन करना है जिसमें शोधकर्ता शोधकार्य करना चाहता है। हम यह कह सकते हैं कि यह चरण हमारा लक्ष्य निर्धारित कर देता है, समस्या तथा समय यैसा हो, जिसे निश्चित समय में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से शोध ा कार्य पूरा किया जा सके तथा शोध को उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जा सके। नारथ्राप के शब्दों में "शोध का कार्य एक ऐसा जहाज की तरह है जो किसी बन्दरगाह से दूर के गन्तव्य स्थान पर जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारम्भ करता है। यदि प्रारम्भ में ही गन्तव्य की दिशा र्निधारण में साधारण सी भूल हो जाती है तो जहाज कितना भी अच्छा क्यों न हो उसके भटक जाने की पूरी सम्भावना होती है।"[13]

"पी.व्ही. यंग" ने इस सम्बन्ध में चार बाते लिखी हैं।[14]

1 - विषय समझने की शोधकर्ता में योग्यता हो ताकि सम्बन्धित अध्ययन समय से पूरा किया जा सके।

2 - यदि विचारणीय विषय पर अन्य शोध न किये गये हो तो विषय को अत्यधिक विस्तृत नहीं किया जाना चाहिये।

3 - ध्यान रखना आवश्यक है कि चयन किये गये विषय का अध्ययन उपलब्ध प्राविधियों की सहायता से सम्भव है कि नहीं।

4 - यह देखना आवश्यक है कि उस विषय पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने से किस सीमा तक यथार्थ निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त चार बातों के अलावा सम सामयक शोध के लिए अध्ययन का लिया जाने वाला समय भी महत्वपूर्ण है, प्रस्तुत शोध सामयक प्रवर्ती का ही है, उदाहरण – आजादी के पश्चात् 1951 में ही यदि उदार आर्थिक नीतियों

को प्रदेश में अपनाया जाता तब कुछ अलग परिणाम प्राप्त होते तथा आज से दस वर्ष पश्चात् उदारीकरण के दीघ्र कालिक परिणाम भी काफी भिन्न होंगे। अध्ययन के लिए बहुत अधिक समय भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस स्थिती में स्वतंत्र चरों में भी अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है।

प्रस्तुत शोध में उदारीकरण की नीतियों के पूर्व, जो जून 1991 में प्रभाव में आयीं, समय 1990-91 के आँकड़ों को लिया गया है तथा उदारीकरण के पश्चात् 2004 के बाद की वर्तमान स्थिती को लिया गया है।

समस्या तथा उसके समय के योग से विषय का निर्माण होता है तथा विषय का चयन मुख्यरूप से शोधार्थी के मूल्यों एवं ज्ञान पर आधारित होता है। मूल्यों के आधार पर विषय के प्रति उसकी रूची बनती है और ज्ञान के द्वारा उसे विभिन्न समस्याओं के सामाजिक महत्व का पता चलता है।

शोधार्थी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण विषय को समझने की पूर्ण योग्यता रखता है तथा शोधार्थी का विश्वास है कि वह शोधकार्य निश्चित समय में पूर्ण करेगा तथा शोध विभिन्न योजनाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। शोध का विषय – "उदारीकरण" भविष्य को लेकर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है तथा यह नीतियों के विश्लेषण में भी सहायक होगा।

शोध का विषय चुनने के बाद पूर्व शोध के सभी विचारों, पद्धतियों, कठिनाईयों एवं निष्कर्ष का अध्ययन किया गया है ताकि अनावश्यक श्रम व्यय तथा पुनरावृत्ती से बचा जा सके। क्लखान ने लिखा है– "जब तक विषय से सम्बंधित उपलब्ध साहित्य बड़ी मात्रा में एकत्र नहीं किया जायेगा तब तक क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य सामग्री की दृष्टि से पिछड़े रहेंगे क्योंकि उसके आभाव में सही प्रश्न नहीं पूंछे जा सकते।[15] उपर्युक्त क्रम में शोधार्थी द्वारा प्रलेख,

आलेख, पुस्तकें, पत्रिकायें, प्रतिवेदन आदि का अध्ययन किया गया है, यैसा पता चला कि समग्र रूप में उदारीकरण के परिणाम जी.डी.पी. तथा फलस्वरूप प्रतिव्यक्ति औसत आय के रूप में अच्छे थे परन्तु आय असमानता में वृद्धि हुयी है, एंजिल के नियम से यह बात और भी पुष्ट हो जाती है। शोधार्थी द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना के कारण उपर्युक्त दिशा में पर्याप्त शोध किया जा सका है। दूसरा विचारणीय प्रश्न उदारीकरण के दीर्घकालिक प्रभाव के सम्बन्ध में है। शोधार्थी द्वारा इकॉनॉमिक टाईम्स, दलाल स्ट्रीट तथा समाचार पत्रों के आर्थिक पृष्ठों के नियमित अध्ययन से विषय की भावना को समझने में मदद मिली।

घ - समंक संकलन

सांख्यकीय अनुसंधान के विभिन्न चरण निम्नलिखत होत हैं :-

1 - सांख्यकीय अनुसंधान का आयोजन।

2 - समंक का संकलन।

3 - समंकों का सम्पादन तथा प्रस्तुतीकरण।

4 - समंकों का विश्लेषण।

5 - समंकों का निर्वचन तथा प्रतिवेदन तैयार करना।

सांख्यकीय अनुसंधान के आयोजन के अन्तर्गत अध्ययन का विषय, समय चयन करने के पश्चात् समंक संकलन प्रमुख चरण है। समंकों का संकलन दो प्रकार से सम्भव है : (i) नैमित्तिक रूप में (ii) जानबूझकर।

शासन के प्रशासनिक कार्यो के दौरान पर्याप्त मात्रा में समंक संकलित हो जाते हैं, जैसे - कर संग्रह, आयात-र्नियात, आदि इन्हें नैमित्तिक समंक कहते हैं। जानबूझकर एकत्र किये गये समंक सामान्य उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। जिनमें भेद किया जाना आवश्यक है। शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत एकत्र किये गये समंक सम्भव है कि योजना से लाभान्वित लोगों का ही वर्णन करें और सुविधासे वंचित लोगों की गणना शायद न की गई हो, यह प्रश्न "ग्लास आधा खाली है अथ्वा भरा हुआ" इसी प्रकार का है, अनुसंधान कार्य के लिए ज्ञान व कौशल की महती आवश्यकता है। ग्रिफिन के शब्दों में "सांख्यकीय अनुसंधान के लिए सांख्यिकी में सदैव पर्याप्त व्यवहार चातुर्य, विषय सामग्री क्षेत्र का गहरा विस्तृत ज्ञान तथा व्यवहारिक कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त योग्यता आपेक्षित है।"[16]

इसी प्रकार शोध हेतु भी समंक संकलन की दो बातों पर निर्भर करती है - (i) विषय की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य (iii) धन एवं समय की

उपलब्धता। समंक दो प्रकार के होते हैं :- (i) प्राथमिक समंक (ii) द्वितीयक समंक।

प्राथमिक समंक, अनुसंधान कर्ता द्वारा स्वयं संकलित किये गये हैं जबकी द्वितियक समंक अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित अथवा प्रयुक्त होते हैं जिन्हें प्राथमिक समंक निम्न लिखित रीतियों से संकलित किये जा सकते हैं

1- घटनाओं के अवलोकन द्वारा।

2 - विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के निष्कर्ष।

3 - प्रतयक्ष व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष मौखिक अथवा संवाददाताओं के माध्यम से सूचना एकत्र करके।

4 - अनुसूचियां अथवा प्रश्नावली भरवाकर।

प्रस्तुत शोध "उदारीकरण" सम सामयिक होने के कारण विषय के प्रत्यक्ष अवलोकन की व्यापक सम्भावना थी। 1991 में उदारीकर की प्रकिया प्रारम्भ होने के बाद से 16 वर्षों से अधिक समय होने को है और योजनाओं का परिणाम भारत की वर्तमान दशा है, इस प्रकार प्राथमिक प्रकार के समंक स्वतः ही एकत्र होते चले जाते हैं। शेष प्राथमिक समंक के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क तथा अनुसूचियों एवं प्रश्नावली का उपयोग किया गया है।

शोध में पर्याप्त मात्रा में द्वितीय समंकों का प्रयोग भी किया गया है। जिनके स्रोत निम्नलिखित थे -

(i) केन्द्र तथा राज्य सरकार के सांख्यकीय विभाग (ii) कृषि, उद्योग व वित्त विभाग के आंकड़े (iii) समितियों तथा आयोग के प्रतिवेदन (iv) व्यापारिक संस्थाओं तथा परिषदों के प्रकाशन (v) पत्र पत्रिकाएं (vi) विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों का शोध कार्य (vii) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध कार्य (viii) बाजार समाचार।

शोध विषय से सम्बन्धित समंकों के संकलन में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि इसी आधार पर शोध का निष्कर्ष तैयार किया जाता है। वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना आर्थिक शोध वास्तव में अपंग प्राणी की भाँती हैं। शोध की सफलता इस बात पर निंभर करती है कि अध्ययन के संदर्भ में कितनी वास्तविक तथा निंभर सूचनायें एवं तथ्य एकत्र किये जाते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए समंक संख्यायें मात्र हैं किन्तु विशिष्ट गुणों से युक्त संख्या समंक कहलाती है। समंक शोध के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाताहै। हॉरेंस के शब्दों में "समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है जो अगणित कार्यों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होत हैं। जो संख्याओं में व्यक्त किये जाते हैं एक उचित मात्रा के अनुसार गिने या अनुविभागीय किये जाते हैं, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत ढंग से एकत्र किये जाते हैं जिन्हें एक दूसरे से सम्बंधित रूप समें प्रस्तुत किया जाता है।[17] इसी प्रकार बेबस्तर ने अपने शब्द कोष में लिखा है कि "समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा से सम्बंधित वर्गीकृत तथ्य हैं।" और यह परिभाषा प्रस्तुत शोध "वैश्वीकरण के पश्चात पूर्वी तथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक अध्ययन" की दृष्टी से सटीक भी हैं क्योंकि शोध के माध्यम से उदारीकरण के पहले पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धी में अंतर को इसी प्रकार के समंक से दर्शाया गया है जबकि उदारीकरण के दोनों क्षेत्रों में पढ़ने वाले प्रभाव के लिए भी निवासियों की दशा से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन किया गया है।

समंक संकलन में शोधार्थी द्वारा सार्थक तकनीकों का पूर्ण उपयोग करने

का भरपूर प्रयन किया गया है। शोधार्थी ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का एकत्रीकरण किया है, अनुसूचियों और प्रश्नावलियों का निर्माण कर उनकों भरवाने का स्वयं ही प्रयास किया है। समय-समय पर अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग भी किया गया है। इसके आधार पर किसी स्थिती या घटनाओं के सह संबंध को समझना सम्भव हो जाता है। समंको के संकलन में यथा सम्भव वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया गया है जिससे शोधकार्य को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। एकत्र समंकों का सूक्ष्म निरीक्षण करके उसमे विद्यमान अशुद्धियों को दूर करने का शोधार्थी ने प्रयास किया है तथा उपयोगी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया है जिससे शोध ा कार्य में व्यवहारिक सुझाव दिये जा सकते हैं जो अन्य शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

ड़ - विभिन्न चरों का विशिष्टीकरण

आर्थिक चरों से तात्पर्य प्रतिव्यक्ति आय, औद्योगिक कृषि उत्पादन, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा प्रसार, जीवन स्तर से सम्बन्धित सूचकांक इत्यादि वह परिवर्तनशील राशियां है जिनसे देश की आर्थिक स्थितियां अथवा लोगों के आर्थिक कलयाण की जानकारी मिलती है। सिद्धान्ततः कुछ आर्थिक चरों को आर्थिक दशा का सूचकांक माना जाता है जैसे - स्वास्थ्य संकेतक के रूप में जन्मदर, मृत्युदर, प्रजनन दर (टी०एफ०आर०) मातृ मृत्युदर (ए.एम.आर.) शिशु मृत्युदर इत्यादि को रखा जाता है।

मानवीय विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुए यू.एन.डी.पी. की मानवीय विकास रिपोर्ट (1997) में उल्लेख किया गा कि "यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जता है और इनके द्वारा जनता के कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है" मानवीय विकास रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि "आय केवल एक विकल्प है जो लोग प्राप्त करना चाहेकंगे, चाहे यह बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु यह उनके समग्र जीवन का सार नहीं है, आय एक साधन है जबकि मानवीय विकास एक ध्येय है" यह टिप्पणी प्रस्तुत शोध की आत्मा के बहुत निकट हैं क्येंकि शोधार्थी भी इसी समस्या को लच्छित करता है। भारत में जब उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया तब निहित उद्देश्य लोगों की बुनियादी सुविधायें ही था आज भले ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही भागों में आय में वृद्धि हुई हो परन्तु कीमत स्तर में वृद्धि के कारण वास्तविक वृद्धि थोड़ी सी हुई है और कीमत स्तर में वृद्धि का कारण देश में विदेशी पूंजी का बेहिसाब आगमन बताया जा रहा है। आय असमानता में वृद्धि हुई है तथा वंचितो की संख्या में वृद्धि हुई है उदारीकरण के प्रभावों के अध्ययन में इन

तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। मानवीय विकास सूचक विकास के तीन मूल आयामों की औसत उपलब्धि है :-

1 - एक लम्बे और स्वास्थ जीवन के माप के लिए जन्म पर जीवन प्रत्याशा।

2 - ज्ञान जिसके माप के लिए बालिग साक्षरता दर (दो-तिहाई) और समग्र प्राथमिक, माध्यमिक और तृतियक कुल नामांकन अनुपात (एक-तिहाई) आँका जाता है।

3 - एक अच्छा जीवन स्तर जिसका माप है प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पादन (यू.एस. डॉलर क्रय शक्ति समता)।

मानवीय विकास सूचक का परिकलन करने से पूर्व इन तीनों आयामों के अलग अलग सूचक तैयार किये जाते हैं इसके लिये तीनों चरों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निंधारित करने के बाद निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है -

$$\text{आयाम सूचक} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य}}$$

लिंग सम्बंधित विकास सूचक GOI पुरूष तथा स्त्री के बीच असमानता को दर्शाता है परन्तु इसकी प्रस्तुत शोध में काई उपयोगिता नहीं है।

मानवीय निंधनता सूचक HPI में मानवीय विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार मानवीय जीवन के तीन अनिवार्य अंगों में वंचन पर केन्द्रित किया जाता है, पहला वंचन कम आयू, दूसरा वंचन असाक्षर, तीसरा वंचन निम्न जीवन स्तर है।[20] जानना प्रासांगिक है कि HPI में निंधनता का समावेश क्यों नहीं किया जाता? विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार सकल उत्पादन की धारणा भ्रामक निष्कर्ष देती है क्योंकी आय असमानता बहुत अधिक है, इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पादन सरकारी तथा गैर सरकारी सुविधाओं का समिश्रण है क्योंकि

सार्वजनिक सेवाओं का भुगतान भी कुल राष्ट्रीय आय में से किया जाता है।

किसी भी आर्थिक शोध में चरों को सही-सही परिभाषित करते हुये उनका विशिष्टीकरण किया जाना अति आवश्यक है। शोध की परिकल्पना विभिन्न आय वर्ग पर उदारीकरण के अलग-अलग प्रभाव की है, समझा जाता है कि उदारीकरण का एकमेव उद्देश्य विदेशी पूँजी को आकर्षित करके उच्च्व आय वर्ग को विलासिता की वस्तुयें उपलब्ध कराना भर है, क्योंकि मौजूदा प्रक्रिया से गरीबों के हितों पर आपेक्षित सुधार सम्भव नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिती विभिन्न सूचकांकों में अभी भी देश में नीचे बनी हुयी है इसके अलावा पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंतर भी जस का तस है। गरीबी की परिभाषा के लिए किन चरों का प्रयोग किया जाना चाहिये यह भी विचारणीय है। चूँकी विभिन्न देशों में आवश्यक वस्तुओं की सूची अलग-अलग है अतः इस आधार पर बनाया गया सूचक दोषपूर्ण हो सकता है। Human poverty Index HPI में निंधनता के लिए बच्चों में कुपोषण को संज्ञान में लिया जाता है और इसमें यदि स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित पानी की पहुँच को जोड़ दिया जाये तो यह तीन चल (Variables) गरीबी की अच्छी परिभाषा देते हैं।

धनी देशों के संस्थान ऑर्गेनाईशन फॉर इकॅनामिक डेवलेपमेंट एंड को आपरेशन (OICO) में चार चरों-जीवन प्रत्याशा, कार्यात्म साक्षरता का आभाव, बेरोजगीर दर तथ "डॅालर प्रतिदिन की प्राप्ती को मानवीय निंधनता के सूचक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारत में यू.एन. एफ.पी.एन. ने अपनी रिपोर्ट भारत जनसंख्या और विकास लक्ष्यों की ओर सन् 1997 में तथा महबूब उल हक जो यू.एन.डी.पी.

मानवीय विकास रिपोर्ट के मुख्य र्निमाता समझे जाते हैं, ने अपनी पुस्तक दक्षिण एशिया में मानवीय विकास (1997) में विकास के लिए अलग-अलग चरों का प्रयोग किया।

सार यह कि किसी भी शोध का निष्कर्ष इस बात पर बहुत अधिक निर्भर है कि प्रस्तुतीकरण के लिए किन चरों का प्रयोग किया गया है, यदि कहा जाये कि उदारीकरण के पश्चात पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्पन्नता बड़ी है तो यह सही है पर यह भी सही है कि वंचितों की संख्या में वृद्धी हुयी है और प्रस्तुत शोध असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें पूंजीवादी प्रक्रिया से बहुत अधिक बृद्धी हुयी है।

चुने हुए देशों के लिए मानवीय विकास सूचक (2000)

क्रम	देश	जन्म दर जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	बालिग साक्षरता (%)	संयुक्त नामांकन अनुपात (%)	मानवीय कल्याण सूचक
उच्च मानवीय विकास (एच.डी.आई. 0.8 और इससे अधिक)					
1.	नार्वे	78.5	99.0	97	0.942
3.	कनाडा	78.8	99.0	97	0.940
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	77.0	99.0	95	0.939
9.	जापान	81.0	99.0	82	0.933
14.	संयुक्त राज्य	77.7	99.0	106	0.928
27.	दक्षिण कोरिया	74.9	97.8	90	0.882
मध्य मानव विकास (एच.डी.आई. 0.5 से 0.8)					
51.	मेक्सिको	72.6	91.4	71	0.796
55.	रूसी फेडरेशन	66.1	99.6	78	0.781
56.	मलेशिया	72.5	87.5	66	0.782
61.	वेनेजुएला	72.9	92.6	65	0.770
68.	साऊदीअरब	71.6	76.3	61	0.759
69.	ब्राजील	67.7	85.2	80	0.757
70.	फिलीपींस	69.3	95.3	82	0.754
81.	श्रीलंका	72.1	91.6	70	0.741
87.	चीन	70.5	84.1	73	0.726
90.	ईरान	68.9	76.3	73	0.721
101	वियतनाम	68.2	93.4	67	0.688
102	इण्डोनेशिया	66.2	86.9	65	0.684
105	मिश्र	67.3	55.3	76	0.642
115	**भारत**	**63.3**	**57.2**	**55**	**0.577**
निम्न मानवीय विकास (एच.डी.आई. 0.5 से कम)					
127	पाकिस्तान	60.0	48.0	40	0.499
132	बांग्लादेश	59.4	40.8	37	0.478
136	नाईजीरिया	51.7	62.6	45	0.462
161	नाईजर	45.2	15.3	16	0.275

चुने हुए देशों के लिए मानवीय विकास की प्रवर्ती

क्रम	देश	1975	1980	1990	2000
	उच्च मानवीय विकास				
1.	नार्वे	0.856	0.875	0.899	0.942
3.	कनाडा	0.867	0.882	0.925	0.940
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.861	0.882	0.912	0.939
9.	जापान	0.851	0.876	0.907	0.933
14.	संयुक्त राज्य	0.839	0.846	0.876	0.928
27.	दक्षिण कोरिया	0.687	0.729	0.814	0.882
	मध्य मानव विकास				
51.	मेक्सिको	0.688	0.732	0.759	0.796
55.	रूसी फेडरेशन	0.809	0.823	0.779	
56.	मलेशिया	0.614	0.657	0.720	0.728
61.	वेनेजुएला	0.715	0.730	0.756	0.770
68.	साऊदीअरब	0.587	0.647	0.706	0.759
69.	ब्राजील	0.641	0.676	0.710	0.757
70.	फिलीपींस	0.649	0.683	0.716	0.754
81.	श्रीलंका	0.614	0.648	0.695	0.741
87.	चीन	0.522	0.553	0.624	0.726
90.	ईरान	0.556	0.563	0.645	0.721
101	वियतनाम	-	-	0.604	0.688
102	इण्डोनेशिया	0.467	0.529	0.622	0.684
105	मिश्र	0.433	0.481	0.573	0.642
115.	**भारत**	**0.406**	**0.433**	**0.510**	**0.577**
	निम्न मानवीय विकास				
127	पाकिस्तान	0.343	0.370	0.441	0.499
132	बांग्लादेश	0.332	0.350	0.414	0.478
136	नाईजीरिया	0.326	0.386	0.423	0.462
161	नाईजर	0.234	0.253	0.254	0.277

चुने हुए देशों के मानवीय कल्याण सूचकों (2000) की तुलना

क्रम	देश	मानवीय विकास सूचक	लिंग सम्बन्धित विकास	मानवीय निर्धनता सूचक	क्रय-शक्ति समता
उच्च	**मानवीय विकास**				
1.	नार्वे	0.942	0.941	7.5	4*
3.	कनाडा	0.940	0.938	12.3	7*
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.939	0.937	15.8	14*
9.	जापान	0.933	0.927	11.2	-
14.	संयुक्त राज्य	0.928	0.932	15.1	16*
27.	दक्षिण कोरिया	0.882	0.875	-	-
मध्य	**मानव विकास**				
51.	मेक्सिको	0.796	0.789	9.4	12.4
55.	रूसी फेडरेशन	0.781	0.780	-	-
56.	मलेशिया	0.782	0.776	10.9	-
61.	वेनेजुएला	0.770	0.764	8.5	23.0
68.	साऊदीअरब	0.759	0.731	17.0	-
69.	ब्राजील	0.757	0.751	12.2	90
70.	फिलीपींस	0.754	0.751	14.6	-
81.	श्रीलंका	0.741	0.732	17.6	6.6
87.	चीन	0.726	0.724	14.0	18.8
90.	ईरान	0.721	0.703	17.0	-
101	वियतनाम	0.688	0.687	27.1	-
102	इण्डोनेशिया	0.684	0.678	18.8	7.7
105	मिश्र	0.642	0.628	31.2	3.1
115.	**भारत**	**0.577**	**0.560**	**33.1**	**44.2**
निम्न	**मानवीय विकास**				
127	पाकिस्तान	0.499	0.468	41.0	31.0
132	बांग्लादेश	0.478	0.468	42.4	29.1
136	नाईजीरिया	0.462	0.449	34.9	70.2
161	नाईजर	0.277	0.263	62.5	61.4

पाद टिप्पणी

1. जगदीश चन्द्र पंत – व्यष्टि अर्थशास्त्र (साहित्य भवन), पृष्ठ – 36
2. डॉ. अनुपम अग्रवाल – उपकार अर्थशास्त्र, पृष्ठ – 4
3. डॉ. वी.एन. गुप्ता – सांख्यिकी, पृष्ठ – 17
4. अग्रवाल एवं पाण्डेय – सामाजिक शोध, पृष्ठ – 1
5. ओगार्ड्स इ.एस. – सोशियोलॉजी, पृष्ठ – 543
6. मोजर, सी.ए. – सर्वेमैथर्ड्स इन सोशल इन्वेस्टीगेशन्स, पृष्ठ – 3
7. फिशर, जी.एम. – डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पृष्ठ – 178
8. डॉ. बी.एन. गुप्ता – सांख्यिकी, पृष्ठ – 24
9. डॉ. बी.एन. गुप्ता – सांख्यिकी, पृष्ठ – 25
10. सामाजिक शोध – डॉ. जी.के. अग्रवाल, एस.एस. पाण्डेय, पृष्ठ – 10
11. बोगार्ड्स – सोशियोलॉजी, पृष्ठ – 548
12. पी.बी. यंग – साइंटिफिक सोशल सर्वे एवं रिसर्च, पृष्ठ – 302
13. नारथ्राप, एफ.एस.सी. – दी लॉजिक ऑफ साइंस एण्ड ह्यूमेनिलिटीज, पृष्ठ – 1
14. यंग, पी. व्ही. – साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृष्ठ – 130
15. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथर्डलॉजी, पृष्ठ – 54
16. डॉ. बी.एन. गुप्ता – सांख्यिकी, पृष्ठ – 51
17. डॉ. कैलाश नाथ नागर – सांख्यिकी के मूल तत्व, पृष्ठ – 3

18, 19. भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त एवं के.पी. एम. सुन्दरम्
(एस. चन्द्र प्रकाशन), पृष्ठ – 41

20. भारतीय अर्थव्यवस्था – के.पी.एम. सुन्दरम्, पृष्ठ – 43

तृतीय अध्याय
अध्ययन का क्षेत्र तथा परिकल्पनायें

क - क्षेत्रों की स्थिती
(पूर्वी तथा पश्चिमी)

ख - कृषि एवं उद्योग

ग - बाजार तकनीकि

क - क्षेत्रों की स्थिति
पूर्वी तथा पश्चिमी

उत्तर प्रदेश भारत का पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि यहां कृषि की उत्पादकता कम है तथा प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन कम है। मानवीय विकास सूचकांक के अनुसार भी उत्तर प्रदेश अविकसित राज्य है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी सम्भाग का आर्थिक विकास एक समान नहीं है, यद्यपि इन्हें एक समान होना चाहिये था। उदारीकरण के पश्चात् 15 वर्षों का परिणाम यह है कि इस आर्थिक असमानता में और अधिक वृद्धि हुयी है क्योंकि निजी पूँजी का निवेश विकसित क्षेत्रों में अधिक रहा है। अमीर देशों की संस्था ओ.ई.सी.डी. के अनुसार उदारीकरण के कारण भारत में 1.3 करोड़ नये रोजगार सृजित हुये हैं।[1] यह तर्क सही है परन्तु भारत की समस्या भिन्न है, यहां 4 प्रतिशत बेरोजगारी ज्योंकी त्यों है।[2] भारत की विशाल जनसंख्या के कारण विकसित देशों के मशीनीकरण की नीति भारत के संदर्भ में सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की समस्या भारत से अधिक है। यह सारी समस्या शोध का विषय रहेगी।

उत्तर प्रदेश निम्न आर्थिक विकास के दुष्चक्र में फँसा हुआ है इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए उच्च विनियोग के साथ ही साथ प्रदेश में मानवीय संसाधन के विकास पर भी समुचित ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक पिछड़ा हुआ है जिसके विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विनियोग के महती लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में उदारीकरण की आर्थिक नीति को अपनाया गया। उदार आर्थिक नीति का तात्पर्य यह था कि उत्पादन में वृद्धि के नियमों में कुछ ढील दी जाये ताकि बढ़े पैमाने पर निजी विनियोग आकर्षित हो पर देखा गया कि इस विधि से बड़े उद्योगपति एकाधिकारी स्वरूप धारण करने लगते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा का परिणाम यह होता है कि योग्य कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन देकर उद्यमी उन्हें अपने साथ जोड़े रखना

चाहते हैं और धीरे–धीरे यह व्यवस्था पूँजीवाद का रूप ले लेती है। चंद उद्यमियों द्वारा लाभ कमाना ओर कुछ कर्मचारियों को अत्याधिक वेतन ही असमानता का कारण बनता हैं भारतीय गणतंत्र की पचासवीं वर्षगांठ पर पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने देश को सावधान करते हुए कहा – "उदारीकरण से उपजी विषमता और धन का अश्लील प्रदर्शन यदि जारी रहा तो समाज में सिर्फ अशांति फैलेगी।" आर्थिक असमानता हर पूँजीवादी राष्ट्र की विशेषता है, अमेरिका में धनी व विपन्न के बीच 440 गुना आय का अंतर है। भारत में लगभग 555 गुना आय का अंतर है। सर्व प्रमुख उद्योग चैम्बर सी.आई.आई. के सालाना समारोह को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी इसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, उहोंने कहा – "लाभ कमाने की कुछ सीमायें तथा मर्यादायें होनी चाहिये, लाभ को लोभ नहीं बनाया जाना चाहिये।" उन्होनें कम्पनी के प्रवर्तकों तथा निदेशकों को अधिक वेतन न उठाने की नसीहत दी। उदारीकरण के बाद अब सरकार के पास आय असमानता को दूर करने के लिए कुछ रास्ते ही बचते हैं। आर्थिक सम्पन्नता का अन्तर व्यक्तिगत होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय भी है और यही पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के मध्य शोध का विषय है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. एम. गोविन्द राव "सेज" परियोजनाओं को भी क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि का वाहक मानते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र समृद्धी के टापू बनकर रह जायेंगे। भारत में उदारीकरण के प्रारम्भ होने के साथ ही देखा गया कि निजी विनयोग विकसित क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित था क्योंकि वहां लागत लाभ अनुपात अधिक था और सेवा क्षेत्र में यह स्थिति अधिक थी क्योंकि मोबाईल, बैंक, मल्टी कॉम्प्लेक्स इत्यादि सेवा क्षेत्र की प्रकृति ऐसी है कि इनके उत्पादन को दूसरे क्षेत्रों में पूर्ती (ट्रॉस्पोर्ट) नहीं किया जा सकता अतः इन्हें येसे स्थानों पर लागाना अधिक

उपयुक्त था जहां लोगों की आय अधिक हो तथा क्रय शक्ति अधिक हो। आर्थिक असमानता का दोष साम्यवादी व्यवस्था में कम देखने को मिलते हैं। भारत में अपनायी गयी राष्ट्रवादी आर्थिक नीति तथा सर्वोदय का अर्थ शास्त्र साम्यवादियों से भिन्न तथा अधिक प्रभाशाली रही है। राष्ट्रवादी तथा सर्वोदय अर्थशास्त्रियों ने समानता मूलक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया, दादाभाई नैरोजी कि पुस्तक **Poverty and un-British rule in India (1901)**, डॉ. मोक्ष गुन्दम रानाडे कि पुस्तक **Reconstruaction in India (1920)** तथा **Planned economy of India (1934)** तथा गाँधीवादी अर्थशास्त्र से कुछ ऐसी ही भावना अनुनाद होती है। 90 के दशक तक अधिकांश देशों ने राष्ट्रवादी विचारों को छोड़कर वैश्वीकरण की राह अपनायी। बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या विकास और साम्य में अन्तर्विरोध है? साईमन कुजनेट्स ने तर्क दिया कि "आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में असमानता बढ़ेगी परन्तु जैसे–जैसे औद्योगिक उत्पादन विस्तृत होता जायेगा असमानता कम होती जायेगी।[7]

इसी प्रकार निकोलास काल्डर ने तर्क दिया आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए बचत उद्योगपतियों की जेब से प्राप्त होगी और इस वर्ग के लिए अधिक लाभ को बर्दाश्त करना होगा ताकि ये विनियोग के उच्च स्तर को प्रोन्नत करने के लिए बचत उपलब्ध करा सकें जिससे विकास प्रक्रिया त्वरित होगी।[8]

इन तर्कों के विपरीत मानवीय विकास रिपोर्ट (1996) में कहा गया – "पारम्परिक विचार कि आर्थिक विकास के आरम्भिक चरणों में अनिवार्य आय वितरण में गिरावट आती है, असत्य प्रमाणित हुआ, नयी खोज यह बताती है कि सार्वजनिक और निजी संसाधनों के साम्यिक वितरण से अधिक विकास की सम्भावना हैं।"[9] मानवीय विकास रिपोर्ट से इसी विरोधाभाष की सम्भावना थी क्योंकि आर्थिक

विकास का वास्तविक सूचकांक कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति में बेहिसाब वृद्धी को आर्थिक विकास नहीं मानती, विकास का सही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों का कम से कम, न्यूनतम स्तर प्राप्त हो।

प्रस्तुत शोध उदारीकरण के पश्चात् पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन इसी दृष्टिकोंण से किया जा रहा है। वैश्विक उदारीकरण की तुलना में पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य श्रम की गतिशीलता जैसी कोई समस्या नही। अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ पूर्वी भाग से श्रमिक असानी से पश्चिमी भाग में जीवकोपार्जन के लिए जा सकता है। (किन्तु इस स्थिति में पूर्वी भाग और अधिक पिछड़ सकता है।)

1999 तक नियोजन का ही परिणाम है कि सरकारी योजना से सड़क शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण संस्थानों की दृष्टि से पूर्वी भाग अधिक पीछे नहीं है परन्तु उदारीकरण के बाद अधिसंख्या उद्योगों की स्थापना पश्चिमी भाग में हुयी है।[9] यह स्वाभाविक वृत्ती है कि जहां उद्यमियों को आर्थिक लाभ तथा सुरक्षा होगी वही वह स्थापित होंगे, उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में जाने को विवश नहीं किया जा सकता। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति आय, उपभोग व्यय तथा बचत अधिक है और पूँजीवादी बाजार शक्तियों के कार्यकरण की वजह से इन क्षेत्रों की सम्पन्नता में तो पर्याप्त वृद्धी हो रही पर पिछड़े क्षेत्र पिछड़ रहे हैं।

शोध का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही साथ उन कारणों की खोज करना भी है जिसके कारण उदारीकरण का लाभ उठाकर अमीर देश और अधिक अमीर होते जाते हैं तथा धन की संस्कृति ने हमारे सामाजिक ढाँचे को किस प्रकार प्रभावित किया हैं सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में "योग्यतम की उत्तर जीवता" (डार्विन का वैज्ञानिक नियम) जैसी नीतियां लागू नहीं की जा सकती। विवकानंद ने कहा था "यदि एक भी व्यक्ति भूखा है तो सारा समाज दोषी है।

धन का समान वितरण आर्थिक चिन्तन का विशेष विषय रहा है। महात्मा गाँधी ने भी इस विषय पर अपने विचार देते हुये पत्र के माध्यम से इंग्लैण्ड के वायसराय से पूंछा था कि "यदि उनके देश में अमीर तथा गरीब के मध्य आय में 150 गुने का अन्तर है तो भारत में 5000 गुने अंतर के लिए ब्रिटिश नीतियां क्यों उत्तरदायी नहीं है?[10] आर्थिक असंतुलन सामाजिक तानेबाने को छिन्न भिन्न कर सकता है। प्रो. रिचर्ड क्विनी ने "अपने विचार देते हुये कहा – अपराध को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – 1. प्रतिरोध अपराध 2. वर्चस्व अपराध।[11] इसी प्रकार प्रो. राबर्ट मिलर के अनुसार "गरीबी की संस्कृति समाज के प्रति नफरत पैदा करती है।"[12]

आर्थिक विकास के साथ ही साथ साम्य तथा लोकतंत्र के उद्देश्यों को साथ–साथ चलाने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रबल रूप में जुड़े हुये हैं।

विश्व बैंक के 192 देशों के बारे में किए गये अध्ययन से पता चलता है कि विकास के केवल 16 प्रतिशत भाग की व्याख्या भौतिक पूँजी की तीव्रता के द्वारा (मशीन, बिडिंग, आधार संरचना) की जा सकती है जबकि 20 प्रतिशत भाग के लिए मानवीय एवं सामाजिक पूँजी को श्रेय दिया जाता है।[13] शोधार्थी का ऐसा मानना है कि ऐसे विश्वसनीय प्रमाण होते हुये भी यह वांछनीय नहीं है कि आर्थिक विकास को धीरे–धीरे नीचे की ओर रिसने दिया जाये तथा इंतजार किया जाये। नीचे की ओर रिसने वाले दृष्टिकोंण का प्रतिस्थापन रोजगार – जनन विकास से किया जाना चाहिये जिसके लिए भारत को पूर्ण रोजगार के प्रति अपनी वचन बद्धता प्रदर्शित करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में विकास प्रक्रिया को साम्यिक तथा जन सहयोगी बनाना होगा, इसके लिए सामाजिक क्षेत्र अर्थात् स्वास्थ्य और शिक्षा में भारी विनयोग करना होगा

ताकि एक बेहतर श्रम शक्ति द्वारा उत्पादिता को बढ़ाया जा सके जिसके परिणाम स्वरूप विकास का अधिक लाभ श्रमिकों को मिल सकेगा। इस बात की आवश्यकता नहीं कि प्रदेश में उद्योगों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ती केवल पश्चिमी भाग या अन्य प्रदेश करते रहें। बल्की पूर्वी उ.प्र. का भी सहभाग रहे। यह समझना होगा कि विनियोग एवं मानवीय विकास में अंतर विरोध नहीं बल्की दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। विकास, साम्य तथा लोकतंत्र के उद्देश्यों को जब तक एक साथ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, विकास प्रदेश के गरीब वर्ग तथा बड़े भू भाग के लिए अपूर्ण रहेगा।

ख - कृषि एवं उद्योग में

कृषि किसी भी देश की आवश्यकता है, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन जहां नागरिकों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए आवश्यक है वहीं कृषि उत्पादन श्रम गहन एवं बड़ा उद्योग होने के कारण अधिक जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत कृषि प्रधान देश है और इस कारण वैश्वीकरण की कृषि सम्बन्धित नीतियों ने हमे अधिक प्रभावित किया है। विश्व व्यापार के अन्तर्गत माना गया था कि अमीर देश औद्योगिक उपादन को तथा अल्पविकसित देश कृषि उत्पादन का निर्यात करेंगे परन्तु संधी के विपरीत (क्योंकि ऐसी वाध्यता नहीं थी) औद्योगिक देशों ने सब्सिडी देनी प्रारम्भ कर दी जिसके फलस्वरूप लागत लाभ दृष्टि से कुशल न होने के बावजूद उन्होंने जरूरी उत्पादन तो कर ही लिया बल्कि उसे निर्यात योग्य स्थिति में आ गये और इसका परिणाम आज यह है कि हमारे यहां तथा अन्य विकासशील देशों के किसान आत्म हत्या को मजबूर हैं, यह समस्या तथा निजी पूँजी ने कृषि को किस प्रकार लाभ पहुँचाय है एवं नीवन प्रौद्योगिकी का लाभ क्या है यह शोध का विषय रहेगा। इसी के साथ तुलनात्मक रूप से सम्पन्न व विपन्न क्षेत्र के मध्य उदारीकरण के प्रभाव का अध्ययन भी शोध का विषय रहेगा।

आजादी के समय भी भारत अंग्रेजों की गलत नीति के कारण गम्भीर खाद्य संकट से गुजर रहा था और उस समय का अनुभव अत्यंत कटु रहा, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने राष्ट्र के नाम सम्बोधन में कहा "खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पश्चात् परिस्थितियों का बदस्तूर दबाव बना रहेगा और इससे दुःख व संकट ही उत्पन्न होगा।"[14] और तब हमने खाद्य सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हुये प्रथम पंच वर्षीय योजना से ही कृषि को अत्यधिक महत्व दिया। 1964 में एक बार फिर हम तीव्र खाद्यान्न संकट की स्थिति से गुजरे तब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन नें पी.एल. 480 प्रोग्राम से भारत को वियतनाम नीति पर मजबूर किया।[15] एक बार फिर

हम खाद्य सुरक्षा के प्रति सतर्क हुये और ''अधिक अन्न उपजाओ'' तथा ''जय जवान जय किसान'' के नारे के साथ हरित क्रँाति तथा अन्य क्षेत्रीय नीतियों के माध्यम से खाद्य संकट को दूर करने का प्रयत्न किया गया और भारत ने 1976 में खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली।

उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में पश्चिमी क्षेत्र का योगदान अधिक है जबकि पूर्वी भाग का योगदान कम है जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दोनों क्षेत्र लगभग समान हैं कृषि वैज्ञानिक मंगलाराय के अनुसार ''पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी क्षारीय होने के कारण तथा उर्वरकों का कम प्रयोग होने के कारण (40 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) इस क्षेत्र की उत्पादकता कम है पर इसे दो गुने तक बढ़ाने की अपार सम्भावना है।''[16]

हमारे अध्ययन का समय 1991 के पश्चात् होने के कारण इस दौरान उदारीकरण व वैश्वीकरण के रूप में व्यापक तकनीकि परिवर्तन हुये। कृषि में ठेका खेती तथा रिटेल, कोल्ड चैन के माध्यम से विपणन तथा भण्डारण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रवेश किया गया तथा इनके विस्तार की व्यापक सम्भावना है। विश्व व्यापार कानून में निहित पेटेंट कानून से लाभ होने की दशा में शोध फर्में निजी पूँजी की सहायता से बीजों के विकास में भी आगे आयी है पर यह मानव कल्याण के लिए न होकर मुनाफा वसूलने के लिए है क़्योंकि ऐसी बातें देखीं गयीं कि यह कम्पनियाँ ''जेनेटिक – संवर्धन'' के द्वारा बीजों की उत्पादकता भले बढ़ा देती है परन्तु यह फसल दोबारा बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी तथा खेतों की उत्पादकता भी कुछ समय के लिए नष्ट हो जायेगी। शोध के माध्यम से यह भी कारण खोजने का प्रयत्न किया जायेगा कि क्यों कृषि में निजी निवेश पश्चिमी क्षेत्र

की ओर ही आकर्षित हुआ, सम्भवता यहां पूँजी उत्पाद अनुपात अधिक है।

1991 के पश्चात् कृषि में निजी पूँजी निवेश के प्रारम्भिक परिणाम कई कारणों से सुखद नहीं रहे, ऐसा माना जा रहा है कि निजी पूँजी श्रम प्रतिस्थापना है जिसके कारण बेरोजगारी का दबाब और अधिक बढ़ जायेा। पेटेंट कानून तथा हाईब्रिड बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न आत्म निर्भरता संकट में पढ़ सकती है और कल्याणकारी अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। मंगलाराय के अनुसार "फर्टिलाईजर के अधिक प्रयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्पादकता भी अब घटने लगी है। कयोंकि यहां जमीन में कार्बन तथा अन्य माईक्रोपोषक तत्वों की कमी होने लगी हैं, पहले सनई ढैचा, हरी खाद तथा गोबर से इसकी पूर्ती कर ली जाती थी पर आधुनिक खेती में यह अनुपलब्ध हो गये हैं।[17]

उदारीकरण की लहर का प्रभाव औद्योगिक उदारवार के रूप में अधिक था पर इस उदारवाद का लक्ष्य किन बिन्दुओं पर आधारित होना चाहिये, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा सुविधाजनक जीवन यापन, ना कि कुछ व्यक्तियों द्वारा महंगा तथा उच्च स्तरीय जीवन यापन। अध्ययन के माध्यम से यह देखा गया कि उदारवाद के पश्चात् महंगी तथा विलासी वस्तुओं की जितनी उपलब्धता भारत में बढ़ी है उस अनुपात में गरीबों की संख्या कम नहीं हुयी है। उदारीकरण व वैश्वीकरण के रूप में आधुनिक युग का पूँजीवाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा वर्णित पूँजीवाद से काफी भिन्न है।[18] क्योंकि आज लगभग कहीं भी राजशाही नहीं है व लोकतांन्त्रिक सरकारें होने के कारण मजदूरों के पास वोट के रूप में वह शक्ति प्राप्त है कि पूँजीपतियों को आर्थिक हित कभी–कभी राजनैतिक हित के आगे त्यागने भी पढ़ते हैं और राजनीति–अर्थनीति की जुगलबंदी का सुखद परिणाम यह हुआ कि आज न तो दास है और न श्रमिकों के शोषण पर आधारित "दास कैपिटल" में वर्णित पूँजीपति और

और वर्तमान पूँजीवाद तभी तक जीवित है जब तक उद्योगपति उपभोक्ताओं को भ्रम जाल में उलझाये हुये है।

नव पूँजीवाद के स्थल अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैण्ड की व्यवस्था बहुत अच्छी न हो तब भी संतोषजनक कही जा सकती है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के अनुसार उनके देश में मार्क्स की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुयी क्योंकि वहां की व्यवस्था से मध्यवर्ग 80 प्रतिशत तक पहुँचगया।[19] यह सही है कि अमेरिका में अत्याधिक अमीर लोगों की संख्या कम हुयी है पर इसी कारण पूँजीवादी निर्माता बाहर बाजार ढूंढने निकले है और वैश्वीकरण आर्थिक साम्राज्य विस्तार का कारण बन सकता है।

उदारीकरण नीति निजी पूँजी निवेश में कठिनाई यह है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में निवेश को विवश नहीं किया जा सकता अतः सरकार के सामने समस्या यह है कि किन नीतियों द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया जाये। यही विश्लेषण शोध की प्रमुख समस्या हैं 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने औद्योगिक पिछड़े हुये राज्यों की पहिचान के लिए पांच कसौटियां अपनायी।[20] यह निम्न हैं :–

1. कुल प्रति व्यक्ति आय के साथ उद्योगों एवं खमन का योगदान।
2. प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या।
3. बिजली का प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग।
4. राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल की तुलना में पक्की सड़क की लम्बाई।
5. राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल की तुलना में रेल–मार्ग की लम्बाई।

उपरोक्त आधार पर ही पांडे कमेटी (जो कि औद्योगीकरण में पिछड़े राज्यों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी।) ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा राज्य के रूप

में घोषित किया। वांचू कमेटी ने पिछड़े राज्यों की दशा सुधारने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की उसका अनुपालन करते हुये आयोजन के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया गया। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए नियोजित आर्थिक विकास आवश्यक प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में परस्पर काफी आर्थिक भिन्नता है और इस दृष्टि से यह शोध महत्वपूर्ण है।

ग - बाजार तकनीकि

राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धी आर्थिक विकास का सूचकांक माना जाता है क्योंकि जब उत्पादन में वृद्धि होगी तभी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उत्पादन में वृद्धि के पश्चात् उत्पादन के विक्रय की समस्या है, क्योंकि यदि उत्पादन बेंचा न जा सका तो यह अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण बन जायेगा।

अतः बाजार तकनीकि वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं गतिशील अंग माना जाता है। क्लासिकी अर्थशास्त्री उत्पादन विक्रय की समस्या को नहीं मानते थे, वह अर्थ व्यवस्था को स्वसंचालित मानते थे, उनके समय (1776–1890) में मंदी जैसी कोई समस्या भी सामने नहीं आयी थी, उनके अनुसार अति उत्पादन या बेकारी अस्थायी समस्या है ओर अर्थ व्यवस्था स्वतः ही इन दोषों को दूर कर देती है।[23] इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध "से" का नियम "पूर्ती अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है।" सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।[24] 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फ्रांसिसी अर्थशास्त्री "जीन वैपिस्ते से" के इस बाजार नियम ने पर्याप्त ख्याती अर्जित की, प्रो. हैन्सन ने भी "से" के इस मार्केट नियम को स्वतंत्र वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए सही बताया।[21] ए.सी. पीगू (इंग्लैण्ड 1877–1959) ने से के बाजर नियम को सूत्र बद्ध किया उनके अनुसार "पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रतियोगिता के रहते सदैव एक ऐसी प्रवृत्ति प्रबल रूप से कार्यशील रहेगी जिससे मजदूरी की दरें मांग के साथ इस तरह सम्बद्ध हों कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार में लगा रहे।"[22]

इन विचारों पर सर्वाधिक कड़ा प्रहार जॉन मेनर्ड केन्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Jeneral theory of employment, Interest and money (1936) के माध्यम से किया। केन्ज ने उस प्रथागत तथा संस्थापित अर्थशास्त्र का खण्डन किया जो एक

शताब्दी से अधिक समय तक निर्मित हुआ था और "बड़ी मंदी"से पहले तक आर्थिक विचारधारा तथा नीति पर अपना प्रभुत्व जमाए था। केन्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर क्सासकी अर्थशास्त्र से विपरीत विचार प्रस्तुत किये।[25]

1. अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्थान पर अल्परोजगार संतुलन पाया जाता है।
2. बचत व निवेश पृथक–पृथक कार्य हैं अतः सम्भव है कि अति उत्पादन हो जाये।
3. पूर्ण रोजगार पर अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन नहीं होता।

केन्ज के General theory में उत्पादन का विक्रय बढ़ाने के लिए "प्रभावी मँाग" का सिद्धान्त दिया गया। बरहाल उत्पादन का विक्रय भी एक महती समस्या था। General theory के प्रकाशन के समय ही अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में वैश्वीकरण के रूप में "पूँजीवाद" एक नयी शक्ल ले रहा था, विश्व में 1930 के दशक और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान व्यापार की व्यापक पद्धति को कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और इसी समस्या के समाधान के लिए 96 देशों ने प्राशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट) General Agreement on tariffs and trade - GATT समझौते को 1 जनवरी 1948 से लागू किया और यह विश्व में वैश्वीकरण का आगाज था।

"से" के बाजार नियम तथा केन्ज के प्रभावी मँाग के सिद्धान्त के बीच एक बात स्पष्ट रूप से विभाजित की जा सकती है कि केन्ज के सिद्धान्त की मंदी तथा तेजी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का ही विशिष्ट लक्षण है इसके विपरीत समाजवादी या परम्परावादी (वस्तु विनमय अर्थव्यवस्था) में सम्भवतः व्यापार चक्र की अवस्थायें न पाय जाती हों, जैसा कि "से" ने अपने नियम में स्पष्ट किया और इस तथ्य की पुष्टि मंदी तथा तेजी की अन्य अर्थशास्त्रियों की परिभाषा से होती है। हाट्रे ने व्यापार

चक्र को मौद्रिक समस्या बताया।[26] शुम्पीटर ने व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धान्त दिया उनके अनुसार "मंदी का कारण समृद्धी" है।[27] फ्रीडमैन और श्वार्टज ने यू.एस. ए. के आंकड़ों के आधार पर यह तर्क दिया कि व्यापार चक्र मूल रूप से मुद्राभण्डार में परिवर्तन के साथ–साथ घटित होते हैं।[28] इस प्रकार ज्ञात होता है कि जब वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों को अपनाया गया तभी उत्पादन के विक्रय के लिए बाजार तकनीकि की भी आवश्यकता महसूस हुयी, दूसरा नवीन प्रौद्योगिकी चाहे वह कम्प्यूटर हो या आधुनिक कृषि उपकरण मानव को आराम देने के स्थान पर उसने श्रम प्रतिस्थापन किया जिसके फलस्वरूप क्रय शक्ति सिमिट कर थोड़े से समर्थ लोगों के हाथ आयी है तथा इस थोड़े से क्षेत्र में माल को खपाने के लिए भी विक्रय तकनीकि की आवश्यकता हुयी।

उत्पादन के विक्रय की समस्या पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के रूप में सामने आती है। जिस प्रकार विकासशील तथा अविकसित देशउत्पादन में वृद्धी के लिए परेशान है उसी प्रकार विकसित देश उत्पादित किये गये माल के बिक न पाने के कारण परेशान है और वैश्वीकरण के रूप में विभिन्न देशों के जुड़ने का कारण यह भी है। विकसित देशों में ज्यों–ज्यों फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि होती है त्यों–त्यों अलग–अलग ब्रांडों के मध्य गलाकाट प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होती है और कम्पनियों के मध्य प्रचार युद्ध का सुपरिणाम यह होता है कि उपभोक्ता की बचत प्रवर्ती घटकर अनाधुनध उपभोग से अर्थव्यवस्था में लाभ होता है।

भारत में भी उदारीकरण के लागू होने के बाद धीरे–धीरे विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसार पर व्यय बढ़ा है परन्तु अभी भारत में वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी है कि मंदी पैर पसार सके।

विज्ञापन व्यय की अपेक्षा "विक्रय लागतों" का अर्थ विस्तृत होता है, विक्रय

लागतों में विज्ञापन व्यय के अतिरिक्त सैल्समैनों का वेतन एवं मजदूरी, फुटकर विक्रेताओं द्वारा वस्तु के प्रदर्शन के लिए भत्ता एवं अनेक प्रकार की प्रोत्साहन सम्बन्धी क्रियाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। चैम्बरलिन ने, जिन्होंने मूल्य सिद्धान्त में विक्रय लागतों के विश्लेषण का सूत्रपात किया, इन्हें उत्पादन लागत से भिन्न बताया। उनके अनुसार "वे लागतें जो पदार्थ को मांग के अनुकूल बनाने के लिये की जाती हैं उत्पादन लागते हैं, वे जो मांग को पदार्थ के अनुकूल बनाने के लिये उठायीं जाती है, विक्रय लागते हैं।"[29] जबकि किसी उद्योग की समस्त फर्मे मिलकर किसी अन्य उद्योग की तुलना में बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करती हैं तो इसे "प्रोत्साहन विज्ञापन" कहते हैं।[30] भारत में टेरिन वस्त्रों का उपभोग बढ़ाने में एवं मुर्गी के अण्डों का उपभोग बढ़ाने में प्रोत्साहन विज्ञापन का अहम योगदान रहा है।

इसके विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन एक फर्म द्वारा दूसरे फर्म के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किये जाते हैं। 1930 के बाद से विज्ञापनों का स्थान उत्पादन प्रक्रिया में धीरे– धीरे बढ़ता चला गया और अब इस क्षेत्र में पर्याप्त शोध भी किया जा चुका है। प्रो. हिब्डन के शब्दों में "बड़े पैमाने की विज्ञापन क्रियाएँ निपुण एवं प्रभावशाली विशेषज्ञों से सम्भव है।"[31] अध्ययन के मध्य भारत में उदारीकरण के पश्चात् प्रचार युद्ध और अधिक तेज हुआ है, विचारणीय प्रश्न यह है कि आर्थिक विकास विशेषतः कल्याणकारी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, कहां तक सही है? उत्पादन के विक्रय में विज्ञापनों के साथ ही साथ खुदरा व्यापारियों का भी अहम योगदान है, यह दौर (2006 के बाद) रिटेल कारोबार का है। बड़ी–बड़ी उपादक कम्पनियां रिटेल क्षेत्र में आ रहीं हैं।

भारत में उपभोग वृद्धी में वित्तीय संस्थानों का योगदान बढ़ रहा है, उपभोक्ता ऋण में वृद्धी हुयी है। महंगी वस्तुओं को जहां किस्तों पर दिया गया तथा

प्रतिदिन उपभोग की खरीददारी भी क्रेडिट कार्ड से की जा रही है। भारतीय विविधताभरी अर्थव्यवस्था को वर्तमान व्यवस्था ने किस तरह प्रभावित किया है तथा इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? उ.प्र. भी इन बाजार तकनीक की नीतियों से प्रभावित है। बड़े मॉल, बिग बाजार व आकर्षक उपहार योजनाऐं लाकर उपभोक्ताओं को लुभाने का कार्य प्रारम्भ कर चुकी है। अतः इनके परिणाम जानने के लिए "पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन" किया गया है। यदि उपभोक्तावाद के कारण भारतीयों की बचत प्रवृत्ति घटती है तो उसका दुष्परिणाम उद्यमिता ह्रास के रूप में भी दिख सकता है।

पाद टिप्पणी

1. अमर उजाला – 21 जून 2007, सम्पादकीय
2. दैनिक जागरण – 4 जुलाई 2007 में यह आँकड़े भरत झुन झुन वाला के लेख में प्रकाशित हैं।
3. दैनिक जागरण 28 जनवरी 1999 में यह बात राष्ट्रपति के संबोधन में प्रकाशित हुयी।
4. व 5. दैनिक जागरण 25 मई 2007
6. दैनिक जागरण 8 अक्टूबर 2007 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य का इन्टरव्यू प्रकाशित हुआ।
7. व 8. भारतीय अर्थ व्यवस्था – एस. चन्द्र, पृष्ठ – 52
9. U.N.D.P., Human Development Report (1996), P-6
10. गाँधी स्मृति ग्रंथ माला से।
11. व 12. दैनिक जागरण 19 जून 2007 सुधांसू रंजन का लेख
13. एस. – चन्द्र भारतीय अर्थ व्यवस्था, पृष्ठ – 53
14. व 15. भारतीय अर्थ व्यवस्था रूद्र दत्त एवं सुन्दरम, पृष्ठ – 400
16. व 17.दैनिक जागरण 9 जुलाई 2007, भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद के महानिदेशक मंगलाराय का इंटरव्यू।
18. व 19.आर्थिक चिन्तर का इतिहास – डॉ. चतुर्वेदी, पृष्ठ – 390
20. भारतीय अर्थ व्यवस्था – एस. चन्द्र (डॉ. रूद्र दत्त), पृष्ठ – 381
21. मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ शास्त्र, एम.एल. झिंगन
22. A.C. पीगू, Theory of unemployment, P.-252
23. व 24.–आर्थिक चिन्तन का इतिहास, चतुर्वेदी और चतुर्वेदी, पृष्ठ – 56
25. एम.एल. झिंगन – मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ शास्त्र।
26. हाट्रे R.G. Trade and credit 1928, the art of centeral banking 1932
27. J.A. Schumpeter, Business cycles, 1939
28. M. Friedman and A. W. Schwartz. "Money & Business cycles" R.E.S. (Suppement) 1963
29. Edward, H. Chamberlin - The Theory of monopolistic competition 6'th edition, P-123
30. उच्चतर आर्थिक सिद्धान्त (एस. चन्द्र) एच. एल. अहूजा, P-589
31. James E. Hibdon, Price & Welfare Theory, M.C. Graw-Hill 1969, P-302

चतुर्थ अध्याय
आर्थिक परिवर्तन

क - उदारीकरण का अभिप्राय
ख - उदारीकरण का प्रारम्भिक काल

क - उदारीकरण का अभिप्राय

1985 में सर्वप्रथम सरकार ने उदार आर्थिक नीतियों के संदर्भ में चिन्तन प्रारम्भ किया, उदारीकरण को मूर्त रूप जून 1991 में दिया जा सका जब तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में नियमों में ढील दी तथा उसे प्रतिबन्धों एवं सीमाओं से मुक्त कर दिया।[1] बजट एवं आर्थिक निर्णयों से संचालित इन आर्थिक नीतियों को उदार आर्थिक नीति या उदारीकरण का नाम दिया गया। उदार आर्थिक निर्णय यकायक न होकर सुधारों की एक श्रंखला के रूप में थे जो बाद के कई वर्षों तक एक के बाद एक अपनाये गये थे। उदारीकरण का यह स्वरूप 1991 के बाद से ही राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं रहा अर्थात् राष्ट्रीय उदारीकरण ही नहीं रहा बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय उदारीकरण या वैश्वीकरण हो गया।

आर्थिक नीति की किसी देश के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक नीति एक अत्यधिक व्यापक शब्द है जिसमें किसी भी सरकार की मौद्रिक, राजकोषीय, विदेशी व्यापार, रोज़गार, उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों का समावेश होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का अभिप्राय देश में उपलब्ध आर्थिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को त्वरित करना है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि होती है। आर्थिक नीति के विशिष्ट उद्देश्य सारांशतः निम्नलिखित हैं :-

(i) राष्ट्रीय आय में वास्तविक उच्च्य वृद्धी प्राप्त करना।

(ii) पूर्ण रोजगार तथा कीमत स्थिरता।

(iii) स्थिर विनमय दरों युक्त बाह्य व्यापार एवं भुगतान संतुलन में साम्य।

(iv) देश के नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाना।

इस प्रकार राष्ट्र की अर्थनीति तात्कालिक राजनैतिक तथा सामाजिक कारकों पर निर्भर रहते हुये पूर्ण रूपेण प्रावैगिक होती है जिसमें काल क्रम में परिवर्तन होता रहता है।

यही कारण है कि सभी राष्ट्र समय-समय पर अर्थनीति में परिवर्तन तथा समीक्षा करते रहते हैं। भारत की अर्थनीति की मुख्य विशेषता इसकी गतिशीलता अर्थात् इसमें लोचशीलता का होना है।[2]

आर्थिक विकास की दृष्टि से अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक भारत की स्थिती अत्यंत सुदृढ़ थी, इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के पश्चात् पहले इसका स्वरूप व्यापारिक था परन्तु शीघ्र ही इसने भारत पर सत्ता स्थापित कर ली और "सत्ता व्यापार का अनुसरण करती है।" (Flag follow the trade) कहावत को चरितार्थ किया।[3] 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ती के समय भारत की आर्थिक दशा अत्यंत नाजुक थी और इससे निपटने को समाजवादी स्वरूप की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। 1947 से 1950 तक की अवधि अनियोजित विकास की रही और 1951 से नियोजन के रूप में पंच वर्षीय योजनाओं का श्री गणेश किया गया। 1951 से 1991 तक चार दशकों में भारत सरकार का आर्थिक क्रियाओं में प्रबल हस्तक्षेप था तथा सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में सरकार प्रत्यक्ष व्यापारिक क्रियाओं में सहभागी थी।[4] 1939 में केन्ज ने भी इस प्रकार की व्यस्था का समर्थन तथा पूँजीवाद का विरोध करते हुये लिखा - "संसार ऊपर से इस प्रकार प्रशासित नहीं कि निजी एवं सामाजिक हित सदा एक रूप हो जायें।"[5] इसी प्रकार पीगू ने भी समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में लिखा है।

''समाजवादी केन्द्रीय आयोजन प्रणाली को यदि प्रभावी रूप में व्यवस्थित किया जाये तो यह कई प्रकार से हमारी वर्तमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से बेहतर हैं।''[6]

भारत में चार दशकों तक नियंत्रित एवं नियोजित आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, 1991 में बदलते वैश्विक परिवेश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए उदारीकरण की नई नीति के साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश (विनिवेश) की नीति भी अपनायी गई। विनिवेश प्रक्रिया 1991-92 में पी.एस.यू. के अल्प हिस्सों की विक्री के साथ प्रारम्भ हुयी। 1999-2000 से 2003-2004 तक सामरिक बिक्री को अधिक महत्व दिया गया। विश्व व्यापार के अन्तर्गत बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमती एवं उनके क्षेत्र का विस्तार वैश्वीकरण के रूप में प्रस्तुत है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) का समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ तब भारत इसका संस्थापक सदस्य था और इसी के साथ उदार आर्थिक नीतिया वैश्वीकरण की ओर अधिक प्रत्यावर्त हुयीं।

विश्व व्यापीकरण शब्द आज अन्तर्राष्ट्री बाजार में गुंजायमान है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवांतता एवं उनके विस्तार का द्योतक है। विश्वव्यापीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाओं विशेषकर विपणन सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है जिसमें सम्पूर्ण बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में विश्व व्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व–बाजार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने में सफल होता है।[7] वैश्वीकरण व्यापार को लागत न्यूनतमीकरण में दक्ष बनाकर प्रतिस्पर्धात्मक रूप देने का प्रयत्न है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले

कारक निम्नलिखित थे –

1 - प्रौद्योगिकी में हो रहे निरन्तर सुधार एवं स्पर्धात्मक दृष्टिकोंण।

2 - विश्व बाजार में पूँजी की बढ़ती गतिशीलता।

3 - सूचना क्रॅांति के कारण विभिन्न देशों के बाह्य ढाँचे, रूचियों एवं संस्कृति में उत्पन्न होती समानता।

4 - दुर्लभ संसाधनों के कारण राष्ट्रो के मध्य पारस्परिक निर्भरता बढ़ना।

1930 के दशक की मंदी में विश्व के अमीर देश विशेषतः अमेरिका एवं यूरोप गम्भीर आर्थिक संकट में फँसे हुये थे, अति उत्पादन, बढ़ती बेरोजगारी, स्थैतिक बनी हुयी विकास दर एवं आशानकूल निर्यातों में बृद्धि न होने के कारण विश्व व्यापार के लिऐ नई दिशा खोजने की जरूरत हुयी और तब हवाना में 1947-48 शीतकाल में व्यापार और रोजगार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी परिणति व्यापार एवं प्राशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार – गैट (General Agreement on tariffs and trade - GATT) पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर हुये।[8] 1 जनवरी 1995 को गैट समाप्त हो गया तथा इसकी समस्त शर्तें विश्वव्यापार संगठन के समझौतों में शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र – सेज (Special Economic Zone - SEZ) के रूप में भारत की उदार आर्थिक नीतियां विशेष क्षेत्र के लिए और अधिक उदार बनायीं गयीं।[9] निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (E.P.Z.) के रूप में सर्वप्रथम एशिया में विशेष आर्थिक क्षेत्र के महत्व को भारत ने ही पहिचाना था, कांडला में 1965 में भारत ने सर्वप्रथम ई.पी.जेड की स्थापना की थी परन्तु सेज का वर्तमान स्वरूप चीनी मॅाडल पर आधारित है जिसे भारत ने अप्रैल 2000 में अपनाया।[10] सेज के दो उद्देश्य बताये गये हैं :-

(i) निर्यात को बढ़ावा देना।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (F.D.I.) को आकर्षित करना।

सेज वास्तविकता में ई.पी.जेड. का गुणात्मक सुधार है, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली यूनिटें देश के सीमा शुल्क के दायरे से बाहर समझी जायेंगी और इन्हें कार्यकरने के लिए पूरा लचीलापन प्राप्त होगा। सेज स्वस्थायी और स्वावलम्बी नगर क्षेत्र है, ये "स्टेट ऑफ द आर्ट" ढाँचे से सम्पन्न हैं एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध में "हैसल फ्री" वातावरण निर्यात के लिए उपलब्ध कराते हैं।[11] 1 नवम्बर 2000 से 9 फरवरी 2006 तक
देश में सेज विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत कार्य करता रहा, संसद में एस.ई.जेड. अधिनियम मई 2005 में पारित हुआ।[12]

सरकार के अनुसार फरवरी 2007 तक देश में 234 SEZ परियोजनाओं की अनुमति दी गई है। जिसके लिए 33808 हैक्टेयर भूमी की आवश्यकता होगी।[13] उत्तर प्रदेश के दादरी में सेज परियोजना प्रस्तवाति है। देश की 6.3% SEZ परियोजनायें दक्षिणी क्षेत्र में हैं।

उत्तर		दक्षिण		पूर्व		पश्चिम	
चंडीगढ़ –	1	आ.प्र. –	40	झारखण्ड–	1	गोआ –	1
हरियाणा–	1	कर्नाटक–	16	उड़ीसा–	1	गुजरात–	9
मध्य प्रदेश–	2	केरल –	8	पं. बंगाल–	1	महाराष्ट्र–	15
पंजाब –	2	तामिलनाडु–	16				
उ.प्र. –	6						
राजस्थान –	1						
कुल	**19**		**80**		**3**		**25**

सेज परियोजना[14]

उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम
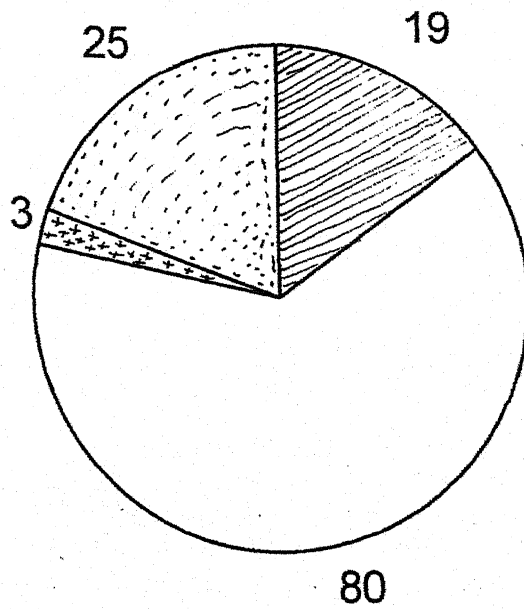
ख - उदारीकरण का प्रारम्भिक काल

उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों को भारत में लागू किए हुये डेढ़ दशक बीत चुका है। विश्व व्यापार के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में प्रारम्भ से ही मतभेद रहा है। क्लास की एवं नव क्लासकी अर्थशास्त्री विदेशी व्यापार के प्रबल पक्षधर रहे हैं। मुक्त व्यापार का तात्पर्य प्रो. जगदीश भगवती के अनुसार "ऐसे व्यापार हैं जहां विदेशी व्यापार पर प्रशुल्क, कोटा, विनमय नियंत्रणों, उत्पादन, साधन प्रयोग तथा उपभोग पर करों तथा सहायिकाओं का आभाव हो।"[15] प्रो. लिप्सी की परिभाषा के अनुसार "मुक्त व्यापार जगत वह होगा जिसमें आयात अथवा निर्यात करने पर कोई प्रशुल्क और प्रतिबन्ध न हो।"[16] शिशु उद्योग तर्क में फ्रैडरिक लिस्ट तथा अलैक्जेन्डर हैमिल्टन (1970) ने घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए विदेशी व्यापार का विरोध किया है।[17] नर्क्से का दृष्टिकोंण है "बिल्कुल बृद्धि न होने की अपेक्षा विदेश व्यापार के माध्यम से होने वाली थोड़ी वृद्धी श्रेष्ठ है।[18] गैट यह नहीं मानता कि उसकी नीतियों से विकासशील देशों को काई नुकसान है उसके अनुसार "अधिकांश विकासशील देश केवल 1/3 निर्मित भाग का ही आयात करते हैं और यह अनुपात भी अब घटता जा रहा है।[19]

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोंण के अतिरिक्त भारत में प्राचीनकाल से ही स्वतंत्रता को महत्व दिया गया, इसी के अनुरूप अर्थव्यवस्था में कृषकों, शिल्पियों, कारीगरों, मजदूरों सभी को पूरी छूट थी कि वह अपने स्थान के विकास के लिए कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। चाणक्य के पूर्व भी विदुर नीति, बृहस्पत नीति, शुक्रनीति, पुराणों एवं शास्त्रों में राजा के कर्तव्य के प्रति बताते हुये कहा गया कि "उत्तम राजा के देश में प्रजा उन्नति करती है।" इसका अभिप्राय यही था कि राजा ऐसे लोगों को संरक्षण देता था जो अपने क्षेत्र में

प्रगतिशील थे। चाणक्य की अर्थनीति में भी विकास एवं अर्थ व्यवस्था के विभिन्न स्वरूपा की चर्चा की गई है और यह भी बताया गया है कि कृषि, उद्योग, कर आदि विभिन्न स्थितियों को देखते हुये कल्याणकारी एवं विकसित राज्य की परिभाषा कैसे की जा सकती है।

राजा के दायित्वों से लेकर कृषि की विभिन्न अवस्थाओं, उद्योगों का विकास व्यापार की उन्नत दशा एवं करों के स्वरूप आदि विषयों की चर्चा चाणक्य ने की थी एवं कल्याणकारी राज्य तथ सुखी प्रजा की कल्पना का चित्रण किया था। चाणक्त के पूर्व, उनके समकालिक तथा उनके पश्चात् के भारतीय अर्थशास्त्रियों के मौलिक चिंतन के कारण भारत समृद्धशाली राष्ट्र बन सका था, क्योंकि स्वदेशी ही यहां के लोगों की विविधताओं, स्वभाव एवं रूचि को भली-भांति समझ सकता था। 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में भारत आये दार्शिनकों ने यहां की व्यवस्था का सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है। चीनी यात्रियों फाह्यान तथा ह्वेनसांग ने यहां के विकसित स्वरूप तथा नागरिकों के सादगीपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। 18 वीं शताब्दी तक भारत का विदेशी व्यापार दूर-दूर के राष्ट्रों तक फैल चुका था तथा भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 20% तक पहुँच गया था परन्तु अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् उसने बल पूर्वक तथा क्षल छद्‌दम से इसे अस्त व्यस्त कर दिया। अंग्रेजों की उपनिवेशिक आर्थिक नीतियों तथा शोषण के कारण इस देश का आर्थिक विकास क्षीण होता गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में बड़े उद्योगों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की नीति अपनायी गई स्वतंत्र व्यापार की मात्रा को सीमित रखा गया और इस कारण कृषि, लघु और कुटीर उद्योग और अधिक हतोत्साहित हुये यद्यपि

जनसंख्या दबाव के उपचार में श्रम गहन कृषि, लघु और कुटीर उद्योग अधिक कारगर थे। नियोजित विकास में कृषि व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अलग रणनीति बनायी गई परन्तु वह अपर्याप्त रही और कृषि में अल्पकालिक लाभ होते हुये दूरगामी दुष्परिणाम भी प्राप्त हुये। असुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आभाव में कृषि व छोटे उद्यम आपेक्षित विकास नहीं कर सके और बढ़ते भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही तथा इंस्पेक्टर राज ने उन्नति के अन्य मार्गों को भी लगभग बन्द कर दिया। 1990 का दशक आते-आते उत्पादन प्रारम्भ करने की जटिल प्रक्रिया तथा पूँजी के अभाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक भंवर में फंस चुकी थी और हम अपनी आर्थिक नीतियों के पुनर्विचार हेतु विवश हुये और उपचार स्वरूप उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। वैश्विक जगत में जब इसी प्रकार की सोच प्रारम्भ हुयी तो हम भी उसमें सम्मिलित हो गये।

उस समय उदारीकरण के निम्न उद्देश्य बताये गये[20]-

1. अर्थव्यवस्था में अविलम्ब स्थाईत्व लाया जाये।
2. राजकोषीय सुधारों को लागू करना।
3. अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया को गतिशील करने हेतु आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाये।
4. आर्थिक कार्यकुशलता में वृद्धी तथा औद्योगिक उत्पादन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता उत्पन्न करना।
5. विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी का अधिक कुशल प्रयोग तथा अधिक आमंत्रण।
6. सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन को सुधारना।

7. वित्तीय क्षेत्र की कार्यप्रणाली सुधारना एवं आधुनिकीकृत करना।

8. साथ ही साथ आर्थिक सुधार का बोझ गरीब वर्ग पर न डाला जाये।

उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ती के लिए तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने सुधारों की एक श्रंखला प्रारम्भ की जो कि आर्थिक सुधार या आर्थिक उदारीकरण के नाम से जाने जाते हैं। यह सुधार निम्न प्रकार थे[21] –

1. रूपये का अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को 9.5%, दो दिन पश्चात् 8.5% और 15 जुलाई 1991 को रिजर्व बैंक द्वारा 2% । इस प्रकार रूपये का कुल 20% तक अवमूल्यन हुआ।

2. केन्द्रीय, बजटीय सुधारों के अन्तर्गत 24 जुलाई 1991 को प्रस्तुत किये गये बजट में बजट घाटे, राजस्व घाटे, और भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% से 6.5% प्रतिशत पर सीमित किया गया। इस बजट में गैर योजनागत व्यय को भी कम किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया। बजट प्रस्तावों के अनुरूप रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 1992 को भारतीय रूपये को 60 प्रतिशत तक परिवर्तनीय बना दिया तथा नई उदारीकृत विदेशी विनमय प्रणाली (L.E.R.M.S.) का श्री गणेश किया गया और इस प्रकार ''एग्जि स्क्रिप्ट'' प्रणाली समाप्त हो गई।

3. बजट 1992-93 में आर्थिक नीति में अनेक परिवर्तन किये गये। ब्याज की दरें 1% कम की गईं। वर्द्धित जमाओं पर SLR को 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया। खुली आयात लाईसेंस प्रणाली (O.G.L.) लागू की गई। पूँजी निर्गमन पर सरकारी नियंत्रण समाप्त किये गये। कस्टम शुल्क कम किये गये। स्वर्ण आयात प्रणाली को सरल किया गया। औद्योगिक सुधारों के

फलस्वरूप बेरोजगार लोगों के पुनर्वास के लिए ''राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष'' की स्थापना की गई। स्वर्ण बॉण्ड योजना भी इसी बजट में प्रसतावित थी। शेयर बाजार में विदेशी निवेश को अनुमती दी गई। कर प्रणाली को सरलीकृत करने का प्रस्ताव भी इसी बजट में रखा गया।

4. औद्योगिक सुधारों के लिए 18 विशिष्ट किस्म के उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए तकनीकि महानिदेशालय में पंजीकरण तथा लाईसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई।

5. मुद्रा प्रसार के नियंत्रण के लिए साख संकुचन की नीति को अपनाया गया। रिजर्व बैंक ने बैंक दर पहले 10 से 11% और फिर 12% कर दी। नगद कोषानुपात जून 1980 के 6.00 से जून 1991 में 5.0 व वैधानिक तरलता अनुपात 34.00 से 38.5% कर दिया गया। 1 अप्रैल 1992 को परिवर्द्धित जमाओं पर भी वैधानिक तरलता अनुपात घटाकर 30% कर दिया गया।

6. वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए अगस्त 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा कर प्रणाली में सुधार के लिए राजा जे. चलैया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। वित्त वर्ष 1991-92 में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से 2500 करोड़ की राशि जुटाई जबकि 1992-93 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के 4.9% शेयरों की बिक्री से 3500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। केन्द्र सरकार ने 1985 के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम में संशोधन किया गया तथा सार्वजनिक उपक्रमों की नियमित जांच के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण ब्यूरो (BIFR) का गठन किया गया।

उपर्युक्त आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप त्वरित प्रभाव यह देखने को मिला की भारतीय विदेशी विनमय कोष में वृद्धी प्रारम्भ हो गई। जून 1991 के 2383

करोड़ की तुलना में फरवरी 1992 के अन्तिम सप्ताह में विदेशी विनमयं कोष 11,440 करोड़ था। अनिवासी भारतीयों द्वारा अप्रैल-जून 1991 में प्रतिमाह 33.5 करोड़ डॅालर की दर से राशि की निकासी अब रूक चुकी थी।

सुधारों के फलवरूप मुद्रा प्रसार पर काबू नहीं पाया जा सका था जिसके लिए राजकोषीय घाटे, भुगतान कमी के कारण आयात में असमर्थता, अनिवार्य वस्तु की मांग एवं पूर्ती में अंतर एवं संगठित क्षेत्र में मजदूरी वृद्धी को कारण बताया गया।

आर्थिक सुधार के रूप में भारतीय रूपये का विश्व की चार प्रमुख मुद्राओं की तुलना में 20% तक अवमूल्यन किया गया था। जिसके फलस्वरूप भारत के निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी तो हुयी परन्तु भारतीय रूपये के रूप में आयात बिल अधिक हो गया और निर्यात बिल कम हो गया। आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद भारत के भुगतान संतुलन का घाटा अन्र्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की सहायता से समाप्त किया जा सका। भारत को IMF से 3 अरब डॅालर का ऋण मिलां जिससे भारत ने अपने अल्पकालिक वाणिज्य उधार चुकाये तथा रिजर्व बैंक ने अपना गिरवीं रखा सोना वापस प्राप्त किया। स्टेट बैंक ने भी अपना सोना (20 करोड़ डॅालर) पुनः क्रय कर लिया।

भारत की उदार आर्थिक नीतियों का लाभ दुनियां भर के देशों ने खुले हाथ उठाया। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान के अधिकांश निवेश सम्बन्धी प्रोजेक्ट या तो मंजूर किये जा चुके थे या मंजूर किये जाने वाले थे।

विदेशी पूँजी के प्रति उदारता का मार्ग कितना सार्थक सिद्ध हुआ, विदेशी पूँजी और घरेलू पूँजी के मध्य गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा का क्या परिणाम हुआ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्मुख हमारी देशी कम्पनियों का कार्य प्रदर्शन कैसा रहा, इस बात का ज्ञान वर्तमान आर्थिक दशा से हो जाता है।

पाद टिप्पणी

स्रोत :- प्रतियोगिता दर्पण जून 1992, केन्द्रीय बजट 1991–92, 92–93, 93–94, फरवरी इंडिया टुडे, क्रोनिकल, सिविल सर्विसेज

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - रूद्र दत्त एवं सुन्दरम्, पेज - 214
2. प्रतियोगिता दर्पण, जून 1992
3. प्रतियोगिता दर्पण, मई 19994
4. भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्रदत्त एवं सुन्दरम्, पेज – 88
5. J.M. Keynes the end of laissezs fair
6. A.C. Pigou, Socialism bersus capitalism

7 - 8 : एम. एल. झिंगन, मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पेज – 594, 681

9. कारोबार डेस्क (दैनिक जागरण 7 अप्रैल 2007)
10. दैनिक जागरण 7 अप्रैल 2007
11. सिविल सर्विसेज टाईम्स, विशेष संस्करण 2006

12-13 : दैनिक जागरण 7 अप्रैल 2007, अर्थ पेज

14. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

15 - 19 : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास – एम.एन. झिंगन

20. प्रतियोगिता दर्पण जून 1992
21. केन्द्रीय बजट 1991 – 92 तथा 1992–93

पंचम अध्याय
वर्तमान स्थिति

क - कृषि में

ख - उद्योगों में

ग - बाजार तकनीकि

घ - अन्य व्यवसाय

क - कृषि में

विकसित तथा अविकसित दोनों ही क्षेत्रों के लिए कृषि का महत्व बहुत अधिक है, एक ओर पर्याप्त अन्न उत्पादन से क्षेत्र को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है तो दूसरी ओर अत्यधिक रोजगार भी इसी उद्योग से है। उ.प्र. की अधिक जनसंख्या को देखते हुये कृषि का महत्व और भी अधिक है, यदि मुद्रास्फीती के प्रभाव को अलग कर दिया जाये तो 1990-91 से 1998-99 तक प्रदेश में प्रतिव्यक्ति सकल कृषि उत्पादन में मात्र 46 रू० की वृद्धी हुयी है।[1] प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने की जरूरत है। विश्व बैंक के महानिदेशक (स्वतंत्र मूल्यांकन समूह) विनोद थॉमस का मानना है "उ.प्र. को यदि विकास के पथ पर लाना है तो कृषि में निवेश को बढ़ाना होगा।"[2] इन दिनों प्रदेश की योजना समिति कृषि में निजी निवेश की सम्भावनाओं पर भी विचार कर रही है। विकास के साथ-साथ देखा जाता है कि जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता कम होती है परन्तु उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा गया कि 1981 में मुख्य कर्मकारों में कृषकों की संख्या 74.50 थी तथा 1991 में 74.25, इस दृष्टि से मामूली सुधार हुआ है।[3] 1980 से 2004 तक उत्तर प्रदेश की विकास दर 4% रही जो बिहार(3.7%) से ही अधिक है।[4] कृषि में पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित तुलनात्मक अध्ययन देखा गया -

* [1] गेंहू उत्पादन (मी. टन)

	1990-901	**1999-2000**
पश्चिमी	8059089	11352623
पूर्वी	5844567	8224885
कुल उत्तर प्रदेश	17907657	25550931

(केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड सहित)

गेंहू उत्पादन का प्रतिशत
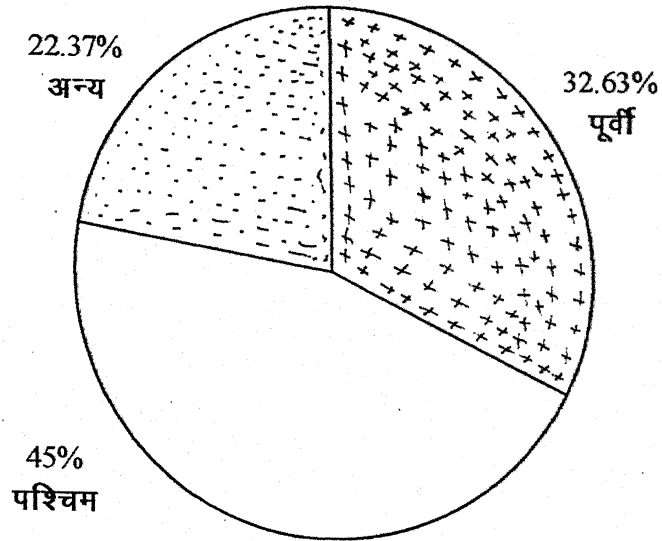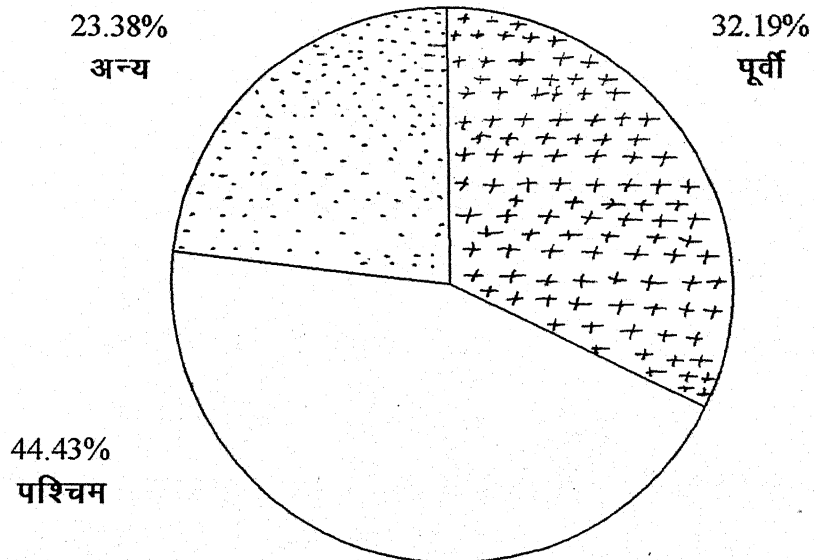
शोध अवधि में उत्तर प्रदेश का सकल गेहूं उत्पादन 70% बढ़ गया है तथा 44.43% गेंहू पश्चिमी सम्भाग उत्पादित करता है।

* [2] औसत उपज

कुन्टल प्रति हेक्टेयर (उत्पादकता)

	1990 - 91	1999-2000
पश्चिमी	26.01	32.48
पूर्वी	19.17	25.00
उत्तर प्रदेश	21.71	27.73

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

प्रति हेक्टेयर गेंहू उत्पादन तुलनात्मक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी कम है, 1991 से 2000 तक गेंहू उत्पादन में आनुपातिक वृद्धी समान हुयी। उत्तर प्रदेश की प्रति हेक्टेयर गेंहू उत्पादकता राष्ट्र के औसत 27.7 के बराबर है, पर यह नहीं भूलना होगा कि उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता अन्य फसलों के लिए कम है।

* [3] चावल उत्पादन

	मी. टन	कुल	औसत (कुन्टल/हे०)	
	1990 - 91	1999 - 2000	1990 - 91	1999 - 2000
पश्चिमी	2466720	3474445	22.35	22.67
पूर्वी	5204746	6837719	16.80	22.18
उत्तर प्रदेश	9668710	12632754	18.27	21.77

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

1990 - 91 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल की औसत उपज संतृप्त थी तथा 1999 - 2000 तक पूर्वी तथा समस्त उ.प्र. की औसत उपज भी लगभग संतृप्त हो चुकी है। (भारत में चावल की औसत उपज 20.9 कुन्टल प्रति हेक्टेयर है।)

*** [4]**

	आलू उत्पादन मी. टन		आलू की औसत उपज (कुन्टल/हे०)	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999 - 2000**
पश्चिमी	3484075	5972552	214.62	252.18
पूर्वी	1711185	2158636	163.41	182.35
उत्तर प्रदेश	6131897	9600881	190.29	225.36

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

*** [5]**

	तिलहन उत्पादन मी. टन		तिलहन का औसत उत्पादन (कुन्टल/हे०)	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999 - 2000**
पश्चिमी	557505	443941	10.25	11.31
पूर्वी	67824	97980	4.97	6.17
उत्तर प्रदेश	833870	833966	8.35	8.71

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

* [6]

	गन्ना उत्पादन मी. टन		गन्ना की औसत उपज (कुन्टल/हे०)	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999 - 2000**
पश्चिमी	68493849	72188337	603.91	596.71
पूर्वी	16193249	16532383	489.97	494.77
उत्तर प्रदेश	97209744	108577182	558.10	573.93

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

देखा गया है कि प्रत्येक कृषि जिंस का कुल उत्पादन तथा उत्पादिता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है तथा पूर्वी क्षेत्र का उत्पादन तथा उत्पादिता प्रदेश के औसत से कम है।

कृषि आधारित पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विस्तृत तुलनातमक अध्ययन निम्न प्रकार है –

* [7] कुल उपयुक्त विद्युत में कृषि में उपयुक्त विद्युत का प्रतिशत

	1990 - 91	**1999-2000**
पश्चिमी	41.5	42.8
पूर्वी	32.8	25.3
उत्तर प्रदेश	33.6	31.5

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

* [8]

	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोया क्षेत्रफल से प्रतिशत		कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल बोय गये क्षे.से प्रतिशत	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999 - 2000**
पश्चिमी	77.8	88.1	77.0	84.9
पूर्वी	59.6	69.0	48.2	60.8
उत्तर प्रदेश	60.9	74.1	58.0	70.0

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि में उपयुक्त विद्युत का प्रतिशत अधिक है तथा यहां कि कृषि अधिक सिंचित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17.7% कृषि नहरों द्वारा सिंचित है जबकी पूर्वी में 27.2% तथा उत्तर प्रदेश में 25.4% तथा निजी पम्पिंग सेट तथा नलकूप पश्चिमी क्षेत्र में अधिक (41%) है। बाढ़ से प्रभावित खरीफ की फसल पूर्वी सम्भाग में 6.35% तथा पश्चिमी क्षेत्र में मात्र 0.04% है। कृषि जोत का आकार पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार है :-

*** [9] खेतों का आकार**

	1 हेक्टेयर से कम		1-2 हेक्टेयर	
	1990 - 91	**1995 - 1996**	**1990 - 91**	**1995-96**
पश्चिमी	66.1%	68.8%	18.9%	17.8%
पूर्वी	82.3%	83.0%	11.6%	10.9%
उत्तर प्रदेश	73.8%	75.4%	15.5%	14.6%

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

* [10] खेतों का आकार

	2-4 हेक्टेयर		4 हेक्टेयर से अधिक	
	1990 - 91	**1995 - 1996**	**1990 - 91**	**1995-96**
पश्चिमी	10.8%	9.9%	4.2%	3.5%
पूर्वी	4.6%	4.7%	1.5%	1.4%
उत्तर प्रदेश	7.7%	7.4%	3.0%	2.7%

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर तक के छोटे खेतों की संख्या 75% है तथा 1990-91 की तुलना में इनमें वृद्धि हुयी है जो सम्भवता जनसंख्या विस्फोट के कारण हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे आकार के खेतों की संख्या औसत से कम जबकी पूर्वी क्षेत्र में औसत से अधिक है तथा इसका प्रभाव कृषि उत्पादन के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि बढ़े आकार के खेतों में कृषि उत्पादकता अधिक देखी जाती है।

* [11] विभिन्न जोत वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण

	1 हेक्टेयर से कम		1-2 हेक्टेयर	
	1990 - 91	**1995 - 1996**	**1990 - 91**	**1995-96**
पश्चिमी	24.7	28.1	24.8	24.9
पूर्वी	43.4	44.8	23.8	22.8
उत्तर प्रदेश	31.4	33.7	24.4	23.8

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

* [12] विभिन्न जोत वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण

	2 - 4 हेक्टेयर		4 हेक्टेयर से अधिक	
	1990 - 91	**1995 - 1996**	**1990 - 91**	**1995-96**
पश्चिमी	27.2	26.4	23.3	20.6
पूर्वी	18.5	19.4	14.3	13.1
उत्तर प्रदेश	23.4	23.3	20.8	19.1

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे तथा बड़े खेतों के अधीन क्षेत्रफल का वितरण समान है जबकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की 44.8 प्रतिशत कृषि भूमि छोटे कृषकों के अधीन है।

* [13] शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का

	कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत		फसल सघनता	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999-2000**
पश्चिमी	89.64	90.96	152.83	157.45
पूर्वी	84.42	85.62	153.95	152.12
उत्तर प्रदेश	82.98	86.36	147.29	149.34

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

* [14] प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलो ग्राम में

	1990 - 91	**1999-2000**
पश्चिमी	108.27	154.09
पूर्वी	86.22	123.64
उत्तर प्रदेश	87.95	126.64

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मंगलाराय के अनुसार भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कम प्रयोग किया जा रहा है, यदि उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया जाये तो यहां भी उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है।[5]

प्रति लाख हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर विनियमित मंडियों की संख्या पश्चिमी (4.2) में पूर्वी (2.9) की तुलना से अधिक है तथा प्रति ग्रामीण व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी पश्चिमी क्षेत्र (.14 हे.) पूर्वी क्षेत्र (.10 हे.) की अपेक्षा अधिक है और इसका प्रभाव कृषि आय के रूप में दिखाई देता है –

*** [15]** प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रूपये)

	प्रचलित भाव पर		1993-94 के भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1990 - 91**	**1998 - 99**
पश्चिमी	10089	24997	5237	16701
पूर्वी	7274	17370	3816	11760
उत्तर प्रदेश	8339	19083	4292	12812

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

[16]	कुल खाद्यान्न उत्पादन (मी. टन)		औसत उपज कुन्टल / हेक्टेयर	
	1990 - 91	**1999 - 2000**	**1990 - 91**	**1999-2000**
पश्चिमी	13121216	17267028	21.29	26.25
पूर्वी	12532515	16466355	16.20	21.18
उत्तर प्रदेश	33867920	44261136	17.43	21.93

(बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)

खद्यान उत्पादन में दोनों क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान

1990 - 91
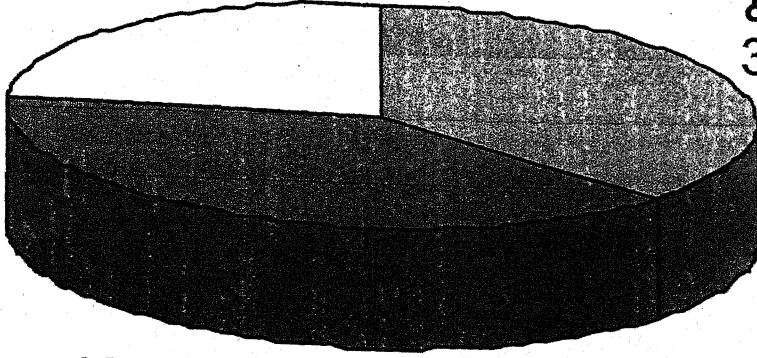
कुल उत्पादन 33867920 मी. टन

1999-2000
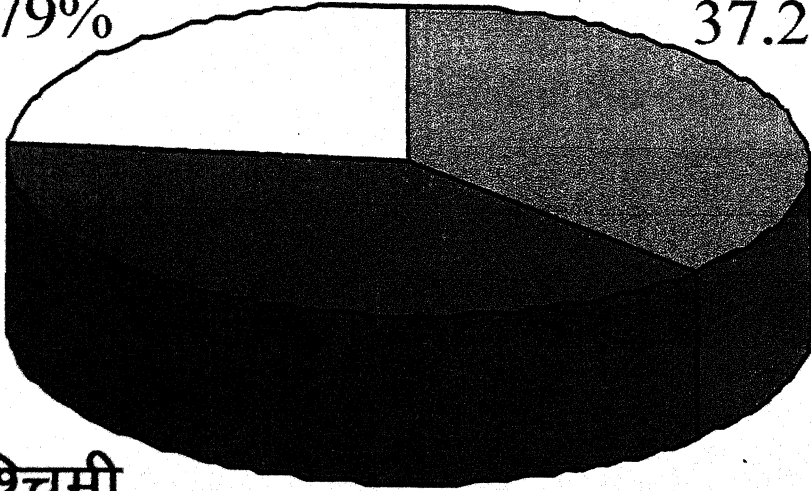
कुल उत्पादन - 44261136

* [17] प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन प्रतिव्यक्ति दलहन उत्पादन

	(कि.गा.)		(कि.गा.)	
	1990 - 91	1999 - 2000	1990 - 91	1999-2000
पश्चिमी	270.90	293.44	11.12	5.65
पूर्वी	240.14	253.31	15.36	11.23
उत्तर प्रदेश (बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)	258.04	276.37	20.14	15.93

* [18] प्रति हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर पशुधन की प्रति हजार जनसंख्या पर पशुधन की संख्या

	1990 - 91	1999 - 2000	1990 - 91	1998
पश्चिमी	3.15	3.15	392	343
पूर्वी	3.85	3.64	414	334
उत्तर प्रदेश (बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)	3.53	3.35	444	349

प्रति हजार जनसंख्या पर पशुधन की संख्या सबसे अच्छी बुन्देलखण्ड में 1990-91 में 685 तथा 1998 में 619 थी अर्थात् पशुपालन बुन्देलखण्ड का मुख्य कृषि व्यवसाय है।

प्रति ट्रैक्टर सकल बोये गये क्षेत्रफल की उपलब्धता हेक्टेयर में सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र (28.5) है जबकि (54.3) में लगभग दो गुनी कृषि भूमि पर ट्रेक्टर है अर्थात् पश्चिमी क्षेत्र में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है।

* **[19]** प्रति हजार जनसंख्या पर दुधारू पशुओं की संख्या — प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या

	1989 - 90	1998	1990 - 91	2000 - 01
पश्चिमी	75	101	94	119
पूर्वी	52	72	51	82
उत्तर प्रदेश (बुन्देलखण्ड व केन्द्रीय सहित)	67	92	78	98

* **[20]** वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षे. का सकल बोये गये क्षे. से प्रतिशत — प्रति हेक्टेयर विभागीय क्षेत्रफल पर मतस्य उत्पादन (कि.ग्रा.)

	1990 - 91	1999 - 2000	1990 - 91	2000-01
पश्चिमी	33.07	31.65	-	638
पूर्वी	10.50	10.55	-	15
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	20.01	20.33	-	22

* **[21]**

प्रतिलाख जनसंख्या पर सहकारी कृषि विपणन केन्द्रों की संख्या — प्रलिाख जनसंख्या पर सहकारी विपणन समितियों की संख्या

	1990 - 91	2000 - 2001	1990 - 91	2000-2001
पश्चिमी	4.65	2.93	0.20	0.16
पूर्वी	1.51	1.78	0.14	0.11
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	2.80	2.23	0.19	0.14

*** [22]** प्रतिलाख ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या / प्रतिलाख जनसंख्या पर संयुक्त कृषि सहकारी समितियों की संख्या

	प्रतिलाख ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 1990 - 91	2000 - 2001	प्रतिलाख जनसंख्या पर संयुक्त कृषि सहकारी समितियों की संख्या 1990 - 91	2000-2001
पश्चिमी	6.62	3.66	1:26	0.97
पूर्वी	7.78	5.17	0.70	0.56
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	7.74	4.58	0.99	0.78

*** [23]** प्रतिलाख ग्रामीण जनसंख्या पर सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकासबैंको की संख्या / प्रतिहजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर शीत गृहों की संख्या

	प्रतिलाख ग्रामीण जनसंख्या पर सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकासबैंको की संख्या 1990 - 91	2001 - 2002	प्रतिहजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर शीत गृहों की संख्या 1990 - 91	2001-2002
पश्चिमी	0.24	0.23	0.45	0.45
पूर्वी	0.16	0.13	0.44	0.43
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	0.20	0.18	0.30	0.36

*** [24]** प्रतिलाख जनसंख्या पर सहकारी विधायन संयन्त्रों की संख्या / प्रतिलाख हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर सहकारी कृषि विपणन केन्द्रो की संख्या

	प्रतिलाख जनसंख्या पर सहकारी विधायन संयन्त्रों की संख्या 1990 - 91	2000 - 2001	प्रतिलाख हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर सहकारी कृषि विपणन केन्द्रो की संख्या 1990 - 91	2000-2001
पश्चिमी	0.07	0.02	37.43	29.29
पूर्वी	0.06	0.02	14.07	20.87
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	0.07	0.02	22.31	22.06

* [25]

	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत		कृषि में लगे मुख्य कर्मकारोंका कुल मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत	
	1981	1991	1981	1991
पश्चिमी	28.17	28.34	69.12	66.42
पूर्वी	28.80	29.53	79.08	77.25
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	29.22	29.63	74.50	74.25

* [26]

	कुल जनसंख्या का कृषि में लगे कर्मकारों से अनुपात		कृषि में लगे मुख्य पुरूष कर्मकारों का कुल मुख्य पुरूष कर्मकारों से प्रतिशत	
	1981	1991	1981	1991
पश्चिमी	5.13	5.31	69.87	66.97
पूर्वी	4.39	4.38	77.94	75.00
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	4.59	4.66	73.68	70.64

* [27]

	सीमान्त कर्मकारों का कुल मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत		कृषकों का मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत	
	1981	1991	1981	1991
पश्चिमी	1.06	4.98	53.77	47.88
पूर्वी	7.48	10.37	59.47	54.76
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	5.11	8.31	58.56	53.27

*** [28]**

	कृषि श्रमिकों का मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत		परिवारिक उद्योग में लगे कर्मकारों का मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत	
	1981	**1991**	**1981**	**1991**
पश्चिमी	15.39	18.54	3.60	2.04
पूर्वी	19.61	22.49	14.74	3.45
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	15.99	20.16	3.69	2.49

*** [29]**

	अन्य कर्मकारों का मुख्य कर्मकारों से प्रतिशत		कुल कर्मकारों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	
	1981	**1991**	**1981**	**1991**
पश्चिमी	27.24	31.54	28.47	29.75
पूर्वी	16.18	19.30	30.95	32.59
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	21.76	25.39	30.72	32.20

*** [30]** प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रूपये)

	प्रचलित भाव पर		**1993-94** के स्थाई भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	1917	4129	2696	2759
पूर्वी	1205	2356	1665	1595
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	1544	3187	2094	2140

* [31] प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रूपये)

	प्रचलित भाव पर		1993-94 के स्थाई भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	2654	5605	3568	3745
पूर्वी	1399	2666	1883	1805
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	1960	3969	2614	2664

प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक तथा पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति कृषि उपज के मूल्य में पूर्वी क्षेत्र व पश्चिमी में दो गुना अन्तर है।

* [32] सकल वस्तु उत्पादन खण्डों से निबल आय में कृषि खंड (पशुपालन सहित) का प्रतिशत

	प्रचलित भाव		1993-94 के स्थाई भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	73.7	38.1	72.2	36.7
पूर्वी	79.0	35.5	77.0	34.4
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	75.6	36.4	73.9	35.1

* [33] प्रति कृषि कर्मी पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रूपये)

प्रचलित भाव पर

	1990 - 91	**1999 - 2000**
पश्चिमी	10101	26892
पूर्वी	5274	13913
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	7204	20189

आर्थिक विकास के साथ देखा जाता है कि सकल उत्पादन में कृषि का योगदान घटता जाता है, प्रदेश में 1990 – 91 की तुलना में 1998 – 99 तक कृषि का भाग आधा रह गया है पर अभी भी प्रदेश के उत्पादन में कृषि का योगदान 35% है। तथा पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति इस सन्दर्भ में समान है।

* समस्त आँकड़े ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक।'' से लिए गये हैं। प्रकाशक – अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उ.प्र.) वर्ष 2002

ख - उद्योगों में

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास की पूर्णतः के लिए औद्योगिक विकास अति आवश्यक है क्योंकि अब वह समय नहीं जब मानव की आवश्यकतायें सीमित थी, यह दौर प्रतिस्पर्धा का है जो खेलों तथा युद्ध से निकलकर अब जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगी है। चाहे अंतरिक्ष में दूर तक जाने की बात हो अथवा रोगों पर विजय पाने की प्रतिस्पर्धा ने मानव जीवन को बहुत लाभ पहुँचाया है। लोगों को भरपेट भोजन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिये जो औद्योगिक विकास से ही सम्भव है कहा जा सकता है "कृषि यदि किसी अर्थव्यवस्था की नीव है तो उद्योग वह इमारत है जिसने मानव जीवन को सुखमय और सुन्दर बनाया है।"

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की स्थिति संतोष जनक नहीं है, 1950 - 51 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 267 के मुकाबले प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 259 रूपये (97%) थी जबकि 10 वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 29382 रूपये के मुकाबले 14834 रूपये (50.49) रह गयी है।[6] देश के तीव्र औद्योगिक विकास की आवश्यकता को देखते हुये 1991 में "उदार आर्थिक नीति" नामक नीतिगत परिवर्तन किया गया। 2005-06 में राष्ट्र की विकास दर 9% तथा 2006 - 07 में 9.4% तक पहुँच गयी पर प्रदेश में यह अब भी 6.1% व 6.9% रही।[7]

वर्तमान स्थिति के विशलेषण के आधार पर पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है –

* [1] प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखाने में लगे व्यक्तियों की संख्या

	1990 - 91	**1998 - 99**
पश्चिमी	718	354
पूर्वी	225	168
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	485	261

*** [2] प्रति श्रमिक आवधित मूल्य (हजार रूपये में)**

	1990 - 91	1998 - 1999
पश्चिमी	85.44	448.69
पूर्वी	185.24	278.32
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	94.13	354.76

वैश्वीकरण के पश्चात् उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घटी है जो कुछ अर्थ व्यवस्था के मशीनीकरण के कारण और कुछ तीव्र जनसंख्या वृद्धी के कारण हुआ है। प्रतिलाख जनसंख्या पर औद्योगिक श्रमिक सबसे कम बुन्देलखण्ड क्षेत्र में है तथा 1990 -91 की तुलना में सबसे ज्यादा रोजगार की कमी इसी क्षेत्र में हुयी है क्योंकि उदार नीति का लाभ इस क्षेत्र को जरा भी नहीं मिल सका है जबकि जनसंख्या लगभग डेढ़ गुनी बढ़ चुकी है।

1990 - 91 की तुलना में 1998 - 99 में प्रतिश्रमिक आवधित मूल्य में पूर्वी क्षेत्र में बहुत कम वृद्धी हुयी है एवं पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धी हुयी है जो यहां अधिक तीव्र मशीनीकरण को दर्शाता है। प्रति श्रमिक आवधित मूल्य सबसे कम बुन्देलखण्ड में मात्र 201.07 हजार रूपये है।

*** [3] प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य हजार रूपये में**

	1990 - 91	1998 - 1999
पश्चिमी	2724	4923
पूर्वी	723	1101
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	1527	2811

* [4] प्रति लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या

	1990 - 91	1998 - 1999
पश्चिमी	9.7	8.9
पूर्वी	2.1	3.7
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	6.2	5.7

निजीकरण के पश्चात् प्रदेश में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धी हुयी है। प्रदेश का समृद्धी का टापू गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में जहां प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन 77422 हजार रूपये है वही चित्रकूट (बुन्देलखण्ड) में मात्र 7000 रूपये जबकि श्रावस्ती (पूर्वी) शून्य औद्योगिक उत्पादन वाला जनपद है।

प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक कारखाने नोएडा में 73.5 हैं जबकि दूसरा नम्बर गाजियाबाद में मात्र 18.9 है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य औद्योगिक जनपद मेरठ (15.5) आगरा (12.0) हैं। केन्द्रीय सम्भाग में औद्योगीकृत जनपद कानपुर नगर (15), लखनऊ (8.6) है। बुन्देलखण्ड में झाँसी (8.7) है तथा पूर्वी सभाग में सर्वाधिक औद्योगिकृत चन्दौली में भी प्रतिलाख जनसंख्या पर मात्र 9.4 कारखाने चालू हालत में हैं।

उत्तर प्रदेश के समस्त वृहद एवं मध्यम उद्योगों का 64.8 प्रतिशत मात्र पश्चिमी सम्भाग में है तथा उदारीकरण के पश्चात् भी इसमें विशेष सुधार नहीं हुआ है दूसरी ओर समान जनसंख्या व क्षेत्रफल के पूर्वी सम्भाग में मात्र 12.6% वृहद एवं मध्यम उद्योग हैं और यही कारण है कि यह क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी सम्भाग में भी नोएडा जनपद में ही 14.9% वृहद व मध्यम उद्योग सिमटे हुये हैं। बुन्देलखण्ड के चित्रकूट व पूर्वी सम्भाग के सिद्धार्थनगर व श्रावस्ती में एक भी वृहद अथवा मध्यम आकार का उद्योग नहीं है।

* [5] उद्योग में उपयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभेग से प्रतिशत / घरेलू उपयोग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत

	उद्योग में उपयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभेग से प्रतिशत		घरेलू उपयोग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत	
	1990 - 91	1999-2000	1990 - 91	1999-2000
पश्चिमी	35.7	19.3	13.4	25.2
पूर्वी	47.8	44.5	10.8	20.0
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	41.4	30.9	14.9	25.3

* [6] प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या / प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक आस्थानों की संख्या

	प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या		प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक आस्थानों की संख्या	
	1990 - 91	2000-01	1990 - 91	2000-01
पश्चिमी	0.08	0.08	0.07	0.14
पूर्वी	0.05	0.04	0.05	0.14
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	0.09	0.08	0.07	0.15

* [7] प्रतिलाख जनसंख्या पर ऋण जमा अनुपात / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या

	प्रतिलाख जनसंख्या पर ऋण जमा अनुपात		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	
	1990 - 91	2000-01	1990 - 91	2000-01
पश्चिमी	50.72	42.17	6.2	5.0
पूर्वी	37.22	22.70	5.5	4.4
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	47.66	28.82	6.3	4.9

* [8] वस्तु उत्पादन खण्डो से कुल निबल आय का प्रतिशत वितरण

प्रचलित भाव पर

1990 - 91

☐ पूर्वी ☐ पश्चिमी ☐ बुन्देल खण्ड ☐ केन्द्रीय
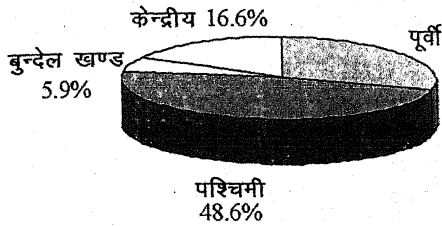
1998-99

☐ पूर्वी ☐ पश्चिमी ☐ बुन्देल खण्ड ☐ केन्द्रीय
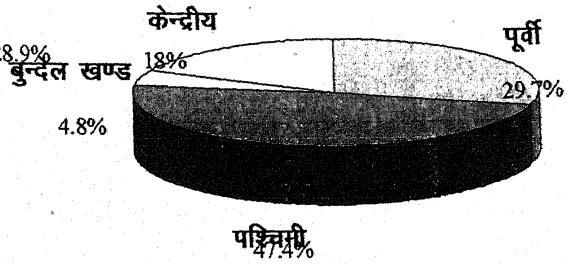
1993 - 94 के स्थाई भाव पर

1993 - 94

☐ पूर्वी ☐ पश्चिमी ☐ बुन्देल खण्ड ☐ केन्द्रीय
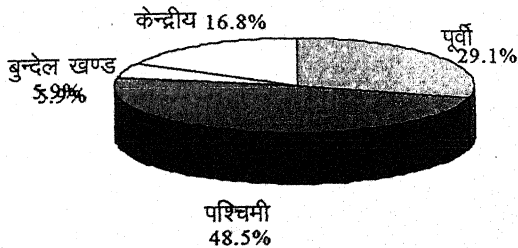
1998-99

☐ पूर्वी ☐ पश्चिमी ☐ बुन्देल खण्ड ☐ केन्द्रीय
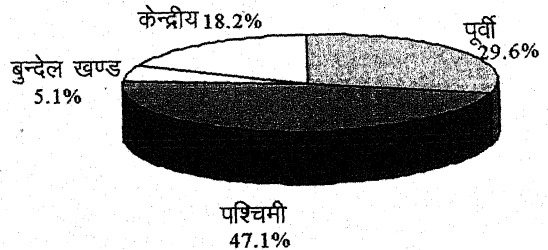
*** [9] सकल वस्तु उत्पादन खण्डों से निबल आय में विनिर्माण खण्ड का प्रतिशत (पंजीकृत)**

	प्रचलित भाव पर		1993 - 94 के स्थायी भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	15.9	11.2	17.4	13.4
पूर्वी	7.6	6.2	9.0	7.5
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	12.3	9.0	14.4	10.7

*** [10] सकल वस्तु उत्पादन खण्डों से निबल आय में विनिर्माण खण्ड का प्रतिशत (अपंजीकृत)**

	प्रचलित भाव पर		1993 - 94 के स्थायी भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	10.3	5.9	9.7	6.2
पूर्वी	11.2	5.9	10.4	6.2
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	10.1	5.7	9.5	6.0

*** [11] वस्तु उत्पादन खण्डों से प्रति व्यक्ति निबल उत्पादन (रू०)**

	प्रचलित भाव पर		1993 - 94 के स्थायी भाव पर	
	1990 - 91	**1998 - 99**	**1993 - 94**	**1998 - 99**
पश्चिमी	2570	11507	3535	7727
पूर्वी	1394	6486	1932	4359
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	1953	9078	2677	6117

*** [12] प्राथमिक क्षेत्र से सृजित आय का कुल निबल घरेलू उत्पादन से प्रतिशत**

	1990 - 91	1998 - 1999
पश्चिमी	73.8	39.6
पूर्वी	81.2	39.4
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	77.6	38.8

*** [13] प्रति व्यक्ति जिला योजना व्यय (रू०)**

	1990 - 91	2000 - 01
पश्चिमी	44	65
पूर्वी	65	70
उत्तर प्रदेश (बु० व के० सहित)	62	71

जिला योजना व्यय सर्वाधिक बुन्देल खण्ड में 94 रू० है, यह क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा हुआ भी है। बुन्देलखण्ड में भी हमीरपुर में प्रति व्यक्ति जिला योजना व्यय सर्वाधिक 160 रू० है।

ग - बाजार तकनीकि

होगी।[10] गरीब देश भारत जहाँ अभी भी एक तिहाई आबादी BPL हो एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इस समय विश्व के 10 सबसे बड़े मॉल में से चीन में अकेले 7 है, और उसकी आर्थिक हालत इतनी बुरी नहीं है, बरहाल इस संदर्भ में भिन्न-भिन्न मत हैं।[11]

भारत में अक्टूबर 2006 में रिलायंस ने 25000 करोड़ की पूंजी के साथ 11 रिटेल स्टोर खोले हैं।[12] सुनील भारती मित्तल की योजना अगस्त 2007 तक पश्चिम बंगाल में रिटेल स्टोर खेलने की है, सम्भव है अन्तर्राष्ट्रीय बालमार्ट उनकी सहयोगी कम्पनी हो।[13] रिटेल स्टोर के खिलाफ विरोध के स्वर भी मुखर हुये हैं, रिलायंस के रांची तथा इंदौर स्टोर पर फुटकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। शोध के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि मॉल संस्कृति सामाजिक बदलाव का संकेत है। विपणन, संग्रहण तथा भण्डारण क्रियाओं में व्यापक पूँजी निवेश से श्रम-उत्पाद अनुपात अत्यधिक बढ़ जायेगा क्योंकि पूँजी K, चर बहुत अधिक प्रयोग किया जायेगा और करोड़ों लोगों का व्यापार सैकड़ों लोगों द्वारा संचालित किया जा सकेगा।

नई बाजार तकनीकि पूँजी गहन है, इकॉनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार वर्तमान स्थिति में भारत में सूची वद्ध 5 लाख रिटेल स्टोर में 96%, 500 वर्गफुट के व्यवसायिक क्षेत्र से संचालित होती हैं[14] तथा एक दुकान पर 12 से 16 व्यक्तियों को रोजगार है। इसके विपरीत वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय दुकान मात्र 4 - 5 व्यक्तियों से संचालित की जा सकती है। मैकेजी की रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत के खुदरा व्यापार[15] में श्रम की उत्पादकता अमेरिका से 6% अधिक है। आज जापान को पीछे छोड़कर भारतीय उपभोक्ता बाजार विश्व में 5वां सबसे बड़ा है पर यह क्रय शक्ति चन्द व्यक्तियों में सिमटी हुयी

है। क्योंकि पूँजीवाद का अर्थ ही 'मैरिटो क्रेसी'' है। भारत 11 धनी देशों के क्लब में शामिल हो चुका है जिनका सकल घरेलू उत्पाद 10 खरब डॉलर से अधिक है।[16] पर उदार आर्थिक नीति की वजह से आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी हुयी है। 2001 - 02 में भारत में 40,000 लखपति, व 20, 000 करोड़पति थे पर मात्र 4 वर्षों में इनमें 60,000 व 33,000 की वृद्धी हुयी। अनुमान है कि भारत में 60 - 70 लाख व्यक्ति लग्जरी वस्तु खरीद सकते हैं।

भारत का खुदरा व्यापार

कुल करोबार - 4 लाख करोड़ रूपये

कुल दुकानों की संख्या - 1.30 करोड़

कुल रोजगार - 4.5 करोड़

राष्ट्रीय आय में योगदान -15%
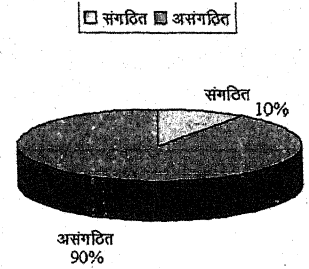
सरकार का मत रिटेल सेक्टर में औद्योगिक घरानों के प्रवेश को लेकर सकारात्मक दिखाई देता है। वर्तमान वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत में भी कहा कि रिटेल में बड़ी कम्पनियों के आने से छोटे दुकानदारों को कोई हानि नहीं है और भारत में शीघ्र ही रिटेल में FDI की अनुमति दी जायेगी।[17] उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी कुछ पहले कृषि उत्पादों के विपणन, भंडारण व ढुलाई के लिये ढँाचागत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही थी। इसके लिए प्रदेश में ''कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964'' तथा कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 1965 (2004 में संशोधित) को नये सिरे से संशोधित किया जायेगा ताकि कान्ट्रेक्ट खेती एवं कृषि उत्पाद को किसी सीमा तक भी क्रय-विक्रय कर सकें।[18]

बाजार के इस बदलते स्वरूप के अलावा उपभोग में वृद्धी के लिए और भी बहुत कुछ किया गया है जैसे – एक समय उद्योगों के लिए कर्ज लेने को बैंको की प्रक्रिया जटिल थी परन्तु अब बैंक बड़ी सहजता से उपभोग के लिए भी कर्ज दे देते हैं यहां तक की सुबह शेव बनाने के लिए ब्लेड तक क्रेडिट कार्ड से खरीदा जा सकता है। ''उपभोक्ता ऋण'' के पीछे यह धारणा कार्य करती है कि हर हाल में उपभोग व्यय को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये, कीन्स ने अपनी "General Theory" में इसी व्यवस्था पर जोर दिया है और फिर अर्थशास्त्र में ''व्यापार की गत्यात्मकता'' को सदैव अच्छा समझा गया है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन चुका है,[19] इस स्थिति के लिए उपभोक्ता ऋणों का बहुत अधिक योगदान है। भारत में कार्यकारी मध्यवर्ग की सबसे बड़ी संख्या है।[20] उम्मीद है कि इसी कारण हमारे यहां और अधिक उत्पादन वृद्धी होगी क्योंकि उत्पाद यहां बिक सकते हैं।

बाजार तकनीकि में तीसरा परिवर्तन सूचना क्रॉंति के रूप में देखा जाता है। कैलाश वाजपेयी एक लेख में लिखते हैं कि मार्क्सवाद का यह हश्र, सूचना क्रॉंति की वजह से हुआ है।[21] सत्य भी है क्योंकि ''उपभोक्ता संस्कृति'' विज्ञापन व प्रचार प्रसार के बिना अधूरी ही है।

घ - अन्य व्यवसाय

उदारीकरण के पश्चात् 16 वर्षों बाद भी पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्पन्नता का अन्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस संदर्भ में टिकल –डाउन का सिद्धान्त कि कुछ लोगों की प्रगति छन कर नीचे आती है गलत साबित होता है। उदार आर्थिक नीतियों का लाभ पूँजीपति वर्ग को अधिक हुआ है तथा आर्थिक असमानता में वृद्धि हुयी है, यह स्थिति क्षेत्रीय असमानता के रूप में भी दिखाई देती हैं उदारीकरण का लाभ शेयर मूल्यों में वृद्धी के रूप में उद्यमियों को प्राप्त हुआ, कुछ उत्पादक केवल शेयरों के मूल्य में वृद्धि के लिए अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन करते हैं जिनका उत्पादन या रोजगार वृद्धि से कतई मतलब नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग और अनुसंधान एजेंसी जे.पी. मोर्गन के अुनसार भारतीय शेयर बाजार के अधिकांश शेयर "ओवर वेल्यूड" हैं। शेयरों की कीमत वास्तविक की अपेक्षा सट्टेबाजी के कारंण अधिक है, शेयर बाजार गुब्बारे की तरह फूला हुआ है जो ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से है जबकि डेबीडेन्ट प्राईज रेशियो अधिक है।[22]

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए.) के सर्वे (2006) के अनुसार उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पाद (3.88%) अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र (29.07%), दिल्ली (11.82%) की तुलना में काफी कम है और इससे भी अधि ाक बात कि प्रदेश की आधे से अधिक औद्योगिक इकाईयां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में सिमटी हुयी हैं इसके विपरीत बुन्देलखण्उ व पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संख्या कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदेश की कुल बीमार इकाईयों (1.35 लाख) में 50,000 है।[23] उत्तर प्रदेश में 32.8% आबादी गरीबी रेखा (B.P.L.) के नीची है, उड़ीसा में 46.4% गरीबी रेखा के नीचे है पर उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या

(B.P.L. से नीचे) सर्वाधिक 5.9 करोड़ है।[24]

दिल्ली की शोधफर्म इंडिकस एनालिटिक्स के अध्ययन के अनुसार प्रदेश की समृद्धि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ में सिमटी हुयी है। जबकि बुन्देलखण्ड के चित्रकूट तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रतिव्यक्ति मासिक आय 1000 रू० से भी कम है। गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में प्रतिव्यक्ति सालाना आय 65000 रू०, सालाना खर्च प्रतिव्यक्ति 43000 रू० तथा बचत 22000 रू० है तथ इंडिकस की रैकिंग के अनुसार यह देश में 16 वें स्थान पर है।[25] यही कारण है कि यहां उपभोक्ता उत्पादों का बाजार 6000 करोड़ रूपये है।, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों की प्रति व्यक्ति सालाना आय 24000 रूपये तथा उससे कम है।[26]

रोजगार की संख्या की दृष्टि से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश समृद्धी के टापू के रूप में उभरा है। रोजगार देने वाले टॉप दस जनपदों में छः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। प्रतिहजार जनसंख्या पर सर्वाधिक रोजगार में गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है तो गाजियाबाद (पश्चिमी उ.प्र.) प्रापर्टी बूम की वजह से विश्व के छः बड़े शहरों में शामिल हो गया है। रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में पांचवां स्थान है, पहला- महाराष्ट्र, दूसरा - तमिलनाडू, तीसरा - वेस्ट बंगाल, चौथा - आन्ध्रप्रदेश है। दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर तथा केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के औरैया तथा मैनपुरी जिलों में सबसे कम रोजगार है। सम्मिलित रूप से भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड रोजगार (प्रति हजार जनसंख्या) की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी पीछे हैं।[27]

पाद टिप्पणी

* समस्त सारणी : ''उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' से ली गयीं हैं, जिसे अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित कराया गया है।

2 व **4** - विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन समूह के महानिदेशक विनोद थॉमस ने भारत में इन्टरव्यू दिया था जो 19 सितम्बर 2007 को अमर उजाला में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनके यह सुझाव थे।

1 व **3** - उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय पत्रिका 2002

5 - दैनिक जागरण में 9 जुलाई 2007 को प्रकाशित मंगलाराय का इन्टरवयू।

6 व **7** - दैनिक जागरण 26 सितम्बर 2007 सद्गुरू शरण का लेख।

8 व **9** - दैनिक जागरण 27 जून 2007 में जोश में प्रकाशित लेख ''रिटेल में अवसरों की भरमार'' से।

10 व **11** - अमर उजाला 4 जुलाई 2007 तीर विजय का लेख।

12 - दैनिक जागरण 3 दिसम्बर 2006 आर्थिक पृष्ठ

13 - अमर उजाला 3 दिसम्बर 2006 आर्थिक पृष्ठ

14 - अमर उजाला 19 मई 2007 प्रताप सोमवंशी का लेख।

15 – अमर उजाला, 3 दिसम्बर 2006, जोसफ बर्नार्ड का लेख।

16 – दैनिक जागरण 16 मई 2007, निरंकार सिंह का लेख।

17 – जी बिजनेस (ई – मीडिया) 27 सितम्बर 2007, सायं 7 बजे

18 – दैनिक जागरण 4 अगस्त 2007

19 व 20 – अमर उजाला 28 सितम्बर 2007, शुभ्र कमल दत्त का लेख।

21 – अमर उजाला 27 सितम्बर 2007, कैलाष वाजपेयी का लेख।

22 – अमर उजाला 3 अप्रैल 2007, आर्थिक पृष्ठ

23 – दैनिक जागरण 1 मार्च 2007, आर्थिक पृष्ठ

24 – योजना आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च 2007 में कहा गया।

25 – इंडिकस एनालेटिक के शोध "स्काईलाइन ऑफ इण्डिया – 2006" के अनुसार।

26 – दैनिक जागरण 26 सितम्बर 2007 की मुख्य पृष्ठ की खबर के अनुसार।

27 –अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्था से जारी आर्थिक गणना 2005 के अनुसार।

षष्टम् अध्याय

भविष्य की सम्भावनाएँ

क - परम्परागत आधार

ख - नवीन तकनीकि

क - परम्परागत आधार पर

स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रवादी तथा सर्वोदयी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का समर्थन किया था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कहा गया कि "लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल काम जुटाते हैं तथा राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं।"[1] इसी प्रकार कर्वे समिति ने आर्थिक विकास की इस युक्ती पर बल देते हुये लिखा कि – "सफल लोकतंत्र के लिए स्व रोजगार का सिद्धान्त कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वशासन का।"[2]

जनांकिक संक्रमण के सिद्धान्त अनुसार उत्तर प्रदेश अभी द्वितीय अवस्था से गुजर रहा है, इसी कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। 1991 से 2001 तक प्रदेश की जनसंख्या में 25 प्रतिशत वृद्धी हुयी। लघु एवं ग्रामीण उद्योग श्रम गहन होने के कारण इसमें कम पूँजी से अधिक रोजगार मिलता है और इस प्रकार आर्थिक विकास में परम्परागत उद्योग अधिक उपयुक्त हैं।

हस्तशिल्प ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग लागत–लाभ की दृष्टि से कुशलता पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। विशेषकर जबकि संशाधनों के कुशलतम प्रयोग की बात हो। धर एवं लार्डडेल का कथन यह है कि "लघु उद्यमों का आर्थिक औचित्य भी होना चाहिये, महत्व का प्रश्न यह है कि दुर्लभ साधनों का प्रयोग किस प्रकार होता है।"[3] आगे कहते हुये उन्होने कहा "सर्वाधिक कुशल पूँजी प्रधान ऐसी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनमें आधुनिक मशीने लगी हो एवं 50 तक श्रमिक कार्य करते हों।[4]"

उत्तर प्रदेश की अधिक जन संख्या एवं परम्परागत उद्योगों में दक्षता को देखते हुये परम्पररागत उद्यमों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की अच्छी सम्भावनायें हैं। इसका एक और प्रमुख कारण है कि हमने सभी सिद्धान्त यूरोपीय सोच व उनके व्यवहार पर आधारित किया है जबकि हमारे देश की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक

व अन्य स्थितियां यूरोपीय परिस्थितियों से अलग हैं और यह सभी तत्व आर्थिक तत्वों को प्रभावित करते हैं इसी कारण यूरोपीय दर्शन व उसका सार तत्व उनके पारिवारिक व आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है और हमारा दर्शन हमको यद्यपि अब हमारी सोच भी उनकी सोच से प्रभावित हो रही है इसी कारण आज हमारा रहन सहन व मनोरंजन व जीवन यापन उससे प्रभावित हो रही है। इस कारण वस्तुइओं की मांग भी उससे प्रभावित है। किन्तु इसका प्रभाव कभी इतना नहीं है कि हमने समग्र रूप से अपने आप को बदल लिया है वरन् अभी भी परम्परागत वस्तुयें व हमारी परम्परागत धरोहर, सोच व चिन्तन हमारे लिए अभी भी आदरणीय हैं अतः "लघु उद्यमों के परिचालन में यदि अधिक लागत आती भी है तो उपरिव्यय में बचत से कुछ हिस्से की क्षतिपूर्ती हो जाती है।"[5]

इस प्रदेश में उपरोक्त उदाहरण के अतिरिक्त सहारनपुर बरेली का लकड़ी का फर्नीचर, मुरादराबाद का पीतल का काम, सम्भल में पशुओं के सींग के शोपीस, अमरोहा के खिलौने, आगरा का जूता उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, फिरोजाबाद का कांच का सामान, भदौही का कालीन, बनारस का साड़ी उद्योग विश्व प्रसिद्ध है।

लागत लाभ दृष्टी से यदि कुटीर उद्योगों को दक्ष करने का प्रयत्न किया जाये तो रोजगार के विकल्प प्रात हो सकते हैं।

सर्वोदयी अर्थशास्त्री गाँधी जी ने लुभावनी लोकोक्ती दी थी – "गाँव का पानी गाँव में"[6] वर्तमान पूरा मॉडल इसी परम्परागत सिद्धान्त का नया रूप है। सर्व प्रथम श्री ए.बी. बाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को 5000 PURA - (Provision of urban Amenities in Rural areas) की घोषणा की।[7] 12 नवम्बर 2005 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आं.आई.टी.) द्वारा इंडिया विजन 2020 एण्ड ग्रोथ सेंटर्स फॉर मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुये

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. कलाम ने कहा कि "पुरा योजनाओं को लागू करके ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।" पुरा एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य जनसंख्या का हस्तान्तरण किये बिना आर्थिक विकास को प्रेरित करना है। इस संदर्भ में स्वर्गीय अर्थशास्त्री प्रो. ए.एम. खुसरों ने कहा था – "विद्यमान आधारभूत ढाँचे की ओर मानव जीवन के गतिमान होने के बजाए यह अच्छा होगा कि गाँवों को अवसंरचना प्रदान की जाये"।[9] क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए यह सिद्धान्त कारगर होगा।

भारत में लघु उद्योगों के लिये आरक्षित वस्तुओं की संख्या उदारीकरण के बाद घटाकर 821 कर दी गयी थी परन्तु नवीं योजना में उल्लेख किया गया "पिछले कुछ वर्षों से लघु उद्योगों में आरक्षित क्षेत्र की अपेक्षा अनारक्षित क्षेत्र का अधिक तीव्रता से विकास हुआ है, इसका अर्थ यह है कि लघु उद्यम अन्तर्निहित क्षमताओं से ही बाजार शक्ति का मुकाबला कर सकता है।"[10]

परम्परागत तरीके से विकास में हाँग–काँग का उदाहरण लिया जा सकता है।" एशिया विकास बैंक द्वारा क्रय शक्ति के आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास का सूचकांक बनाया गया जिसमें हाँग–काँग में प्रतिव्यक्ति सालाना 16,012 डॉलर खर्च आँका गया जो भारत 1202 डॉलर से बहुत अधिक है। हाँग–काँग ने विकास के लिए समग्र प्रयास का परम्परागत तरीका चुना था और वह बहुत आगे है।[11]

निष्कर्ष स्वरूप यदि कहा जाये तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए परम्परागत तरीका अच्छा ही नहीं आवश्यक भी है। वर्तमान में नीति निर्माताओं की सोच ऐसी है कि यदि समस्त भारत में उत्पादन बढ़ा दिया जाये तो समस्याओं का हल खुद व खुद हो जायेगा, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार एवं भरपेट भोजन भी मिल जायेगा

पर मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में मार्च 2004 से मार्च 2007 तक 5,555.30 करोड़ रूपये का निजी निवेश रसायन एवं खाद्य उद्योग में किया जा चुका है।[12] प्रदेश में उदारीकरा के पश्चात् कारखानों तथा उद्योग घन्धों में पर्याप्त वृद्धी हुयी है पर उससे भी ज्यादा उत्पादन में वृद्धी हुयी है। भारत के सन्दर्भ में स्थिति और भी सुखद है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद 10 अरब डॅालर को पार कर चुका है, वाबजूद इसके भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत सुखद नहीं है। भारत में 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 74 प्रतिशत बच्चों में रक्त की कमी है जबकि 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को पूरा पोषण नहीं मिलता।[13] संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन की एशिया प्रशांत मानीवय विकास रिपोर्ट में कहा गया कि उदारीकरण के पूर्व तक जो देश कृषि निर्यातक थे अब अमीर देशों के सब्सिडी प्राप्त उत्पादों के आयातक बन गये हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसका कारण हमारे विकास के सिद्धान्त में कुछ कमी है, हमने अति उत्पादन को ही मानव के आर्थिक कल्याण का सेतु समझ लिया है और यह सिद्धान्त से के बाजार नियम कि ''पूर्ती अपनी माँग स्वयं पैदा कर लेती है''[14] से बहुत अलग नहीं है। से का नियम तो 1929 – 33 की महामंदी के दौरान झुठलाया जा चुका है। जी.डी.पी. बढ़ाने का हमारा वर्तमान सिद्धान्त भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उत्पादन का वर्तमान स्वरूप ''मशीनीकरण'' है मशीनों के द्वारा एक ही व्यक्ति हजारों श्रमिको के बराबर उत्पादन दे सकता है और इसी कारण जी.डी.पी. में वृद्धी के बावजूद आर्थिक कल्याण में वृद्धी नहीं की जा सकी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अधिक घनत्व अधिक मानव श्रम प्रदान करता है ओर अधिक मानव श्रम का कार्यरत होना जहां अधिक रोजगार प्रदान करेगा वही काम की लागत को भी प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश यद्यपि विकास की राह पर है, किन्तु अध्ययन के मध्य जैसा हमने पाया कि इसके कुछ क्षेत्र विकसित हैं तथा कुछ क्षेत्र जो प्रायः पूर्वी क्षेत्र के हैं पिछड़े हुये हैं।

अतः विकास एवं रोजगार दोनों पिछड़े हुये हैं। अतः विकास एवं रोजगार दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुये मानवीय श्रम का प्रयोग उसका उचित सार्थक परिणाम उपलब्ध करवा सकता हैं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सामाजिकता प्रायः परम्परागत है केवल कुछ क्षेत्र जो देहली के आस–पास लगे हुये हैं वहीं अधिक गतिशील है। शेष भाग कुछ कम या अधिक मात्र में परम्परागत हैं यहां तक कि कानपुर जैसा औद्यौगिक नगर व जहां छोटे तथा सभी उद्योग स्थित हैं तथा उ.प्र. की राजधानी लखनऊ भी अत्याधिक सक्रियता के बाद भी अपने परम्परागत सवरूप में दिखाई देती है। यह परम्परा उद्योग सम्बन्धी विशेषता हस्त कौशलता के लिये अत्यधिक उपयोगी है। उदाहरण लखनऊ का जरी का काम एवं वहां के विविध आम बागान एवं मांसाहारी भोजन विश्व भर में प्रसिद्ध है दूसरी ओर कानपुर का कपड़ा उद्योग तथा गरम कपड़ा लाल इमली, धारीवाल, व टाट मिल मंदी और तेजी के साथ अभी जीवित है। किन्तु सुविधाओं के अभाव में अच्छी मिलें जो अपने उत्तम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थीं, बन्द हो रहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी कई कम्पनियां बंद हो गईं। कपड़ा उद्योग फिर भी अभी इस शहर की विशेषता है। इसके अतिरिक्त कत्था उद्योग, काला नमक एवं विशेष रूप से नं. दो रहा चमड़ा उद्योग भी पानी व बिजली व सुरक्षा के अभाव के कारण बहुत मंद हो गए, मंद गति से चल रहा चमड़ा उद्योग अभी भी कानपुर का प्रसिद्ध है।

उपरोक्त प्रकार के उदाहरण के अलावा अपनी क्षेत्रीय विशेषता लिए विभिन्न छोटे व बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं एवं प्रसिद्ध हैं। हस्त कौशल से कम लागत व अधिक लाभ मिलने पर उत्पादन वृद्धि की क्षमता का सिद्धान्त लागू होता है अतः इस प्रदेश में उचित नीति व प्रात्साहन से बन्द उद्योगों के बढ़ने की सम्भावना नहीं है और यह कहा जा सकता है कि विदेशी पूँजी व प्रौद्योगिकी का अत्यधिक स्वागत करने से ही हमारी समस्याओं का हल नहीं है अपितु विकास का परम्परागत तरीका हमारे लिए उपयुक्त है।

ख - नीवन तकनीकि आधारित

यह बात लगभग सर्वमान्य है कि नीवन प्रौद्योगिकी तथा रहन सहन में नवीनता आर्थिक वृद्धि में सहायक होती है। शुम्पीटर के व्यापार चक्रों को तोड़ने के "नव प्रवर्तन" सिद्धान्त को व्यापक स्वीकार्यता मिली।[15] इसी आधार पर उनका अन्य सिद्धान्त आर्थिक वृद्धि का भी था।[16] व्यापार चक्रों के लिए उनका सिद्धान्त निर्विवाद सत्य हो सकता है क्योकि यह विकसित राष्ट्रो की समस्या है जिन्होने विकास के निम्नतम स्तर को पार कर लिया है तथा मजबूत बुनियादी संरचना प्रात है। यदि आर्थिक वृद्धि के सिद्धान्त गरीब राष्ट्रो के संदर्भ में लागू होते हैं तब गरीबी उन्मूलन मुख्य समस्या है जहाँ "नव प्रवर्तन" निर्णायक नहीं पर समर्थित (Support-ive) अवश्य होते हैं।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए समग्र आर्थिक वृद्धि की संकल्पना दी जाती है, यह अप्रत्यक्ष रीति है। भारत ही नहीं दुनिया में भी इस समय गरीबी उन्मूलन के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीका वाली पद्धति पर बहस चल रही है।[17] रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान के अनुसार "ऐतिहासिक अनुभव यह है कि 7 से 8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि वाला घोर से घोर गरीब देष भी 20 से 25 वर्षों में अपनी गरीबी हटा सकता है।"[18] क्रमिक गुणन प्रभाव के चलते यह सत्य भी लगता है क्योंकि यदि भारत की आर्थिक वृद्धि आठवें दशक की दर 2% रही तो प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दर 3.5 रहेगी, यानी 2020 तक प्रतिव्यक्ति आय 700 डॉलर होगी पर यदि आर्थिक वृद्धि उदारीकरण के बाद की 7 से 8% बनी रहे तब 2020 में प्रतिव्यक्ति आय 1200 डॉलर हो सकती है, लगभग दो गुनी। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत में गरीबी अथवा असंतुलन की कोई समस्या नहीं होगी।

दूसरी ओर आर्थिक असंतुलन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रत्यक्ष तरीकों का

विचार है जिसमें सार्वजनिक निर्माण में रोजगार देकर, खाद्य एवं अन्य सार्वजनिक सेवायें देकर गरीबी को तीव्र तथा प्रभावकारी ढंग से मिटाया जाता है। उदारीकरण से पूर्व तक भारत में यही नीतियां प्रभावी थीं, जिसके दो स्तंभ थे – संरक्षण तथा सार्वजनिक क्षेत्र। गरीबी उन्मूलन की प्रत्यक्ष नीति सरकार के वित्तीय स्थिति पर निर्भर है, सार्वजनिक क्षेत्र के बुरे निष्पादन तथा संरक्षण के कारण कम राजस्व के चलते सरकार को सामाजिक सेवाओं को चलाना असम्भव होने लगा। इसी कारण इसके विकल्प पर विचार किया गया और निजीकरण उसके क्रियान्वयन व परिणाम पर विचार किया जाने लगा। इधर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय थी। अतः इन दोनों प्रकार के परिवर्तन के लिये हम भी चिन्तन कर रहे थे और 1991में वैश्वीकरण को हमने स्वीकार किया जिसमें उदारीकरण व निजीकरण दोनों उपकरण शामिल थे इस प्रकार वैश्वीकरण के चलते हुये यह माना गया कि गरीबी उन्मूलन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नीति का अन्तर काल्पनिक है क्योंकि जब आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी तभी सरकार की सामाजिक सेवाओं पर खर्च वहन की क्षमता में भी वृद्धि होगी और इस कारण आर्थिक वृद्धि को मुख्य माना गया। सतत् आर्थिक वृद्धि के लिए उदारीकरण नीति से जन्मा "नव प्रवर्तन" काफी कारगर है। नित नयी तकनीकि तथा पूँजी की उपलब्धता, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में मंदी नहीं आने देती तथा प्रत्येक उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक क्रियाओं की "क्रिया–प्रतिक्रिया" के फलस्वरूप रोजगार वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि में सहायता मिल रही है। मानसून के कारण भारत क जी.डी.पी. में आने वाले उच्चावचनों में कमी आयी है क्योंकि कृषि पर हमारी निर्भरता कम हुयी है।[19] आज नवीन तकनीकि के आधार पर भारत में उत्पादन वृद्धि की नहीं बल्की अति उत्पादन (ओवर हीटिंग)[20] की समस्या है जो यकायक उत्पादन बढ़ने के कारण सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत है। किन्तु उपरोक्त

सिद्धान्त को अपने दृष्टिकोंण से दृष्टिगत करते हुये हमें गरीबी रेखा से नीचे और देश के थोड़े से अरबपति व्यक्ति, जिनके पास देश की पूँजी का अधिक हिस्सा है उन दोनों के मध्य के अन्तर के लिये किन सिद्धान्तों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ऐसा भी हमें विचार करना होगा। ऐसा अर्थशास्त्रियों का मत है। नवीन तकनीकि के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत में आर्थिक वृद्धि की अच्छी सम्भावना है तथा इससे क्षेत्रीय असंतुलन एवं गरीबी की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया की खामियों को उचित आर्थिक नीतियों द्वारा दूर किया जाना चहिये क्योंकि उ.प्र. के साथ अधिक जनसंख्या, धन के असमान वितरण तथा खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय समस्याएँ भी हैं।[21]

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि नव प्रवर्तन तथा नवीन तकनीकि आखिर कब तक चलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राद्यापक आलोक पुराणिक जी लिखते है कि "ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाजार लगातार बढ़ता ही चला जाये।"[22] और जब नव प्रवर्तन थमता है तो यह भयानक बेरोजगीर, असुरक्षा एवं अव्यवस्था को जन्म देता है, इससे अच्छा तो पुरातन भारतीय चिन्तन है जो आवश्यकताओं को सीमित रखने की हिमायत करता है, इस व्यवस्था में व्यापार में उच्चावचन कम रहते है और धीमी मगर स्थाई वृद्धि मानवीय जीवन में होती रहती है। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि भले ही भारतीय चिन्तन में आवश्यकतायें सीमित रखने की बात कही गयी थी परन्तु हमारा तकनीकि ज्ञान तथा उसे अर्जित करने की गति बिल्कुल कम नहीं थी। पाइथागोरस की प्रमेय बहुत पहले से हम यज्ञ वेदियों में प्रयोग करते आये हैं। "कैप्लर" के अंतरिक्ष नियमों से आर्य भट्ट बहुत पहले से परिचित थे। रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रमाण वेदों तथा पुराणों में मिलते हैं, यहां तक की "टीपू सुल्तान" के समय तक भी विश्व में अन्यन्त्र कहीं भी रॉकेट का प्रयोग नहीं किया गया था और यह बात मानने को पश्चिमी विचारक भी मजबूर हैं।

कहने का तात्पर्य कि मानवीय ज्ञान व कल्याण में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं कि पूँजीवादी स्वरूप को स्वीकार किया जाये यह कार्य समाजवादी व राष्ट्रवादी स्वरूप से और अच्छे ढ़ंग से हो सकता है यहाँ तक कि पहला उपग्रह छोड़ने का श्रेय भी घोर कम्यूनिस्ट सोवियत रूस को "स्पूतनिक-1" के लिए दिया जाता है। भारत की वैज्ञानिक उन्नति जिस समय चरमोत्कर्ष पर थी पूँजीवाद कहीं नहीं था, जितने भी वैज्ञानिक थे वह राजकीय सहायता से कार्य करते थे और शोध के निष्कर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति का हक था यही कारण रहा कि वैज्ञानिक उपलब्धी का श्रेय वैज्ञानिकों को तो नहीं मिल पाया पर वह निसंदेह अधिक लोक कल्याणकारी रही। पूँजीवादी देश अमेरिका को यदि किसी वैज्ञानिक उपलब्धी का श्रेय है तो वह एटोमिक बम है जिसने लाखों लोगों का जीवन समाप्त किया है। कहने का तात्पर्य नव प्रवर्तन या नवीन तकनीकि के लिए "उदारीकरण" रूपी पूँजीवादी नीतियों का पक्ष लेना नितांत गलत होगा। क्योंकि इतिहास भी यही बताता है तथा वर्तमान नीतियों का सूक्ष्म विश्लेषण भी यही बताता है।

आज यदि पूँजीवादी नीतियों के संरक्षण मे "एड्स" या "कैंसर" जैसी भयानक बीमारियों का इलाज खोज भी लिया जाता है तो पेटेंट व "बौद्धिक सम्पदा संरक्षण" कानूनों के कारण इनकी कीमत इतनी अधिक होगी कि यह आम आदमियों के पहुँच में नहीं होगी तब इससे कैसा कल्याण? पुराने पेटेन्ट कानून में प्रावधान था कि यदि कोई वस्तु बनायी गयी है तो दोबारा उसी विधि से वह वस्तु "खोजकर्ता" की स्वीकृति से ही बनायी जा सकती है परन्तु वर्तमान TRIPS समझौता इतना सख्त है कि वह वस्तु दूसरी विधि से भी "खोजकर्ता" की स्वीकृति के बिना नहीं बनायी जा सकती।[23]

नव प्रवर्तन तथा नीवन तकनीकि आर्थिक विकास में सहायक है इस

सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं परन्तु उदारीकरण से निर्मित पूँजीवाद में नव प्रवर्तन "बन्दर के हाथ में उस्तरे" के समान खतरनाक है। अध्ययन के मध्य निकले निष्कर्ष के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि मानव की किसी भी खोज के लाभ संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिये चाहे उस खोज में उसका कोई हाथ हो अथवा न हो, मानव की प्रत्येक खोज पर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर हक है और यही आर्थिक कल्याण की सही परिभाषा भी है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं बनायी जा सकती है जिसमें तेज दौड़ने वाले को तो जीने का हक हो परन्तु धीमे चलने वाले को जीने भी न दिया जाये। प्राचीन भारतीय समाज में ऐसी ही व्यवस्था थी, खोजकर्ता को भरपूर सम्मान, ईनाम व सुविधायें तो दी जाती थीं पर खोज पर अमीर व गरीब का समान हक था। यह बात सही है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में अविष्कारों की गति में तेजी आयी है, जो काम 10 वर्षो में होता उतनी तरक्की दो वर्षों में ही हो जाती है परन्तु इसी कारण व्यापार में मंदी व तेजी के रूप में हमारी समस्यायें व चिन्तायें भी बढ़ी हैं। अमीर व्यक्ति तेजी से उपभोग के संसाधनों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। जबकि गरीब और अधिक पिछड़ता चला जा रहा है।

आर्थिक विकास के लिए नव प्रवर्तन व नवीन तकनीकि निश्चय ही आवश्यक है और जिस तरह से भारतीय मेधा उभर कर आयी है भविष्य के लिए हमारी सम्भावनायें बहुत अच्छी है परन्तु समग्र सामाजिक कल्याण के लिए पूँजीवाद के वर्तमान ढाँचे को बदलने की जरूरत है ताकि विकास के लाभ में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके।

पाद टिप्पणी

1. Planning commission, second five year plan, P - 47
2. Report of the Village and small scale industries committee (1955), P - 45

3 & 4. Dhar and Lydall, The role of smart interprises in India economic developement, P - 11 & 19

5. भारतीय अर्थव्यवस्था (एस. चन्द्र), पृष्ठ – 571
6. आर्थिक विचारों का इतिहास – चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी (साहित्य भवन)
7. प्रतियोगिता दर्पण – मई 2006, पृष्ठ – 1821

8 व 9. प्रतियोगिता दर्पण – मई 2006, पृष्ठ – 1819

10. Planning Commission 9th five year plan
11. अमर उजाला 2 अगस्त 07 (सम्पादकीय)
12. मायावती (मुख्यमंत्री) द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 16 जुलाई 2007
13. दैनिक जागरण 16 मई 2007, निरंकार सिंह के लेख से।
14. मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, एम.एल. झिंगन, पृष्ठ – 315

15-16. उपकार अर्थशास्त्र (नेट, स्लेट) – डॉ. अनुपम अग्रवाल

17. World development, Voll. - 16, 1988 में इस सन्दर्भ में जगदीश भागवती का लेख "Poverty and public pollice" भी प्रकाशित है।
18. भारत की अर्थनीति – 21 वीं सदी की ओर – विमला जालान, पृष्ठ – 15
19. 1950–51 में कृषि का जी.डी.पी. में योगदान 59.1 प्रतिशत था जो 2002–03 तक 22 प्रतिशत हो गया (भारतीय अर्थव्यवस्था. – एस. चन्द्र)
20. योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोनटेक अहलूवालिया मानते हैं जून 2006 में भारत में ओवर हीटिंग की समस्या थी। (22 जुलाई 2007 में इन्टरव्यू में कहा)
21. उत्तर प्रदेश में 1999–2000 में 31.15 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। (योजना आयोग भारत सरकार की साईट)
22. अमर उजाला, 29 सितम्बर 2007 – आलोक पुराणिक
23. मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

सप्तम् अध्याय
निष्कर्ष

(I)

संघीय राज्य (Federal State) भारत के कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से अग्रगामी (Advanced) हैं तो कुछ पिछड़े हुये। क्षेत्रीय असंतुलन अन्तः राज्यीय (Inter state) भी है और राज्य अन्तर (Intra state) भी। जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव कृषि पर अत्यधिक विद्यमानता, कृषि व कुटीर उद्योगों में निम्न उत्पादकता आदि आर्थिक पिछड़ेपन के सूचक हैं।

भारत के छः राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा को पिछड़े राज्यों की सूची में रखा जाता है, 1991 की जनगणना के अनुसार यहां राष्ट्र की 46 प्रतिशत आबादी है।

(उत्तर प्रदेश की अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति)

1. [1]साधन लागत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(1993–94 की कीमत पर)

स्थिति (वर्तमान)	राज्य	1990–91	2000–01	1990–91 से 2000–01 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर
I'st	पंजाब	11779	15390	2.7
15'th	बिहार	4476	3345	– 2.8
13'th	उत्तर प्रदेश	5342	5770	0.8
8'th	अखिल भारत	7321	10254	3.4

उदारीकरण के पूर्व 1980–81 व 1990–91 के मध्य अग्रगामी Developed) राज्यों की वार्षिक वृद्धी दर 5.2 प्रतिशत थी, जो उदारीकरण के पश्चात् 1990–91

व 1997–98 के मध्य 6.3: हो गयी जबकि पिछड़े राज्यों में समान वर्षों में वार्षिक वृद्धि की दर 4.9 प्रतिशत से मात्र 3 प्रतिशत रह गयी है जो उदारीकरण के बुरे पक्ष को प्रदर्शित करता है।

योजना आयोग के डॉ. जे.जे. कुरियन ने माना है कि उदारीकरण के पश्चात् विनियोग प्रस्तावों (Investment) का संकेद्रण 2/3 यानी 69.2 प्रतिशत Developed region की ओर रहा।[2] अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आई.सी.आई.सी.आई. भारतीय इकाई न्यास, एल.आई.सी., सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भी 31 मार्च 1997 तक 67.3 प्रतिशत अग्रगामी राज्यों को वितरित किया।

(2) [4]राजकीय शुद्ध घरेलू उत्पाद की स्थिति

1980 – 81 की कीमत पर

स्थिति (वर्तमान)	राज्य	करोड़ रूपये			औसत वार्षिक वृद्धि दर	
		1980–81	1990–91	1997–98	1980–81 से 1990–91	1997–98 से 1990–91
I'st	महाराष्ट्र	15163	27244	42932	5.3	4.4
15'th	असम	2298	3426	4302	4.1	3.3
2'nd	उत्तर प्रदेश	14012	22780	27365	5.0	2.6

उत्पादन में उत्तर प्रदेश की अच्छी स्थिति अधिक जनसंख्या के कारण है तथा इसे उत्पादन दक्षता नहीं कहा जा सकता।

आधार संरचना के आधार पर भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ राज्य है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार संरचना की बहुत आवश्यकता है। सी.एम. आई.ई. ने विभिन्न सुविधाओं के आर्थिक विकास में योगदान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है [5] :–

(i) परिवहन सुविधाएँ 26%

(ii) ऊर्जा उपभोग 24%

(iii) सिंचाई सुविधाएँ 20%

(iv) बैंकिंग सुविधाएँ 12%

(v) संचार 6%

(vi) शिक्षा सुविधाएँ 6%

(vii) स्वास्थ्य सुविधाएँ 6%

3 – आधार संरचना में उत्तर प्रदेश की स्थिति

राज्य	प्रतिव्यक्ति पावर उपभोग	प्रति 1000 व्यक्ति गाड़ियों की संख्या 31/03/97	प्रति 1000 व्यक्ति टेलीफोन लाईन मार्च 31, 99	सिंचित कृषि का प्रतिशत 1994–95	सापेक्ष आधार संरचना सूचकांक
पंजाब	790	103.2	5.34	94.8	191.4
असम	108	19.9	0.95	15.0	78.9
उत्तर प्रदेश	194	22.7	1.21	62.6	103.3
भारत	338	44.0	2.55	36.5	100

जे. जे. कुरियन आर्थिक सुधारों के पश्चात् क्षेत्रीय असमानता के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे थे[6] :–

1. 1980 के दशक के आरम्भ में निजीक्षेत्र को प्रोत्साहन के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धी हुयी है तथा 1991 के बाद के आर्थिक सुधार जिनमें स्थिरीकरण और विनियमन प्रधान उपकरण है तथा जिनमें निजीक्षेत्र को महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है अन्ततः राज्यीय असमानता को और बढ़ा दिया है।

2. समृद्ध राज्य अपनी विकास सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में निजी विनयोग

को आकर्षित कर सके हैं क्योंकि इनके अनुकूल वहां वातावरण है जिसमें बेहतर समाजार्थिक संरचना भी शामिल है दूसरी ओर पिछड़े राज्य ऐसा नहीं कर सके हैं क्योंकि उनमें प्रतिकूल विनयोग वातावरण तथा घटिया आधार संरचना विद्यमान है।

प्रतिव्यक्ति तथा कारखानों में कार्यरत व्यक्ति व उत्पादन की दृष्टि से शोध के मध्य भी ऐसा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 1991 की तुलना में 2003 तक प्रदेश की स्थिति राष्ट्र में और अधिक पिछड़ गयी और इसका कारण नई नीतियों का नियोजित न होना था।

वैश्विक असमानता समझ में आने वाली स्थिति है क्योंकि कोई भी देश अपने लाभ को दूसरे देशों के साथ सहभागी नहीं करेगा। राजनैतिक व सामाजिक कारण हैं जिनके कारण आर्थिक सीमायें बंटी हुयी हैं और इसी कारण धनी देशों की अमीरी, सर्व समाज के लिए कल्याणकारी नहीं बन सकी हैं बुडरो विल्सन लिखते हैं कि "यह हकीकत है कि हम एक महान किन्तु हृदयहीन अर्थव्यवस्था से जकड़े हुये हैं।"[7]

दूसरी ओर क्षेत्रीय असमानता का कोई कारण नहीं है तथा उचित नियोजन के द्वारा उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। अन्तर्देशीय असमानता, अन्तर्क्षेत्रीय असमानता से निम्न कारणों से भिन्न है :–

1. देशों के मध्य श्रम, प्रौद्योगिकी तथा पूँजी स्वतंत्र हस्तातरणीय नहीं है जबकि दो क्षेत्रों के मध्य इन्हें कुशलता से समायोजित किया जा सकता है।

2. देशों के मध्य निर्णय लेने वाली संस्थाएँ अलग–अलग हैं तथा उनकी आर्थिक नीतियाँ भिन्न–भिन्न हैं इसके विपरीत दो क्षेत्रों के मध्य नीति सम्बन्धी एकरूपता है। इसी के साथ राजनैतिक व सामाजिक एकरूपता भी हैं।

3. दो क्षेत्रों के मध्य आर्थिक असमानताएँ सामाजिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी घातक हैं तथा इन्हें दूर किया जाना चाहिये।

(II)

प्रस्तुत शोध ''पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य आर्थिक विश्लेषण'' किया गया जिसके पश्चात् देखा गया कि दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं है तथा अध्ययन के मध्य यह विदित होता है कि उदारीकरण के पश्चात् इनकी असमानता में और अधिक वृद्धि हुयी है। दोनों क्षेत्रों के मध्य निम्नलिखित तुलनात्मक विश्लेषण देखा गया –

1. जनांकिकी :– दोनों क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या व क्षेत्रफल लगभग समान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 1.1 प्रतिशत अधिक है। शोध से स्पष्ट हुआ कि पूर्वी की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में दो गुना शहरीकरण हुआ तथा पूर्वी क्षेत्र की विपन्नता का एक कारण यह भी है कि यहां अनुसूतिच जातियों व जनजातियों की आबादी 42.3 प्रतिशत है जिन्हें निजीकरण की नीति के कारण लाभान्वित नहीं किया जा सका।

2. शिक्षा व स्वास्थ्य :– शिक्षा व स्वास्थ्य मानवीय विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचकांक है, इन सूचकांक की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र में साक्षरता अधिक है और माना जाता है कि स्त्री साक्षरता सम्पन्नता में अधिक प्रभाव डालती है क्योंकि वह परिवार को अधिक प्रभावित करती है। पश्चिमी क्षेत्र में स्त्री साक्षरता 4.9 प्रतिशत अधिक है तथा यहां प्रतिलाख जनसंख्या पर जूनियर व सीनियर विद्यालयों की संख्या भी अधिक हैं निजीकरण की लहर के पश्चात् देखा गया कि निजी स्कूलों व नर्सिंगहोम की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुयी परन्तु इनका रूझान प्रदेश के सम्पन्न शहरों की ओर अधिक रहा क्योंकि इन्हें यहां अधिक आर्थिक लाभ था, यही कारण रहा कि उदारीकरण के पश्चात् इन क्षेत्रों का अन्तर अधिक बढ़ गया।

3. आधार संरचना :— पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लम्बाई तथा प्रति हजार वर्ग कि.मी. पर सड़क की लम्बाई अधिक है। (बुन्देलखण्ड में प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़क की लम्बाई सर्वाधिक है पर प्रति हजार वर्ग कि.मी. पर सड़क की लम्बाई सर्व न्यून है)

4. ऊर्जा एवं अवस्थापन :— डॉकघरों व तारघरों की संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक है परन्तु निजी निवेश के कारण कुरियर, इन्टरनेट, मोबाईल आदि आधुनिक संचार सुविधाओं का विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक देखा गया। निजीकरण की यही एक कमी देखी जाती है कि इनका झुकाव गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ की ओर अधिक रहा। पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत का उपभोग पूर्वी की तुलना में 39.5 यूनिट अधिक है।

पश्चिमी क्षेत्र में 42.8 प्रतिशत विद्युत कृषि कार्य में प्रयुक्त की जाती है, बागपत (पश्चिम) में 88.3 प्रतिशत विद्युत कृषि कार्य में प्रयुक्त है तथा पश्चिम के 87 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं। पश्चिम के 6 जिले पूर्णतः विद्युतीकृत है जबकि पूर्वी क्षेत्र का एक मात्र जिला पूर्ण विद्युतीकृत है।

5. कृषि :— पश्चिमी क्षेत्र की कृषि अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक एवं परिमाणात्मक रूप से भी अधिक है, शोध के माध्यम से इसके निम्नलिखित कारण देखे गये हैं :—

अ — पश्चिमी क्षेत्र की 88 प्रतिशत कृषि सिंचित है।

ब — इस क्षेत्र में बाढ़ व सूखे का प्रभाव कम है।

स — इस क्षेत्र में बढ़े आकार के खेतों की संख्या अधिक है व औसत आकार भी अधिक है।

द — नाईट्रोजन, फास्फेट, नाईट्रेड आदि उर्वरकों का प्रयोग इस क्षेत्र में अधिक किया गया।

इ – पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक क्षेत्र पर कृषि की गई (कृषि योग्य भूमि का 90.96 प्रतिशत बोया गया)

फ – पश्चिमी क्षेत्र की कृषि की तुलना में 1.439 गुना अधिक दक्ष है।

शोध के मध्य पूर्वी क्षेत्र की कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण प्राप्त हुये –

अ – पूर्वी क्षेत्र की 74.1 प्रतिशत कृषि सिंचित है।

ब – पूर्वी क्षेत्र की 4.02 प्रतिशत जनसंख्या तथा 6 प्रतिशत कृषि बाढ़ से प्रभावित है।

स – इस क्षेत्र में 44.8 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम आकार के खेतों में बँटी हुयी है।

द – प्रति हेक्टेयर उर्वरक वितरण इस क्षेत्र में 123.64 कि.ग्रा. है, जो पश्चिम की तुलना में कम है।

इ – पूर्वी क्षेत्र की 85.62 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की बुबाई की गई और इस तरह कृषि का रकबा कम है।

फ – पूर्वी क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 21.18 कुन्टल है जो पश्चिम की तुलना में कम है।

विचारणीय समय में उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वार्षिक वृद्धिदर 3 प्रतिशत रही जबकि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर भी 2.57 प्रतिशत थी।

6. श्रम :– पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य कर्मकारों से कृषि कर्मकारों का प्रतिशत पश्चिमी की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है एवं पंजीकृत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या पश्चिमी क्षेत्र में दो गुनी है, यह भी पूर्वी क्षेत्र की पिछड़ी हुयी स्थिति को प्रकट करता है।

7. उद्योग :– कृषि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक अच्छी स्थिति प्रकृति

प्रदत्त एवं मानवीय दोनों प्रकार से थी एवं उद्योगों में पश्चिमी क्षेत्र की अच्छी स्थिति पूर्णतः मानवीय है। शोध से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुआ :–

अ – तुलनात्मक प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में उदारीकरण के पूर्व 3.76 गुना था। जो उदारीकरण के पश्चात् 4.47 गुना हो गया।

ब – प्रति लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या पश्चिमी क्षेत्र में 2.76 गुना आधिक है।

स – वृहद एवं मध्य श्रेणी के प्रदेश के कुल उद्योगों का 64.8 प्रतिशत पश्चिमी क्षेत्र में है तथा इनमें भी अधिसंख्य केवल नोएडा एवं गाजियाबाद में हैं।

शोध के पश्चात् पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य उदारीकरण के कारण असमानता में वृद्धि के निम्नलिखित कारण देखे गये :–

1. विकसित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ अधिक है और निजी निवेश इनका लाभ उठाना चाहता है।
2. विभिन्न उद्योगों की परस्पर निर्भरता तथा सह अस्तित्व की सुरक्षा के कारण भी निजी निवेश एक ही स्थान पर केन्द्रित हुआ है।
3. कुछ उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ती की दृष्टि से भी विकसित क्षेत्रों में निवेश लाभदायक होता है।
4. समृद्ध क्षेत्र के प्रशासकों एवं नेतृत्व की भी तारीफ करनी होगी कि उनकी दूरदर्शिता तथा उत्पादक इकाईयों को सुविधायें देने के कारण भी उनके क्षेत्र का विकास हुआ है जैसे कि कर्नाटक के बैंगलौर व आंध्र प्रदेश के हैदराबाद का विकास सुनियोजित था।
5. पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जनप्रतिनिधि की कार्य कुशलता भी जिम्मेदार है उदाहरण के लिए झाँसी जनपद के लिए प्रस्तावित रेल कारखाना देखते ही

देखते भीमसेन स्थानान्तरित हो गया है।

असमानता में वृद्धि का कारण निजी लाभ है क्योंकि निजी निवेश ने विज्ञान के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के समान हर आर्थिक क्रिया को प्रभावित किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां प्रत्येक व्यवसाय में लगा व्यक्ति पिछड़े क्षेत्रों के समान व्यवसाईयों से अधिक आय अर्जित करता है और सरल शब्दों में "विकसित क्षेत्र के समान योगयता के व्यक्ति को अविकसित क्षेत्र के व्यक्ति की तुलना में अधिक आय प्राप्त होती है।" उदारीकरण रूपी पूँजीवाद से असमानता की खाई चौड़ी हुयी है इस सम्बन्ध में कैलाश बाजपेयी (साहित्यकार) बहुत अच्छा लिखते हैं "स्टालिन के समय रूस में जो कुछ भी विशिष्ट था वह के.जी.बी. पोलित ब्यूरो या सेना के लिए था उसी तरह जिस तरह आज दिल्ली के 75 प्रतिशत संसाधनों को नौकरशाह, नेता तथा चंद उद्योगपति कब्जाये हुये हैं।"

आज पूर्वी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहां हिंडाल्को को छोड़कर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। कृषि वैज्ञानिक गंगा व यमुना के दोआब की मिट्टी सर्वाधिक कृषि अनुकूल मानते है फिर भी यहां उत्पादकता कम है क्योंकि बाढ़ व सूखे पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र के मध्य आर्थिक सम्पन्नता का अंतर आजादी के समय से ही है। 45 वर्ष पूर्व गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ने जब संसद में कहा कि पूर्वांचल में लोग गोबर में से गेंहूँ बीनकर खाने को मजबूर हैं तो देश का ध्यान इस ओर गया। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तब पूर्वी क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए एवं उसके निराकरण के लिए "पटेल आयोग" का गठन किया परन्तु चीन से युद्ध छिड़ जाने के कारण इसे ठंडे वस्ते में डालना पढ़ा।[9] 1962 में योजना आयोग ने प्रदेश को पांच जोन में बांटने के बाद पाया कि कुद क्षेत्र विकसित व कुछ अविकसित हैं पर इससे अधिक कुछ न किया जा सका।

बेरोजगारी अविकसित क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। किसी अर्थव्यवस्था की लोचशीलता का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि वह किस गति से संघर्षी बेरोजगारी को समाप्त करती है।[10] अल्प विकसित उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी तो ग्रामीण क्षेत्रों में अल्परोजगार तथा अदृश्य बेरोजगारी की दशा सोचनीय है।

पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक अध्ययन में प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रों के ''सामाजिक ढँाचे'' ने भी बेरोजगारी में अन्तर पैदा किया है। पश्चिमी क्षेत्र के नागरिक "Work is worship" की धारणा पर चलते हुये बेरोजगारी की स्थिति में लघु व कुटीर उद्योगों तथा हैण्डीक्राफ्ट (हस्त शिल्प) को महत्व देते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में इस सामाजिक चेतना का आभाव है। पश्चिमी क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का फैलाव इसी तथ्य को बल देता है जबकि बुन्देलखण्ड व पूर्वी क्षेत्र में पनपी रूढ़ीवादिता तथा सामाजिक बुराई यथा जुआ, सट्टा, मद्यपान का अधिक उपभोग भी इसी तर्क का पुष्ट करता है। सामाजिक सुधार को आर्थिक विकास से सम्बद्ध किया जाता है अर्थात् आर्थिक विकास होने तथा शिक्षा का स्तर बढ़ने से स्वतः यह बुराईयां कम होती हैं पर यह कारण भी है और परिणाम भी। सामाजिक चेतना तथा विकास ''उत्तर प्रति उत्तर'' के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

पूर्वी क्षेत्र की विकास में असफलता, विभिन्न घटकों के सम्मिश्रण का परिणाम है और इसे भाग्य भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि समता का सिद्धान्त यही है कि ''कमजोर को सहायता'' इस समाजवादी विचार का जनक यद्यपि ''कार्ल मार्क्स'' को समझा जाता है तथापि आज से 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम अग्रोहा नरेश अग्रसेन ने ''एक ईंट एक मुद्रा'' का नियम अपना कर सोशल

इंजीनियरिंग को लागू किया था जिसके तहत राज्य के सभी व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को एक ईंट व एक मद्रा दान दिया करते थे। जिससे कि व्यक्ति निवास बना सके व व्यापार प्रारम्भ कर सके। अर्थात् वह पराश्रित की अपेक्षा स्वाबलम्बी बनाने पर जोर देते थे। कहने का तात्पर्य यदि हम समस्याओं का हल देशी नीतियों में तलाशें तब भी हमारी समस्याओं का समाधार सम्भव है।

पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं :–

1. बैंकिग संस्थानों को विकसित व अविकसित क्षेत्र में आनुपातिक रूप से उपभोक्ता व उत्पादक ऋणाों को बांटने के लिए नीति बनानी होगी।
2. विदेशी निवेशकों को केवल विकसित क्षेत्रों में ही नहीं अपितु अविकसित क्षेत्रों में भी कुछ न कुछ शाखाएँ खोलने को विवस किया जा सकता है।
3. समस्त अविकसित क्षेत्रों के लिए उप विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेमी–सेज) की नीति कारगर हो सकती है।
4. अविकसित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए अलग से ''हरित क्रान्ति'' की तरह कोई नीति बनानी होगी।
5. आज भले ही निजीकरण की नीति अपनायी गई है परन्तु बचे हुये सार्वजनिक उपक्रमों के नये निवेश राजनैतिक हित के अनुकूल न होकर वास्तविक पिछड़े क्षेत्रों में होने चाहिये।
6. इस समय सरकार विकसित क्षेत्रों में ढँाचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास की नीति पर चल रही है परन्तु अविकसित क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष निवेश आवश्यक है क्योंकि अविकसित क्षेत्रों में भले ही सड़क बिजली, हवाई अड्डे इत्यादि बनवा दिये जाये पर निजी निवेश इन क्षेत्रों में जाने को उत्सुक नहीं है।

7. यदि हम चाहते हैं कि कुछ लोगों की सम्पन्नता छनकर नीचे जाये (टिकल टाउन सिद्धान्त) तो हमें सख्ती से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा अन्यथा विदेशी निवेश की सारी राशि चन्द व्यक्तियों के हाथों में चली जायेगी और भरपाई प्रत्येक नागरिक को करनी होगी।

8. वर्तमान आर्थिक नीतियों की सफलता के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है।

L.P.G. नीतियों के कारण ऐसा देखा गया कि प्रादेशिक व अन्र्तप्रादेशिक स्थिति के समान वैश्विक असमानता में भी वृद्धि हुयी है क्योंकि प्रत्येक देश की संरचना अलग है और इनके विकास के लिए अलग नीति अपनानी होगी। एक अरब भारत की जनसंख्या जो शीघ्र ही विश्व में सर्वाधिक हो जायेगी, कतई आवश्यक नहीं कि नवीन प्रौद्योगिकी के नाम पर उत्पादन प्रक्रिया का मशीनीकरण किया जाये। आज भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 अरब डॉलर को पार कर चुका है परन्तु नवीन तकनीकि के कारण ही उसका लाभ सीमित व्यक्तियों को मिल पाया है कुछ अत्यधिक अमीर हो गये व कुछ की गरीबी और अधिक बढ़ गई है। अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माईकल गोल्डमैन लिखते हैं कि "विश्व बैंक विकास के व्यवसाय में लगा हुआ है जो कि ज्यादा धनिक होने के सिद्धान्त पर कार्य करती है न कि लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक समानता की ओर। आधार संरचना के विकास के कॉन्ट्रेक्ट पश्चिमी देशों की कम्पनियों को मिल जाते है जबकि कर्ज की राशि मय ब्याज के विश्व बैंक को लौटानी होती है और इस प्रक्रिया से धन का प्रवाह दक्षिण ध्रुवीय देशों से उत्तर ध्रुवीय देशों की ओर हो रहा है।"[11] वैश्विक मंच पर भी उदारीकरण रूपी पूँजीवाद के परिणाम बेहतर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन नीतियों के पक्ष में कहा गया था कि इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि तथा "बौद्धिक सम्पदा" जैसे कानूनों के कारण शोध आदि लाभकारी हो जायेंगे व अविष्कारों में तेजी आयेगी परन्तु इन तर्कों के दुष्परिणाम ही अधिक दिखाई दे रहे हैं।

शोध के मध्य यह जानकारी आयी कि उदारीकरण नीति बाजारवाद का एक और बुरा पहलू है कि पेटेंट कानून के नाम पर विकसित देशों को पिछड़े देशों में

वैज्ञानिक शोध कार्य वाधित करने का भी अधिकार मिल गया है, वैश्वीकरण के पश्चात् भारत की विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता बढ़ गयी है और इस प्रकार यह देश हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान व एटोमिक रिसर्च को भी दबाव डालकर रोकने लगे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, व एटोमिक रिसर्च के कई युद्ध के अतिरिक्त कार्य भी हैं जो अत्यधिक मानव कल्याणकारी है। परन्तु विकसित देशों ने इन्हें सैन्य अनुसंधान का नाम देकर रोक दिया है। वर्तमान "परमाणु ऊर्जा करार" विवाद इसी बात का उदाहरण है। आज नई नीतियों के परिणाम स्वरूप हम उस दो राहे पर खड़े हैं जहां न तो समझौते को पूर्णतः स्वीकार करते बनता है और न ही छोड़ते बनता है।

प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त नई नीतियों ने भारत में पूँजी संचय की प्रक्रिया को भी वाधित किया है और इस कारण देश की आत्मनिर्भरता और भी कम हो जायेगी क्योंकि वर्तमान बाजार नीति इस प्रकार है जो बचत हतोत्साहित करती है बल्की नई नीति तो "कर्ज देकर उपभोग" बढ़ाने की है। सरकार को इस संदर्भ में कठोर नियम बनाने चाहिये ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनी दिग्भ्रमित करने वाले विज्ञापन न कर सकें। ऐसे कानून अमेरिका में पहले से ही हैं।

L.P.G. नीतियों को हम आँख मूंद कर स्वीकार करते चले गये और इसका परिणाम यह हुआ कि हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में उनकी उन नीतियों को भी स्वीकार कर लिया जिन्हें विकसित देशों ने प्रतिबन्धित कर रखा है। सरकार को अर्थ व्यवस्था की "ओवर हीटिंग" व उच्चावचन रोकने के लिए पूँजी के खेल को नियमित करना होगा जो सेंसेक्स व वादा कारोबार में सट्टेबाजी के माध्यम से प्रारम्भ हुआ है। सारांश की आर्थिक नीतियों का उदारीकारण की वर्तमान स्थिति को देखकर इस प्रकार समायोजित करना होगा ताकि नई नीति का

अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके तथा इसके साथ ही साथ भारत के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके।

भारत के समग्र आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है कि यहां की नीतियाँ देश व काल की परिस्थितियों के अनुकूल हों परन्तु विकसित देशों द्वारा संचालित L.P.G. नीतयों के परिप्रेक्ष्य में सच्चाई यह है विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जब विकासशील देशों को विकास के लिए धन देता है तो अर्थनीति में संरचनात्मक सुधारों की एक सूची सौंप देता है जिन्हें विकासशील देशों को अपनाना पड़ता है। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकॉनॉमिक के जॉन विलयम सन द्वारा दिया शब्द "वाशिंगटन सर्वानुमति" इन्हीं सुधारों के सौदे को दिया गया नाम है।

आर्थिक कल्याण के लिए यह आवश्यक माना गया है कि समाज में एंक समान तरीके से धन का वितरण हो। इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए समाजवाद, सर्वोदय तथा गाँधीवादी विचार भारत से उदय हुये साम्यवादी विचार भी समानता की बात करते है गुन्नार मिर्डल ने गाँधी की मृत्यु के बीस वर्ष बाद यहां तक कहा कि "मार्क्स के शिष्य लेनिन की तरह गाँधी जी को भी भारत में कोई शिष्य मिल गया होता, तो भारत की आर्थिक स्थिति कुछ और होती।[12] कहने का तात्पर्य कि धन के असमान वितरण के प्रति अर्थशास्त्रियों ने पर्याप्त चिन्तन किया है। डॉ. अमर्त्य सेन के अनुसार, "विषमता तथा विद्रोह में निकट सम्बन्ध है, ज्यों–ज्यों असमानता के प्रति असहिष्णुता में वृद्धी हुयी है विषमता की आर्थिक संकल्पनाओं में भी वृद्धी हुयी है। एथेन्स के विद्वान समता के सिद्धान्त में दासों की अनदेखी करने में इसी कारण सफल हो सके क्योंकि वह ऐसा कर सकते थे।"[13] इस सारे चिन्तन मनन के बावजूद विश्व से असमानता को समाप्त नहीं किया जा सका है यहां तक अमेरिका व ब्रिटेन अत्याधुनिक देशों में भी अमीर व गरीब के मध्य 440 गुना आय का अन्तर है।

यह वैश्वीकरण से प्राप्त हुये आर्थिक विकास का सच है क्योंकि जब कमजोर व सबल को एक ही नीति से चलाने का प्रयत्न किया जायेगा तो सबल सब कुछ हथिया लेगा। पूर्व अध्याय में ज्ञात हुआ कि वर्तमान पूँजीवाद क्लासकी अर्थशास्त्रियों के पूँजीवाद से भिन्न है तो उसका कारण है कि विकसित देशों में सरकार व औद्योगिक गुट दो समान शक्ति सम्पन्न संस्था है जिससे औद्योगिक जगत को उपभोक्ता व श्रमिकों के शोषण का मौका नहीं मिलता क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक है उसे निचले तबके का संरक्षण करना ही होगा, क्योंकि उनकी वोट पॉवर अधिक है परन्तु जब यह अमीर देश वैश्वीकरण के कारण खुले व्यापार के लिए आगे आती हैं तो सरकार कॉरपोरेटर गठबन्धन मजबूत बन जाता है हॉल ही में अमेरिका व भारत के बीच कई ऐसे मौके आये जब अमेरिका की राजीनति ने औद्योगिक नीति व उद्योग नीति ने राजनीति के सौदे किये। सरकार उद्योग गठबनधन को वर्तमान वैश्वीकरण नीति से विकासशील देशों के शोषण का मौका मिल गया। कुछ दिनों पहले यह उदाहरण देखने को मिला कि बहुराष्ट्रीय उद्योग जगत श्रमिकों के गतिशीलता के लाभ उठाना चाहता है क्योंकि मल्टीनेशनल कम्पनी को अमेरिकी इंजीनियर या मैनेजर की तुलना में भारतीय को कम वेतन देनी होती है इस कारण वह श्रम की गतिशीलता सम्बन्धी वैश्विक नीति का लाभ उठाना चाहती है। अमेरिका ने जिस तरह की छूट कनाडा के नागरिकों को अमेरिका में कार्य करने की दे रखी है "मोस्ट फेवरर्ड नेशन" की संधी के तहत यदि वैसी सुविधा भारत को भी मिल जाये तो भारत तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनी दोनों को लाभ है पर अमेरिका ग्रीन कार्ड देने में हिचकिचा रही है क्योंकि वहां के वोटर नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं और इस "पॉलिटिक स्ट्रेटजी" का परिणाम यह है कि वर्तमान पूँजीवाद से विकससित देश के श्रमिक व गरीब सुरक्षित है परन्तु विकासशील व अविकसित देशों के गरीब नागरिक व श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुला हुआ है।

यह सही है कि वर्तमान आर्थिक नीतियां विकासशील देशों के भविष्य के लिए सही नहीं हैं, पर कीन्स कहते हैं "हमें भविष्य की चिन्ता में वर्तमान आर्थिक लाभ नहीं गंवाना चाहिये।" हैमिल्टन के शिशुउद्योग तर्क की भी आलोचना अर्थशास्त्रियों ने इस कारण की क्योंकि "संरक्षण से लागत लाभ अनुपात सदैव के लिए बिगड़ जाता है" यदि इन विचारों के दृष्टीगत सोचें तो वैश्वीकरण की नीति सही प्रतीत होती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा से सदैव मानव को लाभ हुआ है, मानवीय विकास प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वद्विता पर ही आधारित हैं यदि एक–दूसरे से आगे निकलने की होड़ न होती तब भी वैज्ञानिक अनुसंधान किये जाते परन्तु खद को सुरक्षित रखने व दूसरों को पीछे छोड़ने की मानवीय प्रवर्ती ने ही अधिकाधिक अविष्कारों को जन्म दिया।

वैश्वीकरण की नीति सैद्धान्तिक रूप से भले सही प्रतीत हो परन्तु इसकी निम्न कमियां शोध के पश्चात् प्राप्त हुयी –

1. इन नीतियों ने विकसित क्षेत्र को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ पहुँचाया है तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास आर्थिक नियोजन के काल से भी कम हुआ है।
2. उदारीकरण के पश्चात् उपभोक्तावाद में उपभोक्ता लाभ में रहेगा यह बात गलत साबित हुयी।
3. वैश्वीकरण के पश्चात् विकासशील देश कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे यह धारणा भी गलत निकली क्योंकि उदारीकरण के बाद हमारा कृषि आयात उल्टा बढ़ गया है।
4. निजीकरण के पश्चात् सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी मानवीय सुविधाओंपर अधिक खर्च कर सकेगी ऐसा भी नहीं हुआ। योजना आयोग व वित्त मंत्री भी अब मान चुके हैं कि ढांचागत विकास के लिए फंड कम है।

5. बौद्धिक सम्पदा कानून के कारण "रिसर्च वर्क" बढ़ने से लाभ होगा यह नहीं हुआ उल्टा आज पेटेंट की वजह से ही सामान्य बीमारियों तक की दवायें इतनी महंगी हो गयी कि वह आम भारतियों की पहुँच में नहीं है।

6. कहा गया था कि "मैरिटो क्रैसी" के कारण नव उद्यमियों को लाभ होगा परन्तु आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों क सम्मुख उनका टिकना और भी मुश्किल है।

7. विदेशी निवेश से देश के उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धी की आशा की गई थी परन्तु देश का उत्पदन बढ़ा पर रोजगार में वृद्धी नहीं हो सकी क्योंकि नवीन प्रौद्योगिकी श्रम प्रतिस्थापन थी।

8. विदेशी निवेश से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धी की बात कही गयी थी परन्तु देखा गया कि अत्याधिक विदेशी निवेश से भारत में मुद्रा स्फीति की समस्या हुयी। कीमतें बढ़ने के कारण तुलनात्मक जीवन स्तर कम हुआ है।

वैश्वीकरण की नीति के भारत में असफलता के निम्नलिखित कारण देखे गये :–

1. भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या के कारण नीवन प्रौद्योगिकी के श्रम गहन होने की आवश्यकता है जबकि विकसित देशों की प्रौद्योगिकी पूँजी गहन है।

2. 19वीं शताब्दी के मध्य तक विदेशी उपनिवेश के कारण भारत वैज्ञानिक अनुसंधान में पिछड़ गया था और वैश्वीकरण के लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा।

3. भारत में वह ढाँचागत सुविधाएँ नहीं थी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बिना पूर्व तैयारी के उतर सके।

4. यहां क्षेत्रीय आर्थिक असमानता पहले से मौजूद थी और इसके पूर्ण नियोजन सेपहले ही निजीकरण कर देने से यह और अधिक बढ़ गयी।

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं – WTO, IMF इत्यादि ने निष्पक्षता से "मैच रैफरी" की भूमिका नहीं निभाई है।

6. विश्व बैंक अमीर देशों के दबाव के कारण सभी देशों को वैश्वीकरण के लाभ देने में असफल हुआ है और यह मात्र विकास का व्यापार करने वाली संस्था बन गयी है।

सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से उपजी समस्या के समाधान एवं सार्वोत्तम विकास के लिए भारत को निम्नलिखित समाशोधन उपाय अपनाने चाहिये :–

1. कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक सूची में रख कर खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिये एवं सरकार का दाईत्व है कि भूख से कोई मौत न हो पाये।

2. सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि बहुराष्ट्रीय कपनियां उपभोक्ताओं का नियम विपरीत शोषण न कर सकें एवं अधिकारियों को प्रभावित करके कानून विपरीत लाभ न उठा सकें।

3. शोध कार्य एवं शोध संस्थानों पर अत्याधिक खर्च करके स्वदेशी तकनीकि बनाने पर जोर देना चाहिये क्योंकि तभी विकसित देशों की ''ब्लैक मेलिंग'' को रोका जा सकेगा।

4. विदेशी पूंजी निवेश का आँख मूंद कर स्वागत नहीं किया जाना चाहिये, अपितु उसके दूरगामी परिणामों का भी स्मरण रखना होगा।

5. क्षेत्रीय निवेश सम्बन्धी फैसले राजनैतिक न होकर एक ऐसी परिपाटी (स्केलिंग) के आधार पर हो ताकि ''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' या औद्योगिक आस्थान वास्तविक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकें।

6. श्रम गहन उद्योगों, हस्त शिल्प, हथ करघा इत्यादि को निर्यात सब्सिडी देनी चाहिये एवं पर्यटन और वाणिज्य मंत्रालय को मिलकर इनका प्रमोशन (ध्यान आकर्षण) करना चाहिये।

7. भारत आज विकास मे बहुत पीछे है अतः सरकार व उद्यमियों को मिलकर दूसरे देशों के बाजार एवं उद्योगों में अपना स्थान खोजना होगा। विकसित देश व वहां के उद्योग भी ऐसा करते हैं।

8. स्वदेशी उद्यामियों के अमीर होने का अत्यधिक महिमा मंडन नहीं करना चाहिये एवं उद्यामियों क सामाजिक कार्यो की प्रशंसा की जानी चाहिये।

9. सरकार को अफसरशाही, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय करने होंगे एवं जनसंख्या पर यथाशीघ्र नियंत्रण पाना होगा।

10. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में विकसित व अविकसित देशों के अधिकारी समान रूप से होने चाहिये एवं वोटिंग पॅावर भी एक समान होनी चाहिये तभी यह तटस्थ रह सकेंगे।

11. वैश्वीकरण की नीति पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा देश को प्राथमिक व द्वितियक क्षेत्र में आत्म निर्भरता की स्थिति प्राप्त करनी ही होगी।

पाद टिप्पणी

1. Lok Sabha (2002), Unstarred Question 2556 and ministry of finance, Indian public finance statistic (2001-02)

2 - 3 : J.J. Kurian economic and political weekly Feb. 12 to 18, 2000

4. Riserve Bank of India, Hand book of statistic on Indian economy (1999)

5. Rudra datt and Sundram - Indian economy

6. J.J. Kurian economic and political weekly Feb. 12 to 18, 2000

7. अमर उजाला 26 मई 2007, सम्पादकीय

8. अमर उजाला 27 सितम्बर 2007, पूँजी का हश्र (कैलाश वाजपेयी)

9. अमर उजाला 15 अक्टूबर 2007, अजय राम – अजय चतुर्वेदी

10. कुछ विशेषज्ञों का मत है कि 2 से 3 प्रतिशत की औद्योगिक बेरोजगारी स्वभाविक ही नहीं आवश्यक भी है।

11. अमर उजाला 21 सितम्बर 2007, द्वारा – मीनाक्षी अरोड़ा

12. बटरोही द्वारा सम्पादित पुस्तक इक्कीसवीं सदी में गाँधी से

13. आर्थिक विषमता – अमर्त्य सेन

सारणी

नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, 2001
PERCENTAGE OF URBAN POPULATION

अधिकतम मान वाले राज्य
STATES HAVING HIGHEST VALUES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. तमिलनाडु TAMILNADU	44.0
2. महाराष्ट्र MAHARASHTRA	42.4
3. गुजरात GUJARAT	37.4

न्यूनतम मान वाले राज्य
STATES HAVING LOWEST VALUES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH	9.8
2. बिहार BIHAR	10.5
3. असम ASSAM	12.9

भारत के सापेक्ष उ० प्र० की स्थिति
POSITION OF U.P. AS COMPARED TO INDIA

वर्ष YEAR	संकेतक VALUE	
	भारत INDIA	उ० प्र० U.P.
1951	17.3	13.6
1961	18.0	12.9
1971	19.9	14.0
1981	23.3	17.9
1991	25.7	19.8
2001	27.8	20.8

19 प्रमुख राज्यों में उ० प्र० का स्थान U. P.' s RANK AMONG 19 MAJOR STATES	14

मानव विकास सूचकांक, 2001
HUMAN DEVEOPMENT INDEX

सर्वाधिक विकसित राज्य MOST DEVELOPED STATES	
नाम NAME	संकेतक VALUE
1. केरल KERALA	0.869
2. पंजाब PUNJAB	0.818
3. तमिलनाडु TAMILNADU	0.793

सर्वाधिक पिछड़े राज्य MOST BACKWARD STATES	
नाम NAME	संकेतक VALUE
1. बिहार BIHAR	0.616
2. उड़ीसा ORISSA	0.660
3. मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH	0..672

15 प्रमुख राज्यों में उ0 प्र0 का स्थान U. P.'S RANK AMONG 15 MAJOR STATES	12

स्रोतः- उ0 प्र0 मानव विकास प्रतिवेदन

प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कार्यशील कारखानों में औसत दैनिक कर्मचारियों की संख्या, 2000 2001
AVERAGE NO. OF WORKERS PER DAY IN REGISTERED WORKING FACTORIES PER LAKH OF POPULATION

सर्वाधिक विकसित राज्य / MOST DEVELOPED STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. तमिलनाडु TAMILNADU	1835
2. गुजरात GUJARAT	1501
3. पंजाब PUNJAB	1488

सर्वाधिक पिछड़े राज्य / MOST BACKWARD STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. बिहार BIHAR	77
2. उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	328
3. उड़ीसा ORISSA	352

भारत के सापेक्ष उ0 प्र0 की स्थिति / POSITION OF U.P. AS COMPARED TO INDIA

वर्ष YEAR	संकेतक VALUE	
	भारत INDIA	उ0 प्र0 U.P.
1951	N.A.	N.A.
1961	830	241
1971	823	280
1981	885	553
1991	751	450
1994	981	533
1995	1002	502
1996	1084	514
1997	1029	516
1998	1029	475
1999	874	395
2000	627	267
2001	783	328

19 प्रमुख राज्यों में उ0 प्र0 का स्थान U. P.'S RANK AMONG 19 MAJOR STATES	18

पंजीकृत कार्यशील कारखानों में प्रति व्यक्ति शुद्ध आवर्द्धित मूल्य (रु0), 2000-2001
NET VALUE ADDED PER CAPITA IN REGISTERED WORKING FACTORIES

सर्वाधिक विकसित राज्य MOST DEVELOPED STATES	
नाम NAME	संकेतक VALUE
1. गुजरात GUJARAT	3364
2. महाराष्ट्र MAHARASHTRA	3255
3. हरियाणा HARYANA	2671

सर्वाधिक पिछड़े राज्य MOST BACKWARD STATES	
नाम NAME	संकेतक VALUE
1. बिहार BIHAR	89
2. असम ASSAM	485
3. उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	582

19 [illegible] U. P.'S RANK AMONG 19 MAJOR STATES	17

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू0), 'प्रचलित भावों पर', 2002-03
PER CAPITA NET STATE DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT PRICES

सर्वाधिक विकसित राज्य
MOST DEVELOPED STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. हरियाणा HARYANA	26632
2. महाराष्ट्र MAHARASHTRA	26386
3. पंजाब PUNJAB	25855

सर्वाधिक पिछड़े राज्य
MOST BACKWARD STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. बिहार BIHAR	6015
2. उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	9870
3. झारखण्ड JHARKHAND	9955

भारत के सापेक्ष उ0 प्र0 की स्थिति
POSITION OF U.P. AS COMPARED TO INDIA

वर्ष YEAR	संकेतक VALUE	
	भारत INDIA	उ0 प्र0 U.P.
1951	239	259
1961	328	252
1971	675	486
1981	1630	1278
1991	4983	3590
1997	10771	6733
1998	-	7263
1999	14682	9261
2000	15562	9323
2001	16707	9223
2002	17978	9753
2003	18912	9870

18 प्रमुख राज्यों में उ0 प्र0 का स्थान U. P.' S RANK AMONG 18 MAJOR STATES	17

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही जनसंख्या का प्रतिशत, 1999-2000
PERCENTAGE OF POPULATION BELOW POVERTY LINE

सर्वाधिक विकसित राज्य / MOST DEVELOPED STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. पंजाब PUNJAB	6.2
2. हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH	7.6
3. हरियाणा HARYANA	8.7

सर्वाधिक पिछड़े राज्य / MOST BACKWARD STATES

नाम NAME	संकेतक VALUE
1. उड़ीसा ORISSA	47.2
2. बिहार BIHAR	42.6
3. मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH	37.4

16 प्रमुख राज्यों में उ0 प्र0 का स्थान U. P.' RANK AMONG 16 MAJOR STATES	12

विकास स्तर के अनुसार चारों सम्भागों में पश्चिम सम्भाग की स्थिति

RANK OF THE WESTERN REGION AMONG FOUR REGIONS ACCORDINGTO THE LEVEL OF DEVELOPMENT

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
1	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0 मी0) 1 मार्च, 2001 DENSITY OF POPULATION (PER SQ. KM.)		0		
2	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF URBAN POPULATION TO TOTAL POPULATION	0			
3	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF S.C. & S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION				0
4	साक्षरता प्रतिशत (कुल), 2001 LITERACY PERCENTAGE (TOTAL)			0	
5	साक्षरता प्रतिशत (महिला), 2001 LITERACY PERCENTAGE (FEMALE)		0		
6	कुल कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF TOTAL WORKERS TO TOTAL POPULATION				0
7	कृषि योग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF CULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA	0			
8	शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA	0			
9	शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO CULTURABLE LAND	0			
10	ऊसर तथा कृषि के अयोग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF USAR AND UNCULTURABLE LAND TO REPORTING AREA		0		
11	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF AREA UNDER FORESTS TO TOTAL REPORTING AREA				0
12	एक हैक्टेयर से अधिक जोतों का कुल जोतों से प्रतिशत 1995-96 PERCENTAGE OF LAND HOLDINGS MORE THAN 1 HECTARE TO TOTAL LAND HOLDINGS	0			
13	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2001-02 PERCENTAGE OF AREA UNDER COMMERCIAL CROPS TO GROSS SOWN AREA	0			

क्रम सं0 S. NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
14	भूमि उपयोगिता का समग्र विकास सूचकांक 2002-03 COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT OF LAND USE	0			
15	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET AREA SOWN	0			
16	कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल बोए गये क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS AREA SOWN	0			
17	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण (कि0ग्रा0), 2002-03 DISTRIBUTION OF FERTILIZERS PER HA. OF GROSS AREA SOWN (K.G.)	0			
18	भूमिगत जल का दोहन प्रतिशत (1 अप्रैल 2004 के अनुसार), अनुमानित EXPLOITATION PERCENTAGE OF GROUND WATER				0
19	फसल विविधीकरण इण्डेक्स 2002-03 CROP DIVERSIFICATION INDEX			0	
20	फसल सघनता, 2002-03 INTENSITY OF CROPPING	0			
21	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (कि0 ग्रा0), 2001-02 PER CAPITA PRODUCTION OF FOODGRAINS (K.G.)		0		
22	कुल खाद्यान्न की औसत उपज (कुण्टल/हे0), 2001-02 AVERAGE YIELD OF FOODGRAINS (Q./HA.)	0			
23	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रु0),'प्रचलित भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER HA. OF GROSS AREA SOWN (Rs.) AT CURRENT PRICES	0			
24	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रु0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER HA. OF GROSS AREA SOWN (Rs.) AT CONSTANT PRICES	0			
25	प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रु0), 'प्रचलित भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER RURAL PERSON (Rs.) AT CURRENT PRICES	0			
26	प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रु0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER RURAL PERSON (Rs.) AT CONSTANT PRICES	0			
27	प्रति लाख हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर विनियमित मण्डियों की संख्या, 2002-03 NO. OF REGULATED MANDIS PER LAKH HA. OF NET AREA SOWN	0			
28	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी कृषि विपणन केन्द्रों की संख्या (क्रय केन्द्र), 2002-03 NO. OF COOP. AGRICULTURAL MARKETING CENTRES PER LAKH OF POPULATION (PURCHASE CENTRES)	0			

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
29	प्रति लाख ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या, 2002-03 NO. OF PRIMARY AGRICULTURE CREDIT SOCIETIES PER LAKH OF RURAL POPULATION				0
30	प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या, 2003-04 NO. OF MILK PRODUCTIVE COOPERATIVE SOCIETIES PER LAKH OF MILCH CATTLE	0			
31	प्रति लाख जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या, 2002-03 NO. OF SCHEDULED COMMERCIAL BANK BRANCHES PER LAKH OF POPULATION			0	
32	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत), 31 मार्च 2004 CREDIT-DEPOSIT RATIO (PERCENTAGE)		0		
33	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या, 2001-02 NO. OF WORKING FACTORIES PER LAKH OF POPULATION	0			
34	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, 2001-02 NO. OF WORKERS ENGAGED IN REGISTERED FACTORIES PER LAKH OF POPULATION	0			
35	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य (रू0), 2001-02 GROSS VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCE PER CAPITA (Rs.)	0			
36	उद्योग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF CON. OF ELECTRICITY IN INDUSTRY TO TOTAL CONSUMPTION OF ELECTRICITY			0	
37	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILLAGES TO TOTAL INHABITED VILLAGES	0			
38	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि0 वा0 घं0), 2002-03 PER CAPITA CONSUMPTION OF ELECTRICITY (K.W.H.)		0		
39	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0 मी0), 2003-04 LENGTH OF TOTAL PUCCA ROADS PER LAKH OF POPULATION (K. M.)				0
40	प्रति हजार वर्ग कि0 मी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0), 2003-04 LENGTH OF TOTAL PUCCA ROADS PER THOUSAND SQ. K.M. OF AREA (K.M.)		0		
41	प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या, 2002-03 NO. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION				0
42	प्रति लाख जनसंख्या पर दूरभाष कनेक्शनों की संख्या, 2002-03 NO. OF TELEPHONE CONNECTIONS PER LAKH OF POPULATION	0			

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
43	प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालकों का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED BOYS IN PRIMARY SCHOOLS	0			
44	प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED GIRLS IN PRIMARY SCHOOLS				0
45	मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 30 सितम्बर, 2004 REQUIRMENT OF PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO NORM			0	
46	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक विद्यालय) 30 सितम्बर, 2004 PUPIL - TEACHER RATIO (PRIMARY SCHOOLS)		0		
47	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालकों का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED GIRLS IN UPPER PRIMARY SCHOOLS		0		
48	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED BOYS IN UPPER PRIMARY SCHOOLS		0		
49	मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 30 सितम्बर, 2004 REQUIRMENT OF UPPER PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO NORM			0	
50	छात्र-शिक्षक अनुपात (उच्च प्राथमिक विद्यालय) 30 सितम्बर, 2004 PUPIL - TEACHER RATIO (UPPER PRIMARY SCHOOLS)	0			
51	प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या, 2003-04 NO. OF I.T.Is. PER LAKH OF POPULATION			0	
52	प्रति लाख जनसंख्या पर बहुधन्धी तकनीकी संस्थानों की संख्या, 2003-04 NO. OF POLYTECHNICS PER LAKH OF POPULATION			0	
53	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (प्रा0 स्वा0 केन्द्रों सहित), 2002-03 NO. OF ALLOPATHIC HOSPITALS/DISPENSARIES PER LAKH OF POPULATION (INCLUDING P.H.Cs.)		0		
54	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (प्रा0 स्वा0 केन्द्रों सहित), 2002-03 NO OF BEDS IN ALLOPATHIC HOSPITALS/DIS. PER LAKH OF POPULATION (INCLUDING P.H.Cs.)			0	
55	वस्तु उत्पाद खण्डों से प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (रू0), 'प्रचलित भावों पर', 2001-02 PER CAPITA NET PRODUCT FROM COMMODITY PRODUCING SECTORS (Rs.) AT CURRENT PRICES	0			
56	वस्तु उत्पाद खण्डों से प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (रू0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 PER CAPITA NET PRODUCT FROM COMMODITY PRODUCING SECTORS (Rs.) AT CONSTANT PRICES	0			
57	समग्र विकास सूचकांक (28 प्रमुख संकेतकों पर आधारित). COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT BASED ON 28 IMPORTANT INDICATORS	0			

विकास स्तर के अनुसार चारों सम्भागों में पूर्वी सम्भाग की स्थिति

RANK OF THE EASTERN REGION AMONG FOUR REGIONS ACCORDING TO THE LEVEL OF DEVELOPMENT

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
1	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0 मी0) : मार्च, 2001 DENSITY OF POPULATION (PER SQ. KM.)	0			
2	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF URBAN POPULATION TO TOTAL POPULATION				0
3	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF S.C. & S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION			0	
4	साक्षरता प्रतिशत (कुल), 2001 LITERACY PERCENTAGE (TOTAL)				0
5	साक्षरता प्रतिशत (महिला), 2001 LITERACY PERCENTAGE (FEMALE)				0
6	कुल कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, 2001 PERCENTAGE OF TOTAL WORKERS TO TOTAL POPULATION		0		
7	कृषि योग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF CULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA				0
8	शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA				0
9	शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO CULTURABLE LAND		0		
10	ऊसर तथा कृषि के अयोग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF USAR AND UNCULTURABLE LAND TO REPORTING AREA	0			
11	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF AREA UNDER FORESTS TO TOTAL REPORTING AREA	0			
12	एक हेक्टेयर से अधिक जोतों का कुल जोतों से प्रतिशत 1995-96 PERCENTAGE OF LAND HOLDINGS MORE THAN 1 HECTARE TO TOTAL LAND HOLDINGS				0
13	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2001-02 PERCENTAGE OF AREA UNDER COMMERCIAL CROPS TO GROSS SOWN AREA			0	

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
14	भूमि उपयोगिता का समग्र विकास सूचकांक 2002-03 COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT OF LAND USE		0		
15	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET AREA SOWN			0	
16	कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल बोए गये क्षेत्रफल से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS AREA SOWN			0	
17	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण (कि0ग्रा0), 2002-03 DISTRIBUTION OF FERTILIZERS PER HA. OF GROSS AREA SOWN (K.G.)		0		
18	भूमिगत जल का दोहन प्रतिशत (1 अप्रैल 2004 के अनुसार), अनुमानित EXPLOITATION PERCENTAGE OF GROUND WATER			0	
19	फसल विविधीकरण इण्डेक्स 2002-03 CROP DIVERSIFICATION INDEX				0
20	फसल सघनता, 2002-03 INTENSITY OF CROPPING			0	
21	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (कि0 ग्रा0), 2001-02 PER CAPITA PRODUCTION OF FOODGRAINS (K.G.)				0
22	कुल खाद्यान्न की औसत उपज (कुण्टल/हे0), 2001-02 AVERAGE YIELD OF FOODGRAINS (Q./HA.)			0	
23	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0),'प्रचलित भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER HA. OF GROSS AREA SOWN (Rs.) AT CURRENT PRICES			0	
24	प्रति हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER HA. OF GROSS AREA SOWN (Rs.) AT CONSTANT PRICES			0	
25	प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0), 'प्रचलित भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER RURAL PERSON (Rs.) AT CURRENT PRICES				0
26	प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCE PER RURAL PERSON (Rs.) AT CONSTANT PRICES				0
27	प्रति लाख हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर विनियमित मण्डियों की संख्या, 2002-03 NO. OF REGULATED MANDIS PER LAKH HA. OF NET AREA SOWN			0	
28	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी कृषि विपणन केन्द्रों की संख्या (क्रय केन्द्र), 2002-03 NO. OF COOP. AGRICULTURAL MARKETING CENTRES PER LAKH OF POPULATION (PURCHASE CENTRES)			0	

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
29	प्रति लाख ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या, 2002-03 NO. OF PRIMARY AGRICULTURE CREDIT SOCIETIES PER LAKH OF RURAL POPULATION		0		
30	प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या, 2003-04 NO. OF MILK PRODUCTIVE COOPERATIVE SOCIETIES PER LAKH OF MILCH CATTLE			0	
31	प्रति लाख जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या, 2002-03 NO. OF SCHEDULED COMMERCIAL BANK BRANCHES PER LAKH OF POPULATION				0
32	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत), 31 मार्च 2004 CREDIT-DEPOSIT RATIO (PERCENTAGE)				0
33	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या, 2001-02 NO. OF WORKING FACTORIES PER LAKH OF POPULATION				0
34	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, 2001-02 NO. OF WORKERS ENGAGED IN REGISTERED FACTORIES PER LAKH OF POPULATION			0	
35	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य (रू0), 2001-02 GROSS VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCE PER CAPITA (Rs.)				0
36	उद्योग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF CON. OF ELECTRICITY IN INDUSTRY TO TOTAL CONSUMPTION OF ELECTRICITY	0			
37	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत, 2002-03 PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILLAGES TO TOTAL INHABITED VILLAGES			0	
38	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि0 वा0 घं0), 2002-03 PER CAPITA CONSUMPTION OF ELECTRICITY (K.W.H.)			0	
39	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0 मी0), 2003-04 LENGTH OF TOTAL PUCCA ROADS PER LAKH OF POPULATION (K. M.)			0	
40	प्रति हजार वर्ग कि0 मी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0), 2003-04 LENGTH OF TOTAL PUCCA ROADS PER THOUSAND SQ. K.M. OF AREA (K.M.)	0			
41	प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या, 2002-03 NO. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION		0		
42	प्रति लाख जनसंख्या पर दूरभाष कनेक्शनों की संख्या, 2002-03 NO. OF TELEPHONE CONNECTIONS PER LAKH OF POPULATION				0

क्रम सं0 S.NO.	संकेतक INDICATOR	रैंक RANK			
		प्रथम FIRST	द्वितीय SECOND	तृतीय THIRD	चतुर्थ FOURTH
43	प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालकों का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED BOYS IN PRIMARY SCHOOLS				0
44	प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED GIRLS IN PRIMARY SCHOOLS	0			
45	मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 30 सितम्बर, 2004 REQUIRMENT OF PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO NORM				0
46	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक विद्यालय) 30 सितम्बर, 2004 PUPIL - TEACHER RATIO (PRIMARY SCHOOLS)				0
47	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालकों का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED GIRLS IN UPPER PRIMARY SCHOOLS				0
48	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं का प्रतिशत, 30 सितम्बर, 2004 PERCENTAGE OF ENROLLED BOYS IN UPPER PRIMARY SCHOOLS	0			
49	मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 30 सितम्बर, 2004 REQUIRMENT OF UPPER PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO NORM				0
50	छात्र-शिक्षक अनुपात (उच्च प्राथमिक विद्यालय) 30 सितम्बर, 2004 PUPIL - TEACHER RATIO (UPPER PRIMARY SCHOOLS)				0
51	प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या, 2003-04 NO. OF I.T.Is. PER LAKH OF POPULATION				0
52	प्रति लाख जनसंख्या पर बहुधन्धी तकनीकी संस्थानों की संख्या, 2003-04 NO. OF POLYTECHNICS PER LAKH OF POPULATION				0
53	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (प्रा0 स्वा0 केन्द्र सहित), 2002-03 NO. OF ALLOPATHIC HOSPITALS/DISPENSARIES PER LAKH OF POPULATION (INCLUDING P.H.Cs.)			0	
54	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (प्रा0 स्वा0 केन्द्र सहित), 2002-03 NO.OF BEDS IN ALLOPATHIC HOSPITALS/DIS. PER LAKH OF POPULATION (INCLUDING P.H.Cs.)				0
55	वस्तु उत्पाद खण्डों से प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (रू0), 'प्रचलित भावों पर', 2001-02 PER CAPITA NET PRODUCT FROM COMMODITY PRODUCING SECTORS (Rs.) AT CURRENT PRICES				0
56	वस्तु उत्पाद खण्डों से प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (रू0), 'स्थायी भावों पर', 2001-02 PER CAPITA NET PRODUCT FROM COMMODITY PRODUCING SECTORS (Rs.) AT CONSTANT PRICES				0
57	समग्र विकास सूचकांक (28 प्रमुख संकेतकों पर आधारित). COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT BASED ON 28 IMPORTANT INDICATORS				0

कुल खाद्यान्न की औसत उपज (कुण्टल/हे0), 2001-02
AVERAGE YIELD OF FOODGRAINS (Q./HA.)

सर्वाधिक विकसित जिले MOST DEVELOPED DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. मुजफ्फर नगर	MUZAFFAR NAGAR	33.60
2. बागपत	BAGHPAT	32.89
3. मेरठ	MEERUT	32.77
4. बुलन्द शहर	BULANDSHAHR	31.05
5. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	30.91

सर्वाधिक पिछड़े जिले MOST BACKWARD DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. महोबा	MAHOBA	10.55
2. ललितपुर	LALITPUR	10.82
3. चित्रकूट	CHITRAKOOT	11.97
4. हमीरपुर	HAMIRPUR	12.20
5 बांदा	BANDA	12.24

अन्तर्सम्भागीय स्थिति INTER REGIONAL POSITION			
सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	25.76	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	21.19	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	13.71	IV
4. पूर्वी	EASTERN	20.55	III

भूमि उपयोगिता का समग्र विकास सूचकांक 2001-02**
COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT OF LAND USE

सर्वाधिक विकसित जिले / MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. चन्दौली	CHANDAULI	96.76
2. महराजगंज	MAHARAJGANJ	95.66
3. रामपुर	RAMPUR	94.86
4. पीलीभीत	PILIBHIT	93.75
5. सहारनपुर	SAHARANPUR	91.31

सर्वाधिक पिछड़े जिले / MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गौतमबुद्ध नगर	G.B. NAGAR	68.46
2. ललितपुर	LALITPUR	70.39
3. प्रतापगढ़	PRATAPGARH	70.84
4. रायबरेली	RAEBARELY	72.33
5. लखनऊ	LUCKNOW	73.14

अन्तर्सम्भागीय स्थिति / INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	85.81	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	78.37	III
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	75.58	IV
4. पूर्वी	EASTERN	83.49	II

स्रोतः भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

** कम्पोजिट इण्डेक्स के अन्तर्गत कृष्य भूमि उपयोग, क्षमता युक्त भूमि उपयोग, अन्तिम क्षमता युक्त भूमि उपयोग, फसल सघनता तथा प्रतिवेदित क्षेत्रफल के सापेक्ष वन भूमि को समाहित किया गया है।

भूमिगत जल का दोहन (प्रतिशत में) (1 अप्रैल 2004 के अनुसार) अनुमानित
EXPLOITATION OF GROUND WATER (PERCENTAGE)

सुरक्षित जिले SAFE DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. जालौन	JALAUN	32.50
2. बाँदा	BANDA	36.71
3. चित्रकूट	CHITRAKOOT	36.82
4. चन्दौली	CHANDAULI	41.77
5. इटावा	ETAWAH	41.91

सर्वाधिक दोहन वाले जिले MOST EXPLOITATED DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. बदायूँ	BUDAUN	100.85
2. बागपत	BAGHPAT	98.23
3. हाथरस	HATHRAS	97.41
4. मुरादाबाद	MORADABAD	94.56
5. सहारनपुर	SAHARANPUR	91.60

अन्तर्सम्भागीय स्थिति INTER REGIONAL POSITION			
सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	69.51	IV
2. केन्द्रीय	CENTRAL	65.77	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	43.53	I
4. पूर्वी	EASTERN	66.08	III

प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या, 2001-02
NO. OF WORKING FACTORIES PER LAKH OF POPULATION

सर्वाधिक विकसित जिले
MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	160.9
2. गाजियाबाद	GHAZIABAD	36.7
3. कानपुर नगर	KANPUR NAGAR	29.6
4. फिरोजाबाद	FIROZABAD	22.2
5. मेरठ	MEERUT	19.1

सर्वाधिक पिछड़े जिले
MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. श्रावस्ती	SHRAWASTI	0.0
2. चित्रकूट	CHITRAKOOT	0.0
3. कुशीनगर	KUSHINAGAR	0.4
4. बस्ती*	BASTI	0.5
5. गोण्डा	GONDA	0.6
6. बलरामपुर	BALRAMPUR	0.8

*सिद्धार्थ नगर को सम्मिलित करते हुए।

अन्तर्सम्भागीय स्थिति
INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	12.9	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	9.4	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	3.9	III
4. पूर्वी	EASTERN	2.7	IV

प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, 2001-02
NO. OF WORKERS ENGAGED IN REGISTERED FACTORIES PER LAKH OF POPULATION

सर्वाधिक विकसित जिले / MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	5067
2. सोनभद्र	SONBHADRA	1160
3. गाजियाबाद	GHAZIABAD	1112
4. कानपुर नगर	KANPUR NAGAR	665
4. बिजनौर	BIJNOR	605

सर्वाधिक पिछड़े जिले / MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. महोबा	MAHOBA	4
2. प्रतापगढ़	PRATAPGARH	6
3. बाँदा	BANDA	6
4. औरैया	AURAIYA	16
5. बलिया	BALLIA	19

अन्तर्सम्भागीय स्थिति / INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	413	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	229	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	64	IV
4. पूर्वी	EASTERN	107	III

प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य (रू0), 2001-02
GROSS VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCE PER CAPITA (Rs.)

सर्वाधिक विकसित जिले MOST DEVELOPED DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	142830
2. गाजियाबाद	GHAZIABAD	28323
3. सोनभद्र	SONBHADRA	14183
4. कानपुर देहात	KANPUR DEHAT	10622
5. कानपुर नगर	KANPUR NAGAR	9921

सर्वाधिक पिछड़े जिले MOST BACKWARD DISTRICTS		
नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. प्रतापगढ़	PRATAPGARH	19
2. बांदा	BANDA	21
3. महोबा	MAHOBA	36
4. बलिया	BALLIA	72
5. आजमगढ़	AZAMGARH	120

अन्तर्सम्भागीय स्थिति INTER REGIONAL POSITION			
सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	7811	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	3743	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	1587	III
4. पूर्वी	EASTERN	1417	IV

मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता, 2004
REQUIRMENT OF PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO NORM

संतृप्त/कम आवश्यकता वाले जिले
SATURATE, LIST REQUIRED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. मुजफ्फर नगर	MUZAFFAR NAGAR	0
2. मेरठ	MEERUT	0
3. गाज़ियाबाद	GHAZIABAD	0
4. महराजगंज	MAHARAJGANJ	0
5. वाराणसी	VARANASI	0
6. ललितपुर	LALITPUR	2
7. बागपत	BAGHPAT	5
8. बस्ती	BASTI	5

0 संतृप्त/SATURATE

अधिक आवश्यकता वाले जिले
MOST REQUIRED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. बरेली	BAREILLY	109
2. जौनपुर	JAUNPUR	105
3. लखनऊ	LUCKNOW	90
4. कुशीनगर	KUSHI NAGAR	83
5. शाहजहाँपुर	SHAHJAHANPUR	80
6. कौशाम्बी	KAUSHAMBI	77
7. बलिया	BALLIA	68
8. आजमगढ़	AZAMGARH	68

अन्तर्सम्भागीय स्थिति
INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	867	III
2. केन्द्रीय	CENTRAL	309	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	161	I
4. पूर्वी	EASTERN	1084	IV

प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या, 2003-04
NO. OF I.T.Is PER LAKH OF POPULATION

सर्वाधिक विकसित जिले / MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. महोबा	MAHOBA	0.41
2. कानपुर देहात	KANPUR DEHAT	0.24
3. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	0.24
4. इटावा	ETAWAH	0.21
5. ललितपुर	LALITPUR	0.19
6. सुल्तानपुर	SULTANPUR	0.18

सर्वाधिक पिछड़े जिले / MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. चन्दौली	CHANDAULI	शून्य/नगण्य NIL/Negl.*
2. संतकबीर नगर	SANTKABIR NAGAR	
3. श्रावस्ती	SHRAWASTI	
4. चित्रकूट	CHITRAKOOT	
5. औरैया	AURAIYA	
6. बागपत	BAGHPAT	
7. महराजगंज	MAHARAJGANJ	0..04

अन्तर्सम्भागीय स्थिति / INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	0.10	III
2. केन्द्रीय	CENTRAL	0.11	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	0.15	I
4. पूर्वी	EASTERN	0.09	IV

* Negl.= NEGLIGIBLE

प्रति लाख जनसंख्या पर बहुधन्धी तकनीकी संस्थानों की संख्या, 2003-04
NO. OF POLYTECHNICS PER LAKH OF POPULATION

सर्वाधिक विकसित जिले / MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. महोबा	MAHOBA	0.14
2. कानपुर नगर	KANPUR NAGAR	0.11
3. झाँसी	JHANSI	0.11
4. लखनऊ	LUCKNOW	0.10
5. ललितपुर	LALITPUR	0.10
6. मथुरा	JHANSI	0.09
7. फैजाबाद	FAIZABAD	0.09

सर्वाधिक पिछड़े जिले / MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE	नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. सोनभद्र*	SONBHADRA		11. चित्रकूट*	CHITRAKOOT	
2. संतरविदासनगर*	SANTRAVIDASNAGAR		12. हमीरपुर *	HAMIRPUR	
3. मऊ*	MAU		13. कानपुरदेहात*	KANPUR DEHAT	
4. कुशीनगर*	KUSHINAGAR		14. औरैया*	AURAIYA	
5. महराजगंज*	MAHARAJGANJ		15. कन्नौज*	KANNAUJ	
6. संतकबीरनगर*	SANTKABIR NAGAR		16. फिरोजाबाद*	FIROZABAD	
7. सिद्धार्थनगर*	SIDDHARTH NAGAR		17. अलीगढ़*	ALIGARH	
8. बलरामपुर*	BALRAMPUR		18 ज्योतिबाफूले नगर*	J. P. NAGAR	
9. श्रावस्ती*	SHRAWASTI		19. आजमगढ़	AZAMGARH	0.02
10. कौशाम्बी*	KAUSHAMBI		20. जौनपुर	JAUNPUR	0.02

अन्तर्सम्भागीय स्थिति / INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	0.04	III
2. केन्द्रीय	CENTRAL	0.05	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	0.07	I
4. पूर्वी	EASTERN	0.03	IV

* नगण्य   *Negl. - NEGLIGIBLE

बच्चों के पोषण स्तर 2002-2003
NUTRITION STATUS OF CHILDREN

सर्वाधिक विकसित जिले
MOST DEVELOPED DISTRICTS

	नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1.	गाजियाबाद	GHAZIABAD	39.57
2.	गौतमबुद्ध नगर	GAUTAMBUDDHA NAGAR	39.16
3.	फर्रुखाबाद	FARRUKHABAD	35.32
4.	कन्नौज	KANNAUJ	35.32
5.	खीरी	KHERI	29.77
6.	बिजनौर	BIJNOR	28.88
7.	बुलन्दशहर	BULANDSHAHR	27.58

सर्वाधिक पिछड़े जिले
MOST BACKWARD DISTRICTS

	नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1.	सीतापुर	SITAPUR	5.74
2.	श्रावस्ती	SHARAWANTI	6.10
3.	बहराइच	BAHRAICH	6.11
4.	बस्ती	BASTI	6.94
5.	फतेहपुर	FATEHPUR	7.98
6.	बदायूँ	BUDAUN	8.75
7.	गोरखपुर	GORAKHPUR	8.77
8.	संत कबीर नगर	SANT KABIR NAGAR	8.80
9.	फैजाबाद	FAIZABAD	9.32
10.	अम्बेडकर नगर	AMBEDKAR NAGAR	9.46
11.	सोनभद्र	SONBHADRA	9.79

समग्र स्वास्थ्य सूचकांक 2002-03
COMPOSITE INDEX OF HEALTH

सर्वाधिक विकसित जिले
MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गाजियाबाद	GHAZIABAD	73.46
2. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAMBUDDHA NAGAR	71.66
3. मेरठ	MERUT	69.87
4. कानपुर नगर	KANPUR DEHAT	68.29
5. मेरठ	MEERUT	10.80
6 लखनऊ	LUCKNOW	67.49
7. सहारनपुर	SAHARANPUR	66.74
8. मुंजफ्फर नगर	MUZAFFAR NAGAR	65.90
9. बिजनौर	BIJNOR	64.76
10 .बलिया	BALLIA	64.29

सर्वाधिक पिछड़े जिले
MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. बलरामपुर	BALRAMPUR	39.74
2. श्रावस्ती	SHRAWASTI	41.63
3. कौशाम्बी	KAUSHAMBI	41.80
4. हरदोई	HARDOI	42.34
5. बदायूं	BUDAUN	42.90
6. बहराइच	BAHRAICH	43.24
7. शाहजहाँपुर	SHAHJAHANPUR	43.28
8. गोण्डा	GONDA	43.98
9. सीतापुर	SITAPUR	44.89
10.सिद्धार्थ नगर	SIDDHARATH NAGAR	44.94

समग्र विकास सूचकांक (28 प्रमुख संकेतकों पर आधारित)
COMPOSITE INDEX OF DEVELOPMENT BASED ON 28 IMPORTANT INDICATORS

सर्वाधिक विकसित जिले
MOST DEVELOPED DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. गौतमबुद्ध नगर	GAUTAM BUDDHA NAGAR	410.03
2. गाजियाबाद	GHAZIABAD	183.23
3. मेरठ	MEERUT	149.86
4. कानपुर नगर	KANPUR NAGAR	144.27
5. लखनऊ	LUCKNOW	135.20

सर्वाधिक पिछड़े जिले
MOST BACKWARD DISTRICTS

नाम NAME		मान/मूल्य VALUE
1. श्रावस्ती	SHRAWASTI	72.55
2. संत कबीर नगर	SANT KABIR NAGAR	76.06
3. बलरामपुर	BALRAMPUR	77.31
4. जौनपुर	JAUNPUR	77.58
5. कौशाम्बी	KAUSHAMBI	78.97

अन्तर्सम्भागीय स्थिति
INTER REGIONAL POSITION

सम्भाग REGION		मान/मूल्य VALUE	रैंक RANK
1. पश्चिमी	WESTERN	116.33	I
2. केन्द्रीय	CENTRAL	102.32	II
3. बुन्देलखण्ड	BUNDELKHAND	100.39	III
4. पूर्वी	EASTERN	83.53	IV

ग्राफ

उत्तर प्रदेश की कुल राज्य आय
(करोड़ रूपये में)
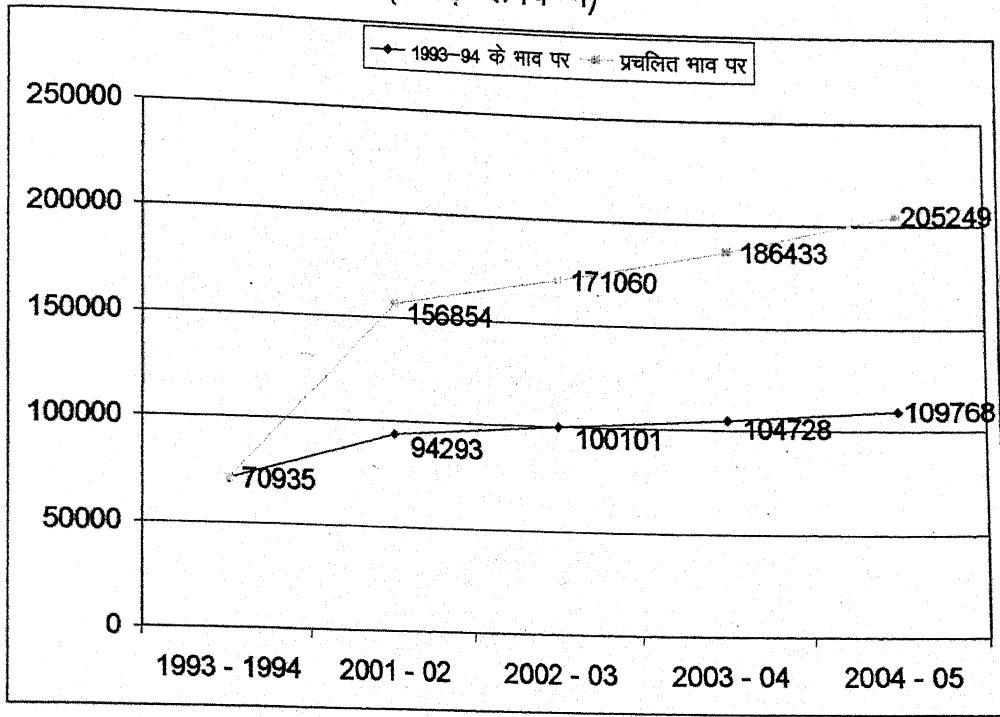
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति राज्य आय
(रूपये में)
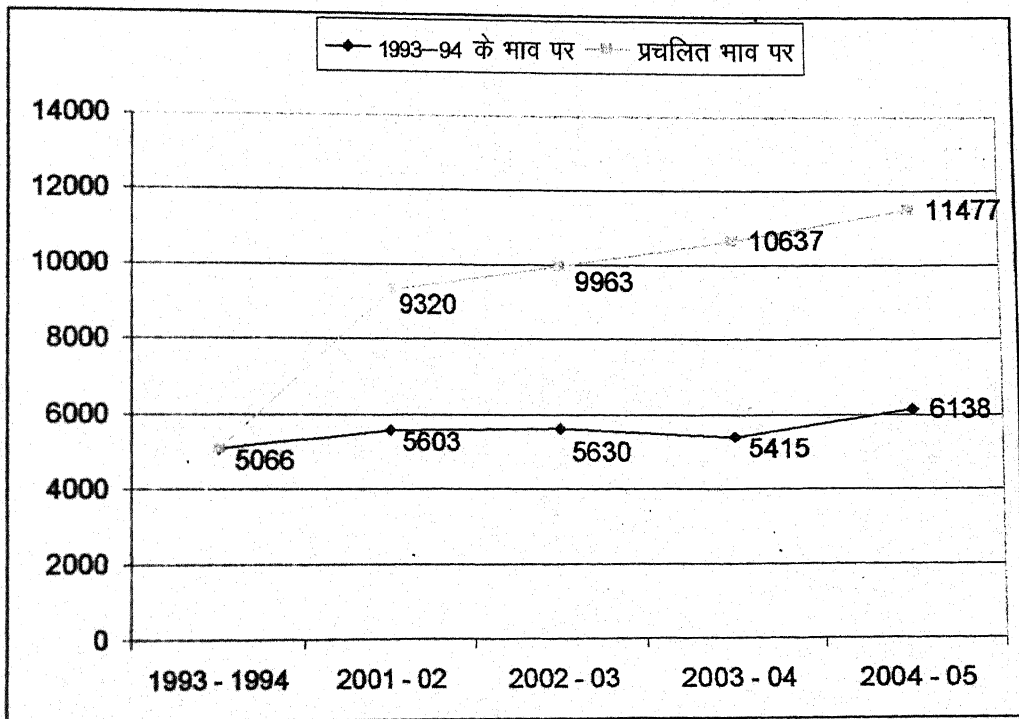
उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग
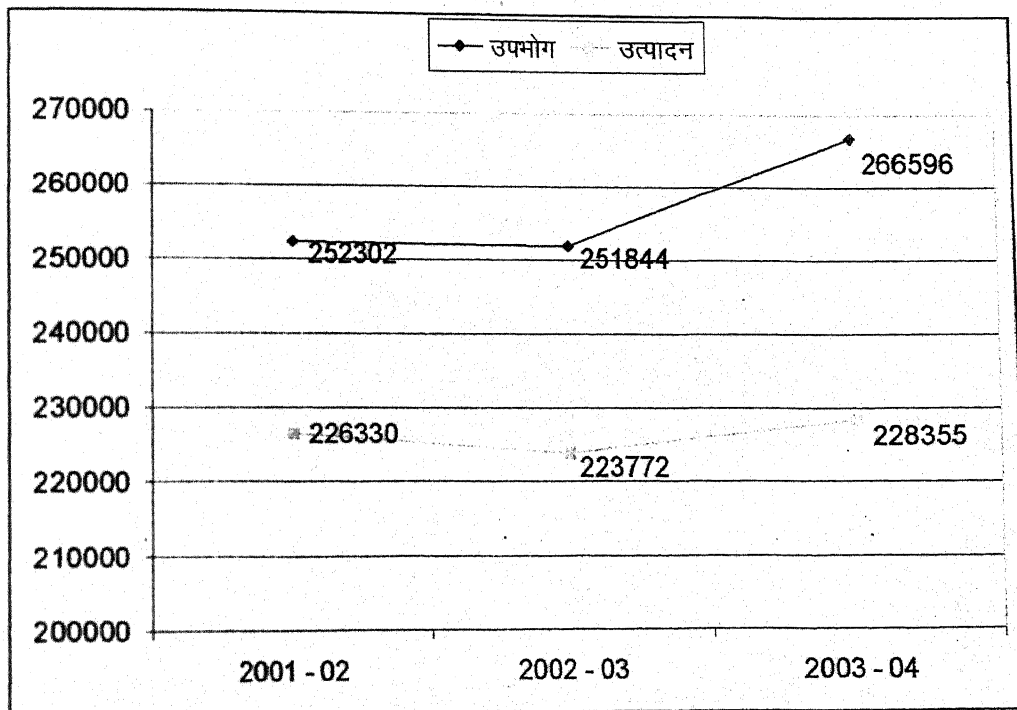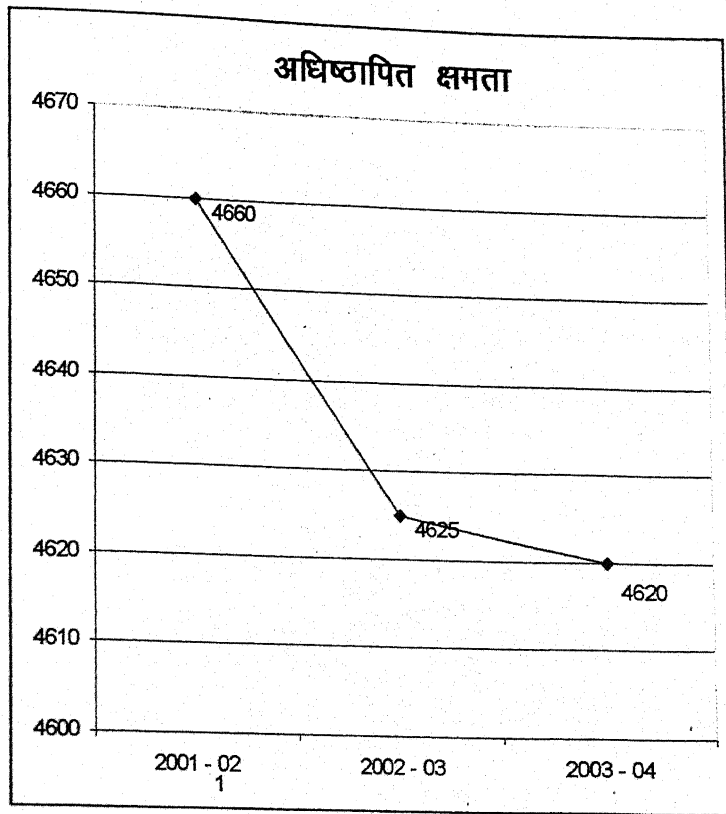
उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग
(हजार हेक्टेयर)

2002 – 03

उत्तर प्रदेश में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल
(हजार हेक्टेयर में)
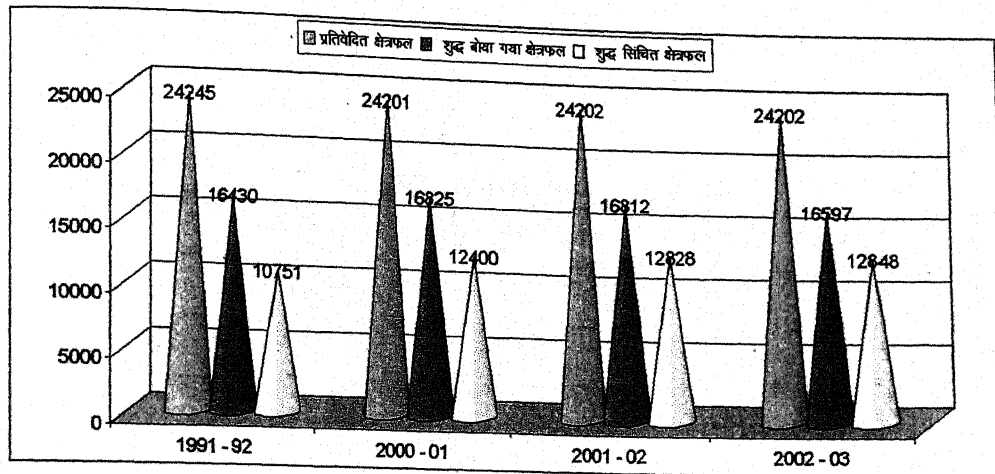
उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद का वितरण
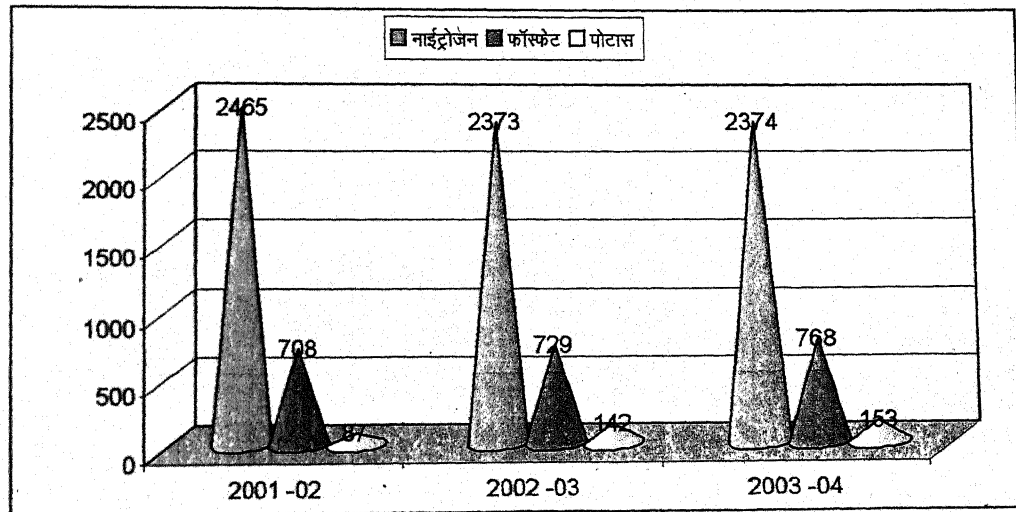
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोजगार की संख्या
(अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान की ओर से जारी आर्थिक गणना 2005 के अनुसार)
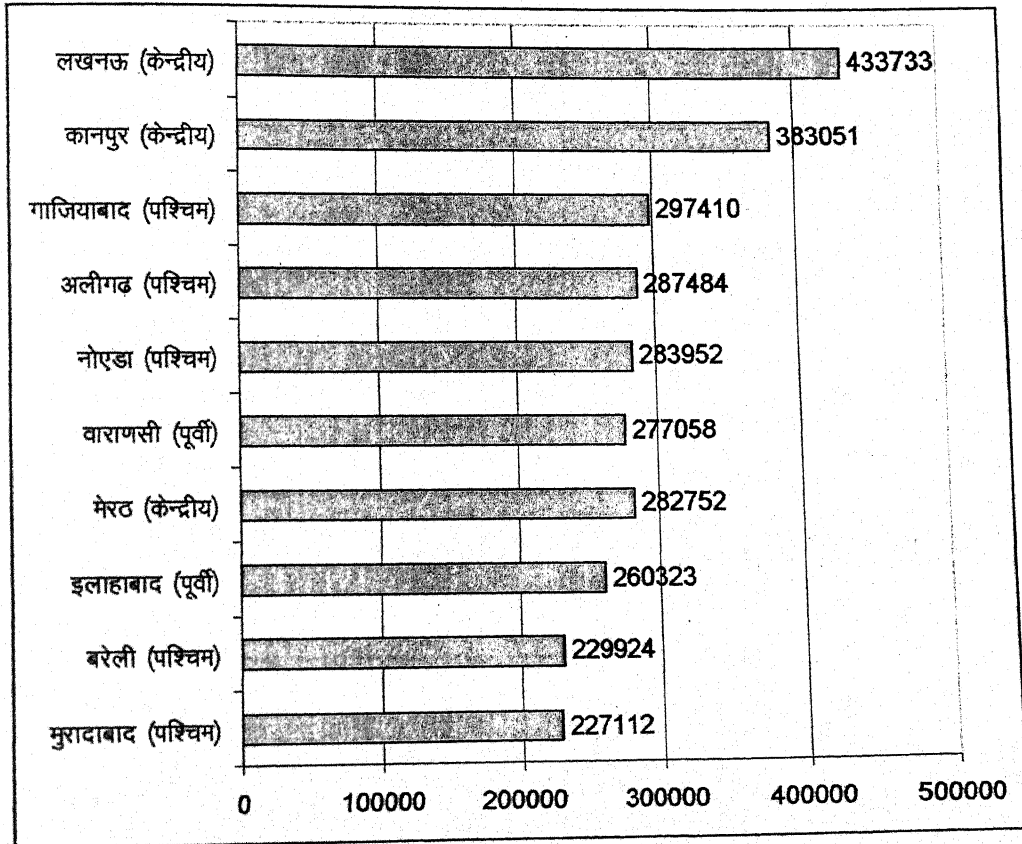
उत्तर प्रदेश में थोक भाव सूचकांक
(1970 – 71 = 100)
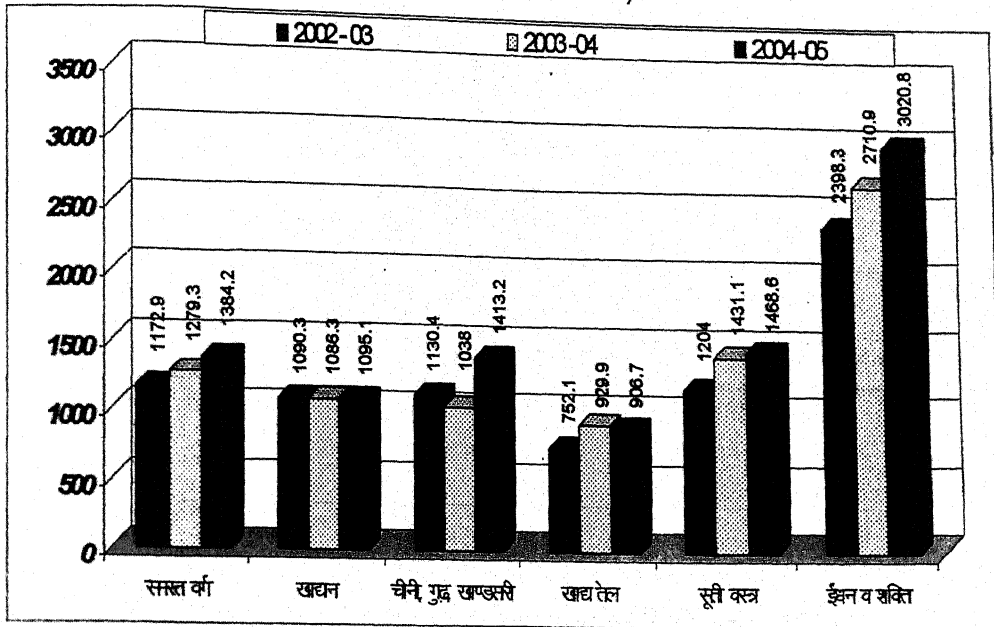
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
(1993 – 94 = 100)
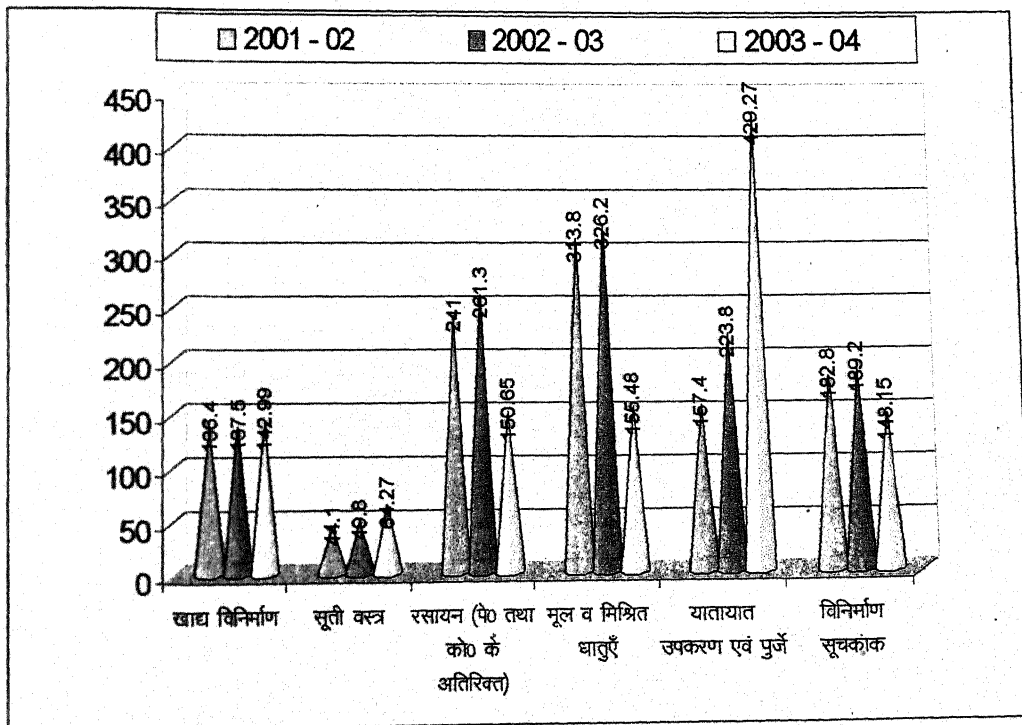
औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत वितरण
(प्रचलित भावों पर)
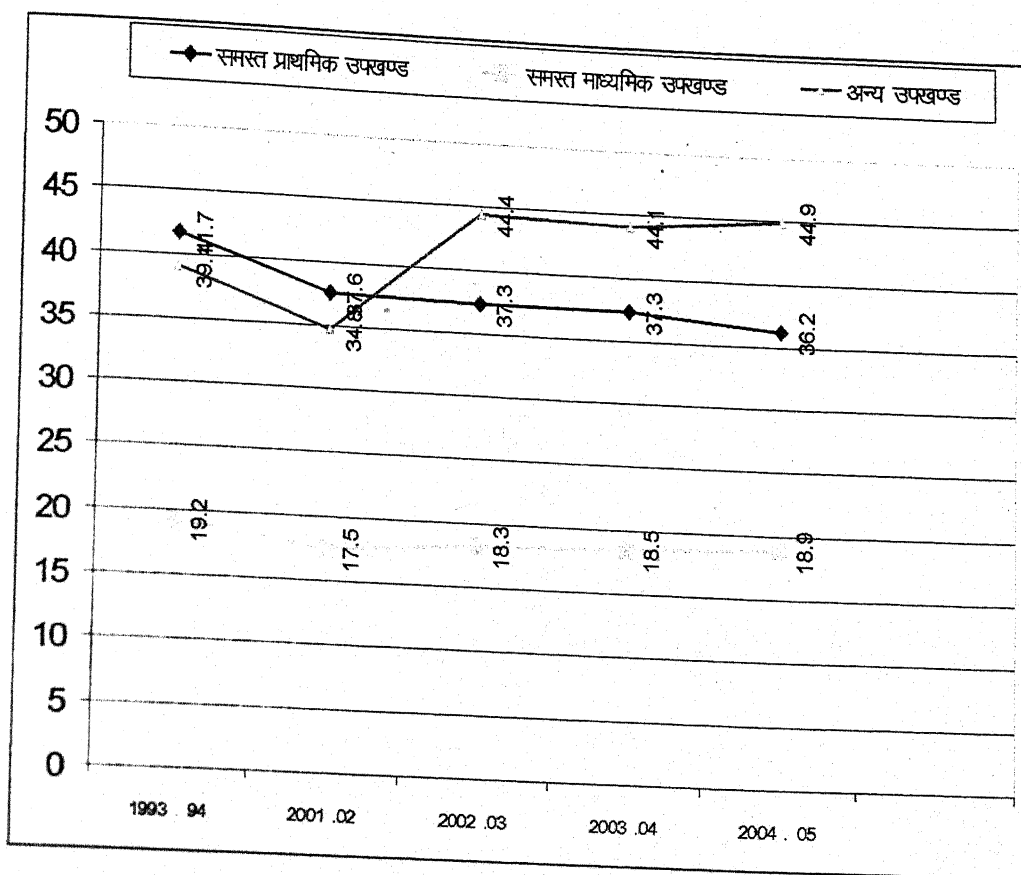
प्रश्नावली

शोध के मध्य निम्नलिखित प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएँ एकत्र की गईं :–

(i) कृषकों से पूंछे गये प्रश्न –

नाम – . . . . क्षेत्र : पूर्वी / पश्चिमी

पता –

जोत का आकार – सीमान्त ☐ लघु ☐ दीर्घ ☐

प्रश्न 1 – कुछ वर्षों पहले की तुलना में कृषि आय में –

वृद्धि हुई ☐ कमी हुई ☐ समान है ☐

प्रश्न 2 – कृषि में भविष्य

सुरक्षित है। ☐ असुरक्षित है ☐

प्रश्न 3 – सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाएँ –

लेते हैं ☐ नहीं लेते ☐

क्या कारण है : ....

प्रश्न 4 – कृषि में निजी कम्पनियों के निवेश के कारण –

लाभ होगा ☐ नुकसान होगा ☐ कह नहीं सकते ☐

प्रश्न 5 – पारिवारिक दायित्व एवं बच्चों की शिक्षा में कुछ वर्ष पहले की तुलना में–

अधिक सक्षम है ☐ कम सक्षम है ☐ समान है ☐

(ii) उद्यमियों से पूछे गये प्रश्न :–

नाम – क्षेत्र : पूर्वी / पश्चिमी

संस्था –

आकार – छोटी ☐ मध्य ☐ बड़ी ☐

प्रश्न 1 – 10 वर्ष पहले की तुलना में उद्योग में लाभ –

बढ़ गया है ☐ घट गया है ☐ समान है ☐

प्रश्न 2 – नया उद्योग प्रारम्भ करना –

आसान हुआ ☐ कठिन हुआ ☐ रिस्क बढ़ा है ☐

प्रश्न 3 – बहुराष्ट्रीय कम्पनियां –

प्रतिद्वंदी हैं ☐ सहयोगी हैं ☐

प्रश्न 4 – उत्पादन की तुलनां में श्रम की मात्रा

बड़ी है ☐ घटी है ☐ समान है ☐

प्रश्न 5 – विशेष आर्थिक क्षेत्र "सेज" में उद्यम लगाने के लिए –

उत्सुक हैं ☐ इच्छुक नहीं ☐ उदासीन ☐

(iii) मजदूरों से पूंछे गये प्रश्न –

नाम – क्षेत्र : पूर्वी / पश्चिमी

पता –

प्रश्न 1 – मजदूरी मिलना –

आसान हुआ ☐ मुश्किल हुआ ☐

प्रश्न 2 – आय तथा सुविधाये –

बढ़ गयी ☐ घट गयी ☐ समान है ☐

(iv) व्यापारियों से पूंछे गये प्रश्न –

प्रश्न 1 – व्यापार से आमदानी 5 वर्ष पूर्व की तुलना में –

बड़ी है ☐ घटी है ☐ समान है ☐

प्रश्न 2 – सुख सुविधाओं में –

वृद्धि हुई ☐ कमी हुई ☐

प्रश्न 3 – भविष्य के प्रति –

निराश है ☐ आशान्वित ☐

प्रश्न 4 – नया व्यापार प्रारम्भ करना –

सरल हुआ ☐ मुश्किल हुआ ☐

(v) गृहणियों से पूंछे गये प्रश्न –

नाम –

क्षेत्र : पूर्वी / पश्चिमी

पता –

प्रश्न 1 – बचत –

बढ़ गयी ☐ घट गयी ☐ समान है ☐

प्रश्न 2 – उत्पादों के विज्ञापन –

लाभकारी हैं ☐ परेशानी है ☐ कोई प्रभाव नहीं ☐

प्रश्न 3 – सपने पूरे करना (मकान, गाड़ी इत्यादि के)

आसान है ☐ मुश्किल है ☐

(vi) छात्रों से पूंछे गये प्रश्न :–

प्रश्न 1 – नई नीतियों से रोजगार के अवसर –

बढ़े हैं ☐ घटे हैं ☐ समान हैं ☐

प्रश्न 2 – क्या पेशा अपनाऐंगे –

नौकरी ☐ स्व व्यवसाय ☐ उद्यम ☐

प्रश्न 3 – किस चीज को वरीयता देते हैं –

पैसा ☐ पेशे की सुरक्षा ☐ रूतवा व सम्मान ☐

प्रश्न 4 – भविष्य की सम्भावना –

उज्जवल हैं ☐ परेशानी बढ़ जायेगी ☐

उदार आर्थिक नीतियों पर राय – ....

अध्याय अष्ठम्
संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 –आर्थिक विषमतायें – अमर्त्य सेन – राजपाल प्रकाशन, दिल्ली (अनुवाद भवानी शंकर बागला)

2 - Developmetn Economics - K. Murtinathan Naidu contributions of Pro. V.K. R.V. Rao - Reliance Publication, Delhi

3 – भारत की अर्थनीति (21वीं सदी की ओर), विमल जालान – राजकमल, दिल्ली

4 – इकॉनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया : एनालिसिस, एक्सपीरिएंस एण्ड लेसंस – दीपक नैयर

5 – भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त एवं सुन्दरम् – एस. चन्द्र प्र. लि.

6 – दैनिक जागरण – झांसी प्रकाशन – अप्रेल 2006 से 2007

7 – अमर उजाला – झांसी प्रकाशन – अप्रेल 2006 से 2007

8 – उपकार अर्थशास्त्र (NET, SELET) - डॉ. अनुपम अग्रवाल

9 – प्रतियोगिता दर्पण – मई 2006, जून 1992, मई 1994

10 - The roll of small enterprises in Indian economic development - Dhar and Lydall

11 - Report of the village and small scale industries commitee (1955)

12 – आर्थिक विचारों का इतिहास – साहित्य भवन प्रकाशन – चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी

13 – सिविल सर्विसेज – टाईम्स विशेष संस्करण – 2006

14 – एम.एल. झिंगन – मुद्रा बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

15 - A.c. Pigou - Socialism versus capitalism.

16 - J.M. Keynes - The end of Laissez fair

17 – गरीबी और अकाल – अमर्त्य सेन – राजपाल प्रकाशन

18 - From plan to market - World Development Report 1996

19 – उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक,

20 – प्रकाशक – अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उ.प्र.)

21 – सांख्यिकी – डॉ. बी.एन. गुप्ता

22 - Business Economics - Dr. N.K. Sharma Book Links Services, Jaipur

23 - Arthur Lewis - Tata Memorial Lecture Bombay 1973